राष्ट्रीय संस्करण

सीडीएस बोले, तकनीकी प्रगति से बदला युद्ध का स्वरूप, सशस्त्र बल रहें तैयार >>3

वर्ष 8 अंक 25

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8 .00 नई दिल्ली, शुक्रवार, 5 जुलाई, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

विश्व विजेताओं के स्वागत में उमड़ा जनसमुद्र

टी-20 विश्व कप जीतने के पांच दिन बाद स्वदेश लौटी भारतीय टीम

नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास में चैंपियन टीम से की मुलाकात

मुंबई में नरीमन प्वाइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक खुली बस में विजय परेड

नई दिल्ली, जेएनएन

ब्रिजटाउन में 29 जून को दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद टी-20 विश्व कप जीतकर 140 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा करने वाली रोहित शर्मा की अगुआई वाली भारतीय टीम अंततः गुरुवार को भारत लौट आई। दिल्ली के बाद मुंबई में विश्व विजेताओं को देखने जनसमुद्र उमड़ा। बारबाडोस में तूफान 'बेरिल' के कारण भारतीय टीम शनिवार से फंसी थी। गुरुवार सुबह छह बजे दिल्ली के आइजीआइ हवाई अड्डे पर विशेष विमान 'एयर इंडिया चैंपियंस 24 विश्व कप' उतरा, जिसमें विजेता टीम सवार थी। लगातार बूंदाबांदी और कड़ी सुरक्षा के बीच हवाई अड्डे पर प्रशंसकों ने खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद टीम होटल गई, जहां कप्तान रोहित व अन्य खिलाड़ियों ने भांगड़ा किया।

प्रधानमंत्री से मुलाकात : कुछ देर बाद टीम होटल से पीएम आवास पहुंची, जहां उन्होंने नाश्ते पर पीएम नरेन्द्र मोदी से भेंट की। बीसीसीआइ अध्यक्ष रोजर बिन्नी व सचिव जय शाह ने मोदी को 'नमो' लिखी विशेष जर्सी भेंट की। पीएम के साथ करीब दो घंटे बिताने के बाद टीम मुंबई के लिए रवाना हुई। टीम इंडिया की विस्तारा फ्लाइट को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते हुए 'वाटर सैल्यूट' दिया गया। हजारों रोमांचित मुंबईवासी विश्व विजेताओं की झलक पाने के लिए नरीमन प्वाइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक एक किलोमीटर के सुरम्य मरीन ड्राइव मार्ग पर जुटे थे। नरीमन प्वाइंट से लेकर चर्चगेट तक इलाका प्रशंसकों से खचाखच भरा हुआ था। नरीमन प्वाइंट से खुली बस में खिलाड़ी वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे, जहां पूरा स्टेडियम भीड़ के गगनभेदी नारों व जयकारों से गूंज उठा। वानखेड़े में बीसीसीआइ ने टीम को 125 करोड़ रुपये का चेक देकर सम्मानित किया।

(विशेष सामग्री : पेज-12 पर)

टी-20 विश्व कप जीतकर स्वदेश लौटी भारतीय क्रिकेट टीम ने गुरुवार को मुंबई में नरीमन प्वाइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक खुली बस में सवार होकर विजय परेड निकाली। टीम के स्वागत में विशाल जनसमुद्र उमड़ा। एएनआइ

विश्वास.News

धार्मिक ग्रंथों पर राहुल गांधी का प्रसारित बयान फर्जी?

विश्वास न्यूज की पड़ताल ● पेज-4

जागरण विशेष

कचरे के बदले दिया सोना, आकर्षित होने लगे पर्यटक

श्रीनगर : अनंतनाग का सैदीवारा कभी ट्रेकरों और सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र था। मगर कचरे के ढेर ने पर्यटकों को दूर कर दिया। ऐसे में तत्कालीन सरपंच ने कचरा लाओ सोना ले जाओ अभियान भी शुरू किया, जिससे पंचायत कचरा मुक्त हो गई है। (पेज-7)

संपादकीय

संसद के न चलने का खतरा : जनादेश का सुविधाजनक निहितार्थ दोनों पक्षों के बीच तकरार की वजह बनकर संसदीय गतिरोध को बढ़ाता दिख रहा है। **राहुल वर्मा** का आलेख।

अपेक्षाओं के अनुरूप आपराधिक कानून : न्याय प्रणाली की लेटलतीफी से जुड़ा 'तारीख पे तारीख' वाला जुमला अब इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। **आशुतोष पाण्डेय** का दृष्टिकोण। ● पेज 8

विमर्श

कम समय में अधिक वर्षा का बढ़ता पैटर्न : पिछले कुछ वर्षों से मानसून के दौरान कई जगहों पर वर्षा दिवसों में कमी तो कुछ जगहों पर इनकी संख्या अपेक्षा से बहुत अधिक हो गई है। कम समय में अत्यधिक वर्षा से जुड़ी चिंताओं को रेखांकित कर रहे हैं, **संजय श्रीवास्तव**।

यूरोपीय संसद चुनाव और भारत : यूरोपीय संसद के चुनाव परिणाम भारत-यूरोपीय संघ संबंधों के विविध पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं। **डा. शक्ति प्रसाद श्रीचंदन** का आलेख। ● पेज-9

दैनिक जागरण सप्तरंग

मनोरंजन की दुनिया का

पूर्वांचल की बोली में है मिठास

बतौर खलनायक शुरू होगा सफर : राघव जुआल

● पेज-13

छह सेवादार गिरफ्तार, फरार मुख्य आयोजक पर एक लाख का इनाम

हाथरस में सत्संग हादसा ▶ गिरफ्तार किए गए सेवादारों में दो महिलाएं शामिल

बाबा को हादसे में आरोपित नहीं मान रही पुलिस, दोषी पाए जाने पर जुड़ेगा नाम

- सेवादारों ने भीड़ को धक्का देने और घटना को दबाने के साथ साक्ष्य मिटाने का किया प्रयास
- कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज आएंगे हाथरस, मरने वालों के स्वजन व घायलों से मिलेंगे

200 से ज्यादा लोगों के मोबाइल नंबर रडार पर

20 से अधिक लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है

70 लोगों के बयान दर्ज किए हैं पुलिस के विशेष जांच दल ने

121 लोगों की जान चली गई है हाथरस हादसे में

जागरण संवाददाता, हाथरस

उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले में दो महिलाओं समेत छह सेवादारों को गिरफ्तार किया गया है। 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर फरार है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस अभी सूरजपाल उर्फ नारायण साकार विश्व हरि (भोले बाबा) को आरोपित नहीं मान रही है। करीब 200 मोबाइल नंबर पुलिस के रडार पर हैं। कुछ नंबरों पर घटना वाले दिन बाबा की बातें हुई थीं। भीड़ रोकने, धकेलने व साक्ष्य छुपाने का प्रयास करने वाले सेवादारों को चिह्नित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआइटी ने अब तक 70 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। उधर, हादसे में मरने वालों के स्वजन से मिलने व घायलों का हाल जानने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को अलीगढ़ और हाथरस आएंगे।

ज्ञात हो, फुलरई गांव में गत मंगलवार को करीब डेढ़ सौ बीघा जमीन में सत्संग का आयोजन किया गया था। सत्संग के बाद बाबा का काफिला जाने को हुआ तो उसके दर्शन करने व चरण रज लेने को भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई।

आइजी शलभ माथुर ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि सेवादार रामलड़ैते यादव, उपेंद्र सिंह यादव, मेघसिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी व मंजू यादव को गिरफ्तार किया है। आयोजन में ये लोग भीड़ व चंदा जुटाने में सहयोग करते हैं। बैरिकेडिंग, भीड़ नियंत्रण, श्रद्धालुओं के लिए पंडाल की व्यवस्थाएं, वाहनों की पार्किंग समेत सभी व्यवस्थाओं को संभालने का जिम्मा सेवादारों का ही रहता है। इस मामले में चौकी प्रभारी ब्रजेश पांडे ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर ने आयोजन समिति की ओर से तथ्य छिपाकर कार्यक्रम में 80 हजार की भीड़ की अनुमति मांगी, जबकि मौके पर ढाई लाख लोग पहुंचे। उधर, भारतीय हिंदू राष्ट्र सेना व भ्रष्टाचार विरोधी सेना के अध्यक्ष पं.केशव देव गौतम ने बाबा का गला काट कर चौराहे पर जूते मारने वाले को 11 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। केशव ने इंटरनेट मीडिया पर इसका संदेश प्रसारित किया।

काफिला निकलते ही अनियंत्रित छोड़ दी भीड़ पेज>>6

हाथरस में सत्संग हादसे के आरोपितों के बारे में जानकारी देते आइजी शलभ माथुर। जागरण

नहीं आने की अपील के बाद भी बागेश्वर धाम में हजारों उमड़े

छतरपुर : उप्र हाथरस हादसे को देखते हुए कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री के जन्मोत्सव में शामिल न होने की अपील के बावजूद गुरुवार को बागेश्वर धाम पर हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। गुरुवार को चार जुलाई को पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी के जन्म दिवस पर धाम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बढ़ती भीड़ के कारण प्रशासन की मशक्कत बढ़ गई। (पेज-6)

जयशंकर ने वांग यी से कहा, शांति के लिए सीमा का सम्मान जरूरी

- सकारात्मक माहौल में हुई अस्ताना में भारत व चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक
- पूर्वी लद्दाख में तनाव खत्म करने के लिए तेज होगी कूटनीतिक और सैन्य वार्ता
- जयशंकर बोले, परस्पर आदर, संवेदनशीलता और हितों का ख्याल रखना जरूरी

कजाखस्तान की राजधानी अस्ताना में गुरुवार को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर द्विपक्षीय वार्ता के अवसर पर चीनी समकक्ष वांग यी के साथ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत ने फिर चीन को दो टूक बता दिया है कि दोनों देशों के बीच स्थायी शांति के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) का सम्मान करना बहुत जरूरी है। अस्ताना (कजाखस्तान) में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बीच करीब एक घंटे बातचीत चली जो दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में सबसे लंबी कूटनीतिक वार्ता है। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की शिखर बैठक के दौरान अलग से हुई इस वार्ता के बाद दोनों देशों ने कहा,वे लद्दाख में सैन्य तैनाती खत्म करने व द्विपक्षीय संबंध सामान्य बनाने की राह की अड़चनों को दूर करने के लिए दोगुना प्रयास करेंगे। भारत में पीएम नरेन्द्र मोदी की अगुआई में तीसरी बार सरकार बनने के बाद चीन संग यह पहली उच्चस्तरीय वार्ता थी जिसके काफी सकारात्मक माहौल में होने की बात बताई गई है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अप्रैल-मई, 2020 में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद से ही तनाव की स्थिति है जिसका असर दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों पर भी पड़ा है।

वांग यी से भेंट के बाद जयशंकर ने 'एक्स' पर लिखा-'सीपीसी पोलित ब्यूरो के सदस्य व विदेश मंत्री वांग यी से भेंट हुई। सीमा विवाद से जुड़े लंबित मामलों को शीघ्रता से सुलझाने पर बात हुई। कूटनीतिक व सैन्य चैनलों से विवाद के हल के लिए कोशिशें दोगुनी करने पर सहमति बनी। सीमा पर शांति बहाली व एलएसी का सम्मान करना बहुत जरूरी है। परस्पर आदर, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हितों का ध्यान रखना हमारे द्विपक्षीय रिश्तों को तय करेंगे।'

विदेश मंत्रालय ने कहा, जल्द ही कूटनीतिक स्तर पर की जाएगी वार्ता पेज>>3

बिहार में लगातार पुल ढहने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

याचिका में सभी पुलों का उच्च स्तरीय स्ट्रक्चरल आडिट कराने की मांग

बिहार में एक के बाद एक ढह रहे पुलों (नये, पुराने व निर्माणाधीन) का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। नालंदा जिले के निवासी बृजेश सिंह ने कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर मांग की है कि बिहार सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह सभी पुलों का उच्च स्तरीय स्ट्रक्चरल आडिट कराए। जो पुल कमजोर हैं, उन्हें या तो गिराया जाए या ठीक कराया जाए। याचिका में पुलों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी कमेटी गठित करने की मांग भी की है। याची ने कहा, कमेटी का गठन कानून के जरिये या कार्यकारी आदेश से हो। कोर्ट से यह भी आग्रह किया गया है कि वह राज्य सरकार को निर्देश दे कि वह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तर्ज पर पुलों की रियल टाइम मानीटरिंग की नीति या तंत्र बनाए। याचिका में बिहार के अलावा एनएचएआइ के चेयरमैन को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

बिहार में इंजीनियरों-ठेकेदारों की कोताही से गिरे पुल और पुलिया पेज>>5

बंगाल में राज्यपाल की बिना अनुमति स्पीकर ने बुलाया विस का विशेष सत्र

अभूतपूर्व फैसला

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

डा सीवी आनंद बोस। फाइल

- कहा- असहाय नहीं है विधानसभा, सब कुछ राज्यपाल के हाथ में नहीं
- राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार, राजभवन के साथ टकराव और बढ़ने के आसार

बिमान बनर्जी। फाइल

बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के दो नवनिर्वाचित विधायकों सायंतिका बनर्जी व रेयात हुसैन सरकार के शपथ ग्रहण में देरी को लेकर राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस के साथ चल रहे टकराव के बीच विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) बिमान बनर्जी ने गुरुवार को अभूतपूर्व कदम उठाते हुए राज्यपाल की बिना अनुमति शुक्रवार से विस का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की। कहा,विधानसभा असहाय नहीं है और सब कुछ राज्यपाल के हाथ में नहीं है। नियम, कानून व संवैधानिक मानदंड है। स्पीकर विस सत्र बुला सकता है। यह उनका विशेषाधिकार है।

विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में स्पीकर ने कहा, विशेष सत्र शुक्रवार दोपहर दो बजे से शुरू होगा। उससे पहले सुबह 11 बजे से विस की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। स्पीकर ने गत सप्ताह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को पत्र लिखकर शपथ विवाद में दखल की मांग की थी। अध्यक्ष ने राज्यपाल पर इसे दंभ की लड़ाई बनाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह गतिरोध पैदा कर रहे हैं।

ज्ञात हो, बंगाल के इतिहास में यह पहला मौका है जब राज्यपाल की बिना अनुमति स्पीकर ने विस का विशेष सत्र बुलाया है। आमतौर पर सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल से मंजूरी ली जाती है। विस अध्यक्ष ने इशारे में दोनों विधायकों के शपथ लेने को लेकर भी बड़ा फैसला लेने के संकेत दिए। स्पीकर के कदम से राज्य में सियासी सरगर्मियां बढ़ने के साथ राजभवन के साथ टकराव और बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं।

राज्यपाल ने विधायकों के विस में दी शपथ की अनुमति : राज्यपाल ने तृणमूल के दो विधायकों को विस में शपथ लेने की अनुमति दे दी है। उन्होंने दोनों विधायकों को शपथ दिलाने के लिए विस अध्यक्ष के बजाय उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) आशीष बनर्जी को नामित किया है। इसे लेकर फिर जटिलता पैदा हो गई है। हालांकि राजभवन ने इस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी है।

स्याह तस्वीर

राजधानी समेत देश के दस शहरों में पीएम 2.5 का स्तर चिंता बढ़ाने वाला

दिल्ली में वायु प्रदूषण से सालाना जाती है 12 हजार लोगों की जान

राज्य ब्यूरो, जागरण. नई दिल्ली

देश में वायु प्रदूषण की समस्या इस कदर भयावह हो गई है कि इसकी वजह से मृत्यु दर में वृद्धि होने लगी है। लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ जर्नल मे प्रकाशित एक अध्ययन ने स्याह तस्वीर पेश की है। इसके अनुसार दिल्ली सहित देश के 10 शहरों में प्रतिवर्ष हवा में पीएम-2.5 के कणों की अधिकता के कारण लगभग 33,000 लोगों की मौत हो रही है। इसमें सिर्फ दिल्ली में ही 12 हजार लोगों की जान जा रही है, जो प्रतिवर्ष होने वाली कुल मौत का 11.5 प्रतिशत है। राजधानी में 100 में से 12 लोगों की मौत खराब हवा के कारण होती है। वाराणसी में वायु प्रदूषण से होने वाली मौत 10 प्रतिशत से अधिक है।

भारत के स्वच्छ वायु मानदंड विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के 15 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के मानक से चार गुना अधिक है। यही कारण है कि वायु प्रदूषण के लिहाज से बेहतर माने जाने वाले शहरों में भी लोगों की जान जा रही है। कुछ माह पहले एक रिपोर्ट में दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया था।

अदालत से लेकर संसद तक चिंता जताने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं है। माना जाता है कि मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में हवा अपेक्षाकृत साफ रहती है, परंतु इन शहरों में भी प्रदूषण से मरने वालों की संख्या अधिक है। इसका कारण हवा में पीएम 2.5 का स्तर डब्ल्यूएचओ के मानक से अधिक होना है।

पीएम-2.5 के कणों में 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की वृद्धि होने पर प्रतिदिन मरने वालों की संख्या 1.4 प्रतिशत अधिक हो जाती है। वायु प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों के प्रभाव को अलग-अलग करने वाले तकनीक का उपयोग करने पर यह लगभग दोगुना 3.57 प्रतिशत हो गया। पीएम-2.5 का प्रमुख स्रोत वाहनों का ईंधन जलने से निकलने वाला धुआं और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं होता है। अध्ययन में कहा गया है कि भारत को अपने स्वच्छ वायु मानदंडों को कम से कम डब्ल्यूएचओ के दिशा-निर्देश के अनुरूप कम करना चाहिए, जिससे कि नागरिकों को प्रदूषित हवा के खतरों से बचाया जा सके।

अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि वायु प्रदूषण को कम करना एक राष्ट्रव्यापी चुनौती है। कम प्रदूषित माने जाने वाले शहरों में भी वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु दर पर काफी प्रभाव पड़ता है। पूरे वर्ष राष्ट्रव्यापी कड़े अभियान की आवश्यकता है।

- डा. भार्गव कृष्णा, अध्ययन के प्रमुख लेखक एवं सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव में फेलो

शहर	पीएम 2.5 के कणों से मौतें	मौत का प्रतिशत
दिल्ली	12,000	11.5
वाराणसी	830	10.2
कोलकाता	4,700	7.3
पुणे	1,400	5.9
अहमदाबाद	2,500	5.6
हैदराबाद	1,600	5.6
मुंबई	5,100	5.6
चेन्नई	2,900	4.9
बेंगलुरु	2,100	4.8
शिमला	59	3.7

वर्ष 2008 से 2019 के बीच मृत्यु दर के आंकड़ों का किया गया अध्ययन पेज>>6

हेमंत फिर बने झारखंड के सीएम

- जेल से रिहाई के बाद झामुमो नेता ने 13वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली
- जमीन घोटाले में गिरफ्तारी से पहले छोड़ दिया था मुख्यमंत्री पद

« रांची में गुरुवार को झारखंड के सीएम के रूप में शपथ लेने के बाद पत्नी कल्पना के साथ बजरंग बली की पूजा-अर्चना करते हेमंत सोरेन। प्रेट्र

राज्य ब्यूरो, जागरण ● रांची

झारखंड में फिर हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है। उन्होंने गुरुवार को राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राजभवन के दरबार हाल में आयोजित समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। ज्ञात हो, झारखंड में तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बुधवार को ही चम्पाई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। साथ ही हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने के लिए 44 विधायकों के हस्ताक्षर युक्त समर्थन पत्र सौंपा था।

तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने से पूर्व हेमंत ने कहा, वह विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे और गांव-गांव तक सरकारी योजनाओं का लाभ फिर से पहुंचाएंगे। झारखंडियों का हक उनके दरवाजे पर पहुंचाएंगे। राजभवन रवाना होने के पूर्व एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, मुझे बेवजह झूठे आरोप में फंसाकर पांच माह जेल में रखा गया। कानूनी जंग में लोगों का सहयोग मिला और कोर्ट ने बरी किया। अतः फिर लोगों के बीच हूं।

विशेष सत्र आठ को, विश्वास मत हासिल करेंगे हेमंत पेज>>4

****

120 निजी अस्पतालों और नर्सिंगहोमों का दूसरे चरण में निरीक्षण करेगी एसीबी। पहले चरण में मई में अभियान चला 62 निजी अस्पतालों व नर्सिंगहोमों का निरीक्षण किया था।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 5 जुलाई, 2024

आज का मौसम

सामान्यतया बादल छाए रहेंगे। बिजली चमकने एवं हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने के आसार हैं।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
5 जुलाई	33.0	26.0
6 जुलाई	34.0	27.0
नोएडा		
5 जुलाई	32.0	26.0
6 जुलाई	33.0	26.0
गुरुग्राम		
5 जुलाई	30.0	26.0
6 जुलाई	31.0	25.0

डिग्री सेल्सियस में

सात वर्ष बाद हुआ शिक्षकों का तबादला

नई नीति ▶ राजधानी में 5,006 शिक्षकों के दो जुलाई की रात किए गए थे तबादले

11 जून को दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने नई तबादला नीति जारी की

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सात साल बाद तबादला नीति में परिवर्तन के बाद करीब पांच हजार शिक्षकों के स्थानांतरण पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने नौकरशाही पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने नियमों को आधार मानते हुए दो जुलाई को रात में 5,006 शिक्षकों तबादला कर दिया। 11 जून को शिक्षा निदेशालय ने नए आदेश जारी किए थे और इसके तहत 10 साल से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों के तबादला करने की नई नीति जारी की थी।

10 साल से अधिक समय तक एक ही स्कूल में अध्यापन का कार्य कर रहे शिक्षकों को आनलाइन आवेदन करने के लिए कहा गया था। शिक्षा मंत्री आतिशी के आश्वासन और निदेशालय को तबादला नीति वापस लेने के संबंध में पत्र लिखे जाने पर किसी शिक्षक ने आवेदन नहीं किया। इसके बाद निदेशालय ने ये तबादले अपने हिसाब से कर दिए। आतिशी और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी इसे गैरजरूरी बता रहे हैं। इस पर शिक्षा निदेशालय चुप है।

शिक्षा निदेशालय का बड़ा फैसला। फाइल फोटो

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या

जानकारों के मुताबिक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के मुताबिक शिक्षकों के लिए बार- बार या बड़े स्तर पर तबादले की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्थानांतरण एक आनलाइन साफ्टवेयर अधारित व्यवस्था के माध्यम से किए जाएंगे।

वर्ष 2017 की तबादला नीति के अनुसार, परस्पर तबादले पूरे वर्ष होते थे। एक प्रधानाध्यापक वर्ष में तीन शिक्षकों का तबादला कर सकता था। इस प्रक्रिया के तहत स्कूलों में तबादले होते रहते थे। 2019 से प्रधानाध्यापक को वर्ष में तीन की जगह दो तबादले करने का अधिकार दिया गया। अब 11 जून, 2024 को शिक्षा निदेशालय ने नया आदेश जारी किया और प्रधानाध्यापकों से तबादले का अधिकार वापस ले लिया। नई नीति के खंड 16 में वर्णित किया गया कि सभी शिक्षक जिन्होंने एक ही स्कूल में लगातार 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से अधिकतम संख्या में स्कूलों का चयन करते हुए पारस्परिक या सामान्य आधार पर स्थानांतरण के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। ऐसे शिक्षक जो आनलाइन आवेदन नहीं करेंगे, मुख्यालय स्वयं उन्हें आधिकारिक आवश्यकता के अनुसार किसी भी स्कूल में स्थानांतरित कर देगा। शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक जुलाई को इस कार्रवाई को रद करने और आदेश वापस लेने के लिए शिक्षा सचिव को पत्र लिखा था। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि उनकी अनुमति के बिना ही शिक्षा विभाग ने तबादला संबंधी आदेश जारी किया था। उन्होंने शिक्षा सचिव को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि उनकी अनुमति के बिना इस तरह के कोई निर्णय न लिए जाएं। लेकिन, दो जुलाई की रात को 1,009 विविध शिक्षक, 847 पीजीटी और 3,150 टीजीटी, कुल 5006 शिक्षकों का तबादला कर दिया।

शिकायत निवारण के लिए समिति बनाने पर बनी सहमतिः शिक्षक संघ : राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव अजय वीर यादव के नेतृत्व में गुरुवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा निदेशक आरएन शर्मा से मुलाकात की। यादव ने बताया कि तबादले के मामले को लेकर शिक्षा निदेशक से शिकायत निवारण समिति गठित करने पर सहमति बनी है।

शिक्षा मंत्री ने मुख्य सचिव को दिए कड़े निर्देश

शिक्षा मंत्री आतिशी ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के मुख्य सचिव को कड़े शब्दों में दिल्ली सरकार के एक स्कूल में 10 साल से ज़्यादा समय से पढ़ा रहे शिक्षकों के अनिवार्य तबादला आदेश पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि पूरी तबादला प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की जांच भी हो और यदि कोई भी अधिकारी शिक्षकों से रिश्वत लेने में शामिल है तो उसपर सख्त कारवाई हो। उन्होंने कहा कि यह आदेश शिक्षा विरोधी है और इस आदेश को खारिज करने के लिए मैंने एक जुलाई को दिल्ली के शिक्षा सचिव और शिक्षा विभाग के निदेशक को निर्देश दिए थे। मेरे आदेश के बावजूद दो जुलाई को देर रात 5,006 शिक्षकों के तबादले का आदेश निकाल दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि, शिक्षा मंत्री के आदेश के बावजूद, शिक्षा प्रणाली पर इससे पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के बावजूद दिल्ली सरकार के अधिकारी ऐसा आदेश क्यों निकाल रहे हैं? जबकि ऐसे तबादलों के पक्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नहीं है।

श्रीनगर हो या मुंबई...सभी दिशाओं की उड़ानों में देरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ **करीब 125 उड़ानों के प्रस्थान में विलंब**

प्रतीकात्मक

पिछले कई दिनों से उड़ानों में लेटलतीफी का जो सिलसिला चल रहा है, वह बृहस्पतिवार को भी बदस्तूर जारी रहा। हालांकि रद उड़ानों की संख्या पहले के मुकाबले काफी कम हुई है, लेकिन विलंबित उड़ानों की संख्या पहले की तरह तीन अंकों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। लेटलतीफी का आलम यह रहा कि मुंबई, गोवा, गुवाहाटी जाने वाली स्पाइसजेट की उड़ानें नौ घंटे विलंब से रवाना हुईं। कुल आठ उड़ानों को रद करना पड़ा।

पूरब, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण चारों दिशाओं को जाने वाली उड़ानें विलंबन के चक्र में फंसी हैं। उत्तर भारत की बात करें तो लेह की उड़ान सात घंटे व श्रीनगर की उड़ान पांच घंटे विलंब से रवाना हुई। दक्षिण भारत की बात करें तो विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोचीन, त्रिवेंद्रम को जाने वाली उड़ान विलंब से रवाना हुई। पश्चिम दिशा को जाने वाली उड़ानों में मुंबई की अधिकांश उड़ानों में विलंब हुआ। पूर्व दिशा में जाने वाली उड़ानों में पटना, बागड़ोगरा व अन्य स्थानों की उड़ानों में विलंब हुआ।

आखिर विलंब की क्या है वजह : अधिकांश विलंबित उड़ानें ऐसी हैं जिसमें विमान के प्रस्थान का मूल स्थान नई दिल्ली न होकर कोई और जगह है। जब विमान दिल्ली विलंब से पहुंचता है तो यहां से प्रस्थान में विलंब का होना स्वभाविक है। डायल से इस संबंध में कुछ पूछा जाता है तो उनका उत्तर होता है कि इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। दूसरी ओर एयरलाइंस से बात करें तो वे आपरेशनल कारणों को विलंब के उत्तरदायी ठहराते हैं।

अब टर्मिनल बदलने की कही जा रही बात : टर्मिनल 1 के पूरी तरह बंद होने के कारण फिलहाल टर्मिनल 2 व 3 से उड़ानें संचालित हो रही हैं। एयरपोर्ट सूत्रों का कहना है कि टर्मिनल 2 के आकार को देखते हुए कुछ उड़ानों को टर्मिनल 3 पर संचालित करने की दिशा में सोचा जा रहा है। कहा जा रहा है कि टर्मिनल 2 से संचालित होने वाली इंडिगो की कुछ उड़ानों को टर्मिनल 3 पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इससे टर्मिनल दो की क्षमता के हिसाब से अभी तो अतिरिक्त भार है, उसे कम करने की कोशिश की जाएगी।

न्यूज गैलरी

लालकृष्ण आडवाणी को मिली अस्पताल से छुट्टी

नई दिल्ली : वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आडवाणी की तबीयत खराब होने पर बुधवार देर शाम अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें न्यूरो से संबंधित परेशानी थी। न्यूरोलाजी के विशेषज्ञ डा. विनीत सूरी की देखरेख में उनका उपचार किया गया। 26 जून को भी उन्हें यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने पर एम्स में भर्ती किया गया था। (राब्यू, जागरण)

कम पानी के बाद अब यमुना में अमोनिया की समस्या

नई दिल्ली: वर्षा के बाद यमुना में कम पानी की समस्या दूर हुई है। पेयजल आपूर्ति की स्थिति सुधरी रही थी, परंतु अब नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से समस्या शुरू हो गई है। इससे सबसे अधिक प्रभावित वजीराबाद जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) हुआ है। मंगलवार की तुलना में बुधवार को इस संयंत्र से 43 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) कम पेयजल मिला। चंद्रावल डब्ल्यूटीपी भी प्रभावित हुआ है। (राब्यू, जागरण)

सुनवाई से न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने खुद को किया अलग

नई दिल्ली: फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अमित शर्मा ने खुद को अलग कर लिया है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि मामलों को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए जिसके सदस्य न्यायमूर्ति शर्मा नहीं हैं। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अधीन होगा। दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत की मांग को लेकर याचिका दाखिल करने वालों में जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम, मीरान हैदर समेत अन्य शामिल हैं। (जासं)

अनधिकृत निर्माण में अदालत का मोहरे के रूप में इस्तेमाल : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ **कहा, कार्रवाई करें तो अधिकारी मालिक से उगाही करते हैं, न करें तो बना रहता है अनधिकृत निर्माण**

दिल्ली में बाढ़ के कारण पर अहम टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अवैध और अनधिकृत निर्माणों के मामले में अदालतों को मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) आयुक्त को फटकार लगाते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दिल्ली में बाढ़ का एक कारण यह है कि अनधिकृत निर्माण के कारण पानी के रास्ते बंद हो गए हैं। इसका कारण अनधिकृत निर्माण है। घरों और इमारतों का निर्माण सार्वजनिक भूमि और नालों पर किया गया है, इसलिए पानी के बहाव के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अदालत ने देखा है कि कुछ वकील अनधिकृत निर्माण मामलों में भी ब्लैकमेल कर पैसे वसूल रहे हैं और अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। अदालत ने एमसीडी आयुक्त से कहा कि अदालत को पूरे मामले में मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इस नेक्सस को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि व्यवस्था चरमरा रही है। पीठ ने कहा कि एमसीडी आयुक्त कुछ करें और इसके लिए जिम्मेदार अपने अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। अदालत के पूर्व निर्देश पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग से मौजूद एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार को पीठ ने प्रेरित याचिकाएं दायर करने के बारे में अवगत कराया।

दिल्ली हाई कोर्ट। फाइल

एक दिन पहले ही विधि की परीक्षा रद, छात्र व शिक्षकों में रोष

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ **कम उपस्थिति के चलते छात्रों के परीक्षाओं से वंचित रहने पर डीयू ने लिया फैसला**

डीयू में विधि की परीक्षाएं बुधवार को एक दिन पहले ही रद कर दी गईं। डीयू प्रशासन ने कहा है कि कम उपस्थिति के चलते कई छात्र परीक्षा से वंचित हो गए थे। उन्हें दो हफ्ते की रेमेडियल कक्षाएं दी जा रही हैं, जिससे उनकी उपस्थिति परीक्षा देने लायक हो सके। डीयू के फैसले पर छात्र व शिक्षकों ने हैरानी जताई है। उन्होंने कहा है कि हर बार छात्र परीक्षा से वंचित होते हैं और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे एलएलएम में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सर्वाधिक परेशानी हो रही है, हालांकि परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा कर दी गई है।

डीयू में विधि कोर्स में दूसरे, चौथे और छठवें सेमेस्टर की परीक्षाएं चार जुलाई को प्रस्तावित थीं, लेकिन एक दिन पहले ही तीन जुलाई को इन्हें स्थगित कर दिया गया। विधि विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. अंजू वली टिक्कू ने कहा है कि कुलपति के आदेश के बाद विधि की सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं। डीयू के फैसले पर एक छात्र ने कहा कि यह चौंकाने वाला फैसला है। हर सेमेस्टर में 200 से 300 छात्र ऐसे होते हैं, जिनकी उपस्थिति कम होती है और उनकी ईयर बैक लगती है। वे एक साल बाद परीक्षा देते हैं, लेकिन पहली बार रेमेडियल कक्षाओं की घोषणा की गई है और 250 छात्रों के लिए नौ हजार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। छात्र ने कहा कि एलएलएम में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को परेशानी होगी। कई छात्रों का विदेश के विश्वविद्यालयों में प्रवेश हुआ है। उन्होंने टिकट बुक किए थे। टिकट कैंसिल होंगे और विश्वविद्यालयों में प्रवेश में भी समस्या उत्पन्न होगी। छात्र ने कहा, इससे नई प्रथा जन्म लेगी और हर साल परीक्षा से वंचित रहने वाले छात्र रेमेडियल कक्षाओं की मांग करेंगे।

दिल्ली विश्वविद्यालय। फाइल

पीजी, बीटेक और पांच वर्षीय विधि कोर्स की कक्षाएं एक अगस्त से

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ **27 अक्टूबर से तीन नवंबर तक होंगे पहले व तीसरे सेमेस्टर के मिड सेमेस्टर ब्रेक**

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर (पीजी), बीटेक और पांच वर्षीय विधि कार्यक्रम के लिए नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 की एक अगस्त को शुरुआत की घोषणा की गई है। नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी करते हुए इन तीनों कार्यक्रमों की पहले और तीसरे सेमेस्टर की कक्षाएं एक अगस्त से शुरू होंगी। डीयू में पीजी के 82 कोर्स संचालित होते हैं। हालांकि, स्नातक को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिलहाल सीयूईटी स्नातक के परिणाम जारी नहीं किए गए हैं। डीयू ने स्नातक का सत्र भी एक अगस्त से शुरू करने की घोषणा की है।

पीजी, बीटेक और पांच वर्षीय विधि कार्यक्रम के लिए जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार पहले सेमेस्टर के साथ ही तीसरे सेमेस्टर की कक्षाओं की शुरुआत एक अगस्त से हो जाएगी। पहले व तीसरे सेमेस्टर के लिए मिड सेमेस्टर ब्रेक 27 अक्टूबर से तीन नवंबर तक होंगे। चार नवंबर से कक्षाओं की शुरुआत होगी। प्रायोगिक परीक्षाओं की शुरुआत 28 नवंबर से होगी, जबकि लिखित परीक्षाएं 10 दिसंबर से शुरू होंगी। शीतकालीन अवकाश 29 दिसंबर से एक जनवरी तक होंगे। शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार दूसरे व चौथे सत्र की शुरुआत दो जनवरी से होगी। मिड सेमेस्टर ब्रेक नौ मार्च से 16 मार्च 2025 तक होंगे। परीक्षाओं की तैयारी व प्रायोगिक परीक्षाओं की शुरुआत 30 अप्रैल 2025 से होगी। लिखित परीक्षाएं 13 मई से होंगी। एक जून 2025 से 20 जुलाई 2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेंगे। पीजी, बीटेक और विधि कार्यक्रम के लिए दाखिला प्रक्रिया अभी जारी है।

सीजेआइ को पत्र लिख सीएम की जमानत पर रोक लगाने पर जताई चिंता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली के कई वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री केजरीवाल की नियमित जमानत पर रोक लगाने पर चिंता व्यक्त की है। अधिवक्ताओं का यह भी कहना है कि जज ईडी और सीबीआइ मामलों में जमानतों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर रहे हैं और लंबी तारीखें दे रहे हैं। यह पत्र 150 से अधिक वकीलों द्वारा लिखा गया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट और जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले कई वकील चिंताओं और शिकायतों के साथ पहुंचे हैं। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश अपलोड होने से पहले ही ईडी की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाने पर सवाल उठाया।

पत्र में कहा गया है कि केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने वाले न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन को मामले की सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए था क्योंकि उनके सगे भाई ईडी के वकील हैं।

विधानसभा चुनाव में एक तिहाई सीटों पर खास फोकस करेगी प्रदेश कांग्रेस

संजीव गुप्ता • जागरण

▸ **मुस्लिम, निम्न मध्यवर्गीय और अनुसूचित जाति एवं जनजाति मतदाता बहुल सीटों पर लोस चुनाव में मिला अच्छा मत**

नई दिल्ली : लोकसभा में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली प्रदेश कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव के लिए अपने दम पर जाने तैयारी कर रही है। इसके तहत संगठन की मजबूती के साथ ही एक तिहाई सीटों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक रणनीति पर काम हो रहा है।

दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 25 से 26 सीट ऐसी हैं, जो मुस्लिम, निम्न मध्यवर्गीय और अनुसूचित जाति एवं जनजाति मतदाता बहुल हैं। लोकसभा चुनाव में भी इन सीटों पर कांग्रेस को अच्छा वोट मिला है। इन सीटों में मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, बाबरपुर, सीमापुरी, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, गोकलपुर, चांदनी चौक, मटिया महल और बल्लीमारान प्रमुख हैं। पार्टी यहां भी समय से काफी पूर्व उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है ताकि उन्हें क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यहां पर पार्टी की कुछ न कुछ गतिविधियां भी चलती रहेंगी। वैसे पार्टी अन्य सीटों के लिए भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है।

दूसरी तरफ संगठन की मजबूती के लिए पार्टी ने हाल ही में तीन अहम निर्णय लिए हैं। पहला सभी 280 ब्लाक और 14 जिलों में अब मासिक बैठक अनिवार्य होगी। ब्लाक में यह माह की दो तारीख जबकि जिले में पांच तारीख को की जाएगी। इससे दोनों स्तरों पर कार्यकर्ता एवं नेता सक्रिय भी रहेंगे। इसके अलावा हर जिले में तीन-तीन नेताओं को पर्यवेक्षक की भूमिका में उतारा गया है। एक युवा, एक वरिष्ठ और एक अति वरिष्ठ नेता को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जिससे युवा जोश, अनुभव और मार्गदर्शन का समावेश रहे। प्रदेश कांग्रेस के नेता जानते हैं कि उनका मुकाबला आप और भाजपा दोनों से है। भाजपा का जहां अपना कैडर वोट है वहीं आप का सारा वोट बैंक कांग्रेस वाला ही है। इसलिए कांग्रेस की रणनीति आप के प्रति खासतौर पर आक्रामक रहेगी। वे एक ओर आप सरकार की विफलता उजागर करेंगे वहीं शीला दीक्षित सरकार के 15 वर्ष लंबे कार्यकाल की उपलब्धियां भी जनता को याद दिलाएंगे।

कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अनेक रणनीतियों के साथ संगठन की मजबूती पर भी शिद्दत से काम किया जा रहा है। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पुरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर रहेगा।
– देवेंद्र यादव, अध्यक्ष, दिल्ली कांग्रेस

दिहाड़ी श्रमिकों से मिले राहुल गांधी ने की दीवार की चिनाई

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली

▸ **जीटीबी नगर के लेबर चौक पर श्रमिकों से मिले, समस्याएं जानीं**

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को दिहाड़ी श्रमिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानीं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुबह जीटीबी नगर पहुंचे और लेबर चौक पर दिहाड़ी श्रमिकों से मुलाकात की। इसके बाद मुखर्जी नगर के पास गोपालपुर गांव पहुंचे। वह एक निर्माणाधीन मकान में रुके और श्रमिकों व राज मिस्त्री से बात की। इसी दौरान उन्होंने श्रमिकों से फावड़ा लेकर सीमेंट-रेत का मिक्स्चर बनाया और दीवार की चिनाई भी की। राहुल गांधी ने श्रमिकों से स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के बारे में पूछा।

राहुल गांधी के जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के पास लेबर चौक पर पहुंचने की खबर फैलते ही भीड़ बढ़ गई। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने फुटपाथ पर बैठकर श्रमिकों से बात की और सवाल किए। उन्होंने कारपेंटर, पेंटर, राज मिस्त्री, श्रमिकों से अलग-अलग बात की। उनसे पूछा कि रोज काम मिलता है या नहीं। स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है या नहीं। आधा घंटा रुकने के बाद गोपालपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन मकान में महिला एवं पुरुष श्रमिकों से बात की। उनकी समस्याएं पूछीं। कराला नगर के जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज ने बताया कि राहुल गांधी गोपालपुर गांव में सचिन मावी के निर्माणाधीन मकान पर करीब आधा घंटा रुके थे।

नई दिल्ली में निर्माणाधीन मकान में श्रमिकों से मिलने के दौरान फावड़ा लेकर सीमेंट-रेत का मिक्चर बनाते राहुल गांधी। एएनआइ

चार महीने बाद की तारीख मिलने पर कोर्ट में कर दी तोड़फोड़

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : कड़कड़डूमा कोर्ट में केस की नई तारीख दिसंबर की मिलने पर आरोपित भड़क गया। उसने कोर्ट रूम में तोड़फोड़ शुरू कर दी। टेबल पलटने के साथ ही कंप्यूटर मानीटर व माइक तोड़ दिए। एक पुलिसकर्मी ने आरोपित को पकड़ा और फर्श बाजार थाना पुलिस को सौंप दिया। कोर्ट रीडर रजनी ए कुमार की शिकायत पर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी को डराने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा में प्राथमिकी की है। आरोपित की पहचान शास्त्री पार्क निवासी राकेश के रूप में हुई है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि न्यायाधीश अखिल मलिक मंगलवार को सुबह आधे दिन की छुट्टी पर थे। सुबह 11 बजे के आसपास उन्होंने सरकार बनाम राकेश के केस की आवाज लगाई। राकेश कोर्ट रूम में आ गया और अगले ही दिन की तारीख मांगने लगा। रजिस्टर के अनुसार रीडर ने उसे दिसंबर की तारीख दे दी। आरोपित आगबबूला हो गया और उसने कोर्ट में तोड़फोड़ शुरू कर दी। किसी तरह से उसे काबू किया गया।

ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो

अत्याधुनिक ड्रोन तकनीकों की मदद से भारत की आतंकवाद-रोधी और कानून प्रवर्तन क्षमताओं को आधुनिक बनाकर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर काबू पाना है लक्ष्य

25 से अधिक देशों ने किया ड्रोन का प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मजबूत आंतरिक सुरक्षा बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने और विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन और मानव रहित प्रणालियों की संभावनाओं के मद्देनजर प्रगति मैदान में दो दिवसीय ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया। नेक्सजेन द्वारा आयोजित ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो में यूके, यूएसए, इजराइल, पोलैंड, क्रोएशिया, यूएई, जर्मनी, कनाडा, सिंगापुर, ब्राजील, हांगकांग और ताइवान सहित 25 से अधिक देशों द्वारा बनाए गए नए तरीके से ड्रोन का प्रदर्शन किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो और ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का उद्देश्य अत्याधुनिक ड्रोन तकनीकों की मदद से भारत की आतंकवाद-रोधी और कानून प्रवर्तन क्षमताओं को आधुनिक बनाकर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर काबू पाना है। एक्सपो में अग्रणी ड्रोन निर्माताओं के समाधानों पर प्रकाश डाला जाएगा, जिसमें निगरानी और दीर्घकालिक क्षमताओं में प्रगति पर जोर दिया जाएगा। एबोकोड टेक्नोलाजीज का सर्वेक्षण और निगरानी ड्रोन हवाई मानचित्रण, वन्यजीव ट्रैकिंग और सुरक्षा निगरानी जैसे कई कार्य करने में सक्षम है, जो मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है और निर्णय लेने में मदद करता है। आप्टिमस अनमैन्ड सिस्टम्स का मारक पीएल 7.0 सीमलेस टैक्टिकल मैपिंग करने के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह हल्के वजन वाले मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरे के साथ आता है जो उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो कैप्चर करता है और 20 किलोमीटर तक लाइव फीड रिले करता है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले मारक पीएल 7.0 इन ड्रोन को रडार द्वारा पता लगाना मुश्किल है और इसलिए ये दुश्मन के इलाके में गहराई तक जा सकते हैं। यह पेलोड ड्राप रेडी है और वांछित स्थान पर तीन किलोग्राम तक का पेलोड डिलीवर कर सकता है। आइडियाफार्जटेक के नेत्रा वी4 प्रो की उड़ान का समय 90 मिनट है और इसकी रेंज 15 किमी तक है। इस ड्रोन को रक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और मानचित्रण में महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए तैयार किया गया है, जो जटिल मिशनों के लिए व्यापक समाधान प्रदान करता है।

फायर फाइटर ड्रोन एएफडी2 उन्नत सेंसर और थर्मल इमेजिंग तकनीक से लैस है। यह ड्रोन हाटस्पाट की तेजी से पहचान करता है और लक्षित बुझाने के उपाय करता है।

नई दिल्ली प्रगति मैदान में लगे ड्रोनएक्सपो में अत्याधुनिक तकनीक वाले प्रदर्शित राइफल की डमी के साथ फोटो खिंचवाते युवा। चंद्र प्रकाश मिश्र

दुर्गम इलाकों की निगरानी में सक्षम

ये ड्रोन उन्नत निगरानी, टोही और मानचित्रण क्षमताओं से लैस हैं, जो प्रभावी खतरे की पहचान और निष्प्रभावीकरण की अनुमति देते हैं। वे वास्तविक समय की खुफिया जानकारी प्रदान करने, दुर्गम इलाकों की निगरानी में सक्षम हैं।

नाबालिगों को शर्मसार करने की नहीं दी जा सकती है इजाजत : कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ **हाई कोर्ट ने नाबालिग के आपत्तिजनक वीडियो लीक करने के मामले में दोषी की सजा रखी बरकरार**

अपने मोबाइल फोन पर अपने नियोक्ता की नाबालिग बेटी के छिपकर आपत्तिजनक वीडियो रिकार्ड करने के लिए एक घरेलू नौकर को दी गई तीन साल की कैद की सजा को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में पीड़िता और उसके परिवार को शर्मिंदा करने के लिए कानूनी रणनीति को उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अदालत ने यह टिप्पणी आरोपित द्वारा ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को कई आधारों पर चुनौती देने वाली जमानत याचिका पर की।

याचिकाकर्ता का कहना था कि वीडियो पीड़िता के पिता द्वारा तैयार और पोस्ट किए गए थे क्योंकि वह वेतन नहीं देना चाहते थे। इस तर्क का असंवेदनशील और अकल्पनीय बताते हुए पीठ ने कहा कि अदालत को न केवल पीड़ित बच्चों बल्कि उनके परिवारों की भी गरिमा और अधिकारों को बरकरार रखना चाहिए। अदालत ने कहा कि अपराधी को पीड़िता और पीड़ित परिवार को शर्मिंदा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने माना कि रिकार्ड पर मौजूद सामग्री और गवाहों की गवाही ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि अपीलकर्ता ने पीड़िता के तीन आपत्तिजनक वीडियो बनाए थे। निचली अदालत ने उसे विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था।

****

21 सालाना बैठक भारत के प्रधानमंत्रियों और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच अभी तक हो चुकी है। भारत और रूस के बीच हर वर्ष शिखर सम्मेलन की व्यवस्था थी जो वर्ष 2022 व वर्ष 2023 में नहीं हो सकी थी।

'तकनीकी प्रगति से बदला युद्ध का स्वरूप, सशस्त्र बल रहें तैयार'

बोले सीडीएस ▶ महाशक्ति बनने को नई ऊर्जा के साथ काम करें

- कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर कब्जा करने के 25 वर्ष पूरे होने पर सैन्य अधिकारियों को किया संबोधित
- खेलों के विपरीत युद्ध में कोई उपविजेता नहीं होता क्योंकि विजेता सब कुछ जीत लेता है

कारगिल युद्ध के दौरान तोलोलिंग एवं टाइगर हिल की लड़ाई के 25 वर्ष पूरे होने पर गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सीडीएस जनरल अनिल चौहान एवं अन्य। एएनआइ

18 ग्रेनेडियर्स बटालियन ने कारगिल युद्ध में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका

नई दिल्ली, प्रेट्र : चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने वीरवार को कहा कि तकनीकी प्रगति के कारण युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और देश की सशस्त्र सेनाओं को इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। हम भारत को पेशेवर सशस्त्र बल और एक महाशक्ति बनना चाहते हैं। यह तभी हो सकता है जब हम नई ऊर्जा, नए जोश और नई सोच के साथ काम करें।

वे 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान तोलोलिंग और टाइगर हिल की लड़ाई के 25 साल पूरे होने के मौके पर सेना के अधिकारियों, जूनियर कमीशंड आफिसर (जेसीओ) और 18 ग्रेनेडियर्स के सैनिकों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। भारतीय सेना ने चार जुलाई 1999 को टाइगर हिल चोटी फतह की थी। कारगिल युद्ध में 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन ने अहम भूमिका निभाई थी। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।

जनरल चौहान ने कहा कि देश के लोगों को हमारी क्षमताओं पर भरोसा है और उसी के कारण हमारी इतनी प्रतिष्ठा है। जो विरासत आपको दी गई है, वह हमारे पूर्वजों द्वारा अर्जित की गई है। उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत रूप से और एक समुदाय के रूप में भी हमें जिम्मेदारियां सौंपता है। उन्होंने कहा कि एक सैनिक के रूप में कोई कभी गलती नहीं कर सकता और एक समुदाय के रूप में विश्वास कम नहीं किया जा सकता। जनरल चौहान ने कहा कि हम परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। हमें इस स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा।

वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि केवल परिवर्तन ही स्थायी है और भारतीय सशस्त्र बल इस बदलाव से दूर नहीं रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित तकनीकी घटनाक्रम के कारण युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पहले था कि युद्ध जीतने के लिए वीरता एक आवश्यक तत्व है, लेकिन भविष्य के युद्धों में केवल वीरता ही पर्याप्त नहीं है, हमें लचीला और कल्पनाशील बनना होगा तथा खुला दिमाग रखना होगा। जनरल चौहान ने कहा कि कई हथियारों के बेहतर प्रौद्योगिकी से उन्नत होने के साथ ही युक्तियां और रणनीतियां भी बदल गई हैं। उन्होंने कहा कि आज हम कई क्षेत्रों में युद्ध की बात कर रहे हैं। केवल पारंपरिक क्षेत्रों जैसे कि जमीन, समुद्र और वायु के बजाय हमारी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और अंतरिक्ष क्षेत्र भी जोड़े गए हैं। सीडीएस ने कहा कि लोग सशस्त्र बलों से प्यार करते हैं तथा उन पर भरोसा करते हैं। अगर हमें इसे बरकरार रखना है तो हमें बदलाव लाना पड़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम युद्ध में असफल नहीं हो सकते। खेलों के विपरीत युद्ध में कोई उपविजेता नहीं होता क्योंकि विजेता सब कुछ जीत लेता है। जनरल चौहान ने कहा कि इस भरोसे को बनाए रखने के लिए आपको नई चीजों को समझना तथा स्वीकार करना होगा।

टाइगर हिल की लड़ाई निर्णायक साबित हुई

कारगिल हीरो बोले

18 ग्रेनेडियर्स बटालियन के कारगिल नायकों ने आपरेशन विजय में अपने जांबाजों की वीरता को याद किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : सेना में शामिल होने के महज चार महीने बाद ही युवा लेफ्टिनेंट बलवान सिंह ने कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों के हमले में भारतीय सेना की घातक पलटन का नेतृत्व किया और वह चार जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर कब्जा जमाने वाले बहादुर जवानों में से एक थे। वह अब प्रसिद्ध 18 ग्रेनेडियर्स के कर्नल हैं। दुश्मन से लड़ते वक्त घायल होने के बावजूद मुकाबला जारी रखने वाले बलवान सिंह ने उस वक्त को याद करते हुए कहा- 'वहां से फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह टाइगर हिल पर कब्जे के बाद की जीत थी।' उन्हें उनकी बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 18 ग्रेनेडियर्स की स्थापना 1976 में हुई और इसने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बटालियन को परम वीर चक्र, दो महावीर चक्र, छह वीर चक्र, सात सेना पदक और थल सेनाध्यक्ष से प्रशस्ति पत्र समेत 52 सम्मानों से नवाजा गया।

बुधवार को कर्नल बलवान सिंह तथा बटालियन के कई अन्य कारगिल नायकों ने आपरेशन विजय में अपने जांबाजों की वीरता को याद किया। भारतीय सेनाओं के पाकिस्तानी बलों को पीछे हटने के लिए सफलतापूर्वक मजबूर करने के बाद 26 जुलाई 1999 को युद्ध खत्म होने की घोषणा की गई थी। ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) कुशाल ठाकुर ने बताया कि तीन जुलाई 1999 की रात को 18 ग्रेनेडियर्स के जवानों ने टाइगर हिल पर कब्जा जमाने के अपने अभियान की शुरुआत की और अगली सुबह तक अपने अभियान में कामयाबी हासिल की। ठाकुर ने तोलोलिंग और टाइगर हिल की अहम लड़ाइयों के दौरान इस बटालियन की कमान संभाली थी।

उन्होंने कहा कि 12-13 जून 1999 को हमने तोलोलिंग जीता और यह इस युद्ध में महत्वपूर्ण विजय थी। इसने हमारे सशस्त्र बलों तथा देशवासियों का मनोबल ऊंचा किया और पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल गिराया। एक-एक करके हम मुश्को और बटालिक सेक्टर की चोटियों पर कब्जा करते गए और हमारा अगला लक्ष्य टाइगर हिल था। उन्होंने कहा कि टाइगर हिल के लिए मेरे पास टोह लेने का पर्याप्त समय था। मेरे पास तोपखाने की बंदूकें, मल्टी बैरल राकेट लांचर और ऊंचाई पर लड़ने के लिए आवश्यक युद्ध उपकरण थे। तमाम क्षति के बावजूद 18 ग्रेनेडियर्स के हमारे जवानों का मनोबल ऊंचा था और हमारे जांबाज सैनिकों ने टाइगर हिल पर कब्जा जमा लिया, उसकी चोटी पर भारतीय ध्वज फहराया।

कर्नल सचिन अन्नाराव निम्बालकर को युद्ध के दौरान उनकी वीरता के लिए सेना पदक से सम्मानित किया गया। वह युद्ध के दौरान 18 ग्रेनेडियर्स के कैप्टन के तौर पर काम कर रहे थे तथा उस वक्त करीब 23 वर्ष के थे।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने दिए 300 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, एएनआइ : रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपये आवंटित किए किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी विकास कोष (टीडीएफ) के माध्यम से यह फंड दिया है। टीडीएफ को 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत डीआरडीओ द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

इस पहल के तहत सरकार एमएसएमई और स्टार्टअप्स के साथ-साथ शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थानों सहित भारतीय उद्योगों को रक्षा और दोहरे उपयोग वाली उन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए सहायता देती है, जो इस समय भारतीय रक्षा उद्योग में उपलब्ध नहीं हैं।

इसका उद्देश्य देश में रक्षा प्रौद्योगिकियों के डिजाइन और विकास के लिए भारतीय उद्योगों की क्षमता बढ़ाना और ऐसा ईकोसिस्टम बनाना है जहां उद्योग और शिक्षा जगत सशस्त्र बलों और रक्षा क्षेत्र की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलकर काम करें।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस योजना की मदद से पुणे की स्टार्टअप कंपनी चिरस्टेट्स लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, एयरो गैस टर्बाइन इंजन के लिए वर्चुअल सेंसर विकसित कर रही है, जिससे इंजनों की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। यह सिस्टम आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग तकनीकों पर बनाया गया है।

साइबर क्षेत्र को सुरक्षित बनाने को सहयोग बढ़ाने पर भारत-ब्रिटेन सहमत

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत व ब्रिटेन साइबर क्षेत्र को सुरक्षित एवं मजबूत बनाने के लिए अपनी साइबर एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर बुधवार को सहमत हो गए हैं। छठी साइबर वार्ता में सहमति बनी।

विदेश मंत्रालय ने बताया, 'वार्ता के दौरान हुई चर्चा में साइबर खतरों का मूल्यांकन, इंटरनेट प्रशासन, डाटा की सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र में साइबर क्षेत्र में नवीनतम विकास सहित बहुपक्षीय मंचों पर क्षमता निर्माण व सहयोग शामिल हैं।' वार्ता की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में साइबर कूटनीति प्रभाग के संयुक्त सचिव अमित ए. शुक्ला और ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल व विकास कार्यालय के साइबर नीति विभाग में रणनीति एवं वार्ता की प्रमुख कैट जोंस ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सीईआरटी-इन और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के अधिकारी शामिल थे।

न्यायाधीश सुपर ह्यूमन नहीं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं : हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण ● चंडीगढ़

- जज के खिलाफ दाखिल याचिका का सिंगल बेंच ने लिया था संज्ञान
- केवल तारीख देने और फैसला न करने का लगाया गया था आरोप

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश से संबंधित कथन सद्भावना में हो तो इसे अवमानना नहीं माना जा सकता। न्यायाधीश सुपर ह्यूमन नहीं होते और गलतियां कर सकते हैं, उन्हें आलोचना के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हाई कोर्ट ने एक जज के खिलाफ शिकायत वाली दलीलों के साथ याचिका दाखिल करने वाले के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई को रद करते हुए यह टिप्पणी की।

सुरजीत सिंह ने याचिका में दलील दी थी कि उसका एक मामला डेराबस्सी की अदालत में विचाराधीन है। जज बार-बार तारीख दे रहे हैं। वह केस का निपटारा नहीं कर रहे। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पाया कि याची के वकील ने ही कई बार सुनवाई स्थगित करने का निवेदन किया था। बिना सही तथ्यों के न्यायाधीश पर आरोप लगाने को गंभीरता से लेते हुए सिंगल बेंच ने आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। एमिकस क्यूरी एडवोकेट तनु बेदी ने कहा कि न्यायालय की अवमानना से संबंधित कानून के अनुसार प्रतिवादी का आचरण आपराधिक अवमानना नहीं माना जाना चाहिए। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने कहा कि प्रतिवादी की दलीलों से यह संकेत नहीं मिलता है कि वह दुर्भावनापूर्ण हैं या सद्भावना से नहीं बनाई गई हैं। याचिकाओं को बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है कि वे दुर्भावनापूर्ण थीं। स्वस्थ और रचनात्मक आलोचना का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए। न्यायालय के आदेश सार्वजनिक होते हैं और चर्चा व आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए खुले हैं। न्यायाधीश सुपर ह्यूमन नहीं होते और गलतियां करते हैं। संवाद और बहस कानून के शासन द्वारा शासित लोकतंत्र की पहचान हैं।

'कलेजियम की जानकारी सार्वजनिक करने से नियुक्ति प्रक्रिया पर असर'

जासं, नई दिल्ली : न्यायाधीशों की पदोन्नति के लिए हाई कोर्ट कलेजियम की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट कलेजियम की ओर से अस्वीकार करने के कारणों को सार्वजनिक करने की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक करने से नियुक्ति प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। जिनके नामों की सिफारिश की गई है, उनके हितों और प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होगा।

एकल न्यायाधीश ने सीए राकेश कुमार गुप्ता की याचिका को खारिज करते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने सही कहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कलेजियम की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर अपील पर सुनवाई नहीं कर सकता है। इस वर्ष के अंत तक जिला न्यायपालिका की वास्तविक ताकत वस्तुतः उसकी स्वीकृत ताकत के बराबर हो जाएगी। ऐसे में एकल पीठ ने सही माना है कि अपीलकर्ता के पास रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

अगले सप्ताह रूस-आस्ट्रिया जाएंगे मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पुतिन के साथ बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के अलावा क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर भी होगी चर्चा
- 10 जुलाई को आस्ट्रिया जाएंगे मोदी, 41 वर्षों बाद कोई भारतीय पीएम इस देश की यात्रा करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। फाइल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आठ से दस जुलाई तक रूस और आस्ट्रिया का दौरा करेंगे। रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर वह पहले आठ और नौ जुलाई को मास्को की यात्रा करेंगे और उसके बाद एक दिन के लिए आस्ट्रिया जाएंगे।

विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की बैठक में द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से बात होगी और साथ ही दूसरे क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। रूस भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार देश है। अभी भी भारत अपनी सैन्य जरूरत का 50 प्रतिशत सामान रूस से लेता है। अब भारत ने रूस से बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की खरीद भी शुरू कर दी है। मोदी-पुतिन वार्ता में द्विपक्षीय कारोबार व साथ मिलकर दूसरे देश में कनेक्टिविटी परियोजना लगाने की संभावना पर भी बात होगी।

भारत और रूस के बीच हर वर्ष शिखर सम्मेलन की व्यवस्था थी जो वर्ष 2022 व वर्ष 2023 में नहीं हो सकी थी। इस व्यवस्था के तहत भारत के प्रधानमंत्रियों और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच अभी तक 21 सालाना बैठक हो चुकी हैं। दिसंबर, 2021 में इस शिखर वार्ता के लिए राष्ट्रपति पुतिन कुछ घंटों के लिए भारत आए थे। इसके पहले वर्ष 2019 में मोदी ने रूस की यात्रा की थी। तब दोनों देशों के बीच 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद मोदी और पुतिन के बीच एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान सितंबर, 2022 में समरकंद में बैठक हुई थी। उस बैठक में मोदी ने पुतिन को यूक्रेन-रूस युद्ध के संबंध में कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। यह बयान काफी प्रसिद्ध हुआ था और अमेरिका व दूसरे देशों ने इसके आधार पर रूस को घेरने की कोशिश की थी। हालांकि, यूक्रेन व रूस के बीच अभी भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। यह भी महत्वपूर्ण है कि मोदी से मुलाकात से छह दिन पहले (3 जुलाई) को पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ से मुलाकात की है।

यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के संबंध चीन से काफी मजबूत हुए हैं जबकि पाकिस्तान के साथ भी उसके रिश्ते सुधर रहे हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि भारत और रूस के रिश्ते बिल्कुल अलग किस्म के हैं और इन्हें किसी भी सूरत में रूस-चीन या रूस-पाकिस्तान संबंधों से जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए। रूस के बाद पीएम मोदी आस्ट्रिया जाएंगे जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 41 वर्षों बाद आस्ट्रिया की यात्रा होगी।

जल्द ही कूटनीतिक स्तर पर की जाएगी वार्ता : विदेश मंत्रालय

प्रथम पृष्ठ से आगे

सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर और कूटनीतिक स्तर पर अलग-अलग वार्ताओं का दौर चलता है। बाद में विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी सूचना में बताया गया कि जल्द ही कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की जाएगी। मई, 2020 में चीन ने कई ऐसे क्षेत्रों में घुसपैठ कर ली थी जिसे दोनों देशों की तरफ से दशकों से विवादग्रस्त माना जा रहा था। इनमें से कई स्थलों से चीन के सैनिक वापस हो चुके हैं, लेकिन कई स्थलों पर अभी भी दोनों तरफ से सैनिकों की तैनाती बनी हुई है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि दोनों मंत्री इस बात पर भी एकमत हैं कि सीमा पर मौजूदा हालात को ज्यादा लंबे समय तक खींचना द्विपक्षीय रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष को यह फिर बताया कि द्विपक्षीय संबंधों को लेकर पूर्व में किए गए समझौतों व सहमतियों का पालन करना बहुत जरूरी है।

दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि वांग यी ने बैठक में कहा कि पंचशील सिद्धांत के तहत दोनों बड़े पड़ोसियों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने भारत और चीन को ग्लोबल साउथ के दो बड़े देश बताते हुए इन्हें विकसित देशों के दबाव में नहीं आने की बात कही। उन्होंने पूर्व में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं (प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति चिनफिंग) के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सुधार को लेकर बनी सहमति के आधार पर आगे बढ़ने की भी बात कही। ज्ञात हो, दोनों देशों के संबंध मौजूदा समय में बहुत अच्छे नहीं हैं। चीन वैश्विक मंच पर भारत के विरोध का मौका नहीं छोड़ता।

चंद्रबाबू ने केंद्र सरकार से मांगा आंध्र के पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज

अनुरोध

- पीएम नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात
- पोलावरम परियोजना को शुरू करने समेत सात सूत्री एजेंडे पर किया जोर

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान नायडू ने राज्य की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से सात सूत्री विकास एजेंडे के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने आंध्र के पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज की मांग की। नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। अमित शाह ने कहा कि राजग सरकार विकसित आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

राजग के प्रमुख सहयोगी, तेलुगु देसम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख ने पीएम से मुलाकात के दौरान कहा कि अगर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता तो राज्य को इसके बदले और अधिक सहायता दी जाए। बैठक में दोनों नेताओं ने वित्तीय सहायता से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की

नायडू ने पोलावरम परियोजना को शीघ्र शुरू करने के लिए समर्थन पर जोर दिया। यह बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना है। कहा, आंध्र प्रदेश 2014 के अनुचित और अन्यायपूर्ण विभाजन के दुष्परिणामों से जूझ रहा है। पिछली सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन ने राज्य की आर्थिक स्थिति को और खराब कर दिया है। उन्होंने केंद्र से अल्पकालिक वित्तीय सहायता का अनुरोध किया।

अमरावती के सरकारी परिसर और प्रमुख बुनियादी ढांचे को पूरा करने के लिए समर्थन, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए राज्य की विशेष सहायता योजना के तहत अतिरिक्त आवंटन की मांग भी एजेंडे में शामिल थे। दुग्गीराजुपट्टनम बंदरगाह के विकास पर भी चर्चा हुई।

पीएम मोदी से मिले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी

नई दिल्ली, प्रेट्र : तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान रेवंत के साथ उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू भी थे। नरेन्द्र मोदी के तीसरी बार पीएम पद का कार्यभार संभाल लेने के बाद मोदी और रेड्डी के बीच यह पहली मुलाकात थी। सूत्रों ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मोदी के साथ राज्य की प्रमुख लंबित परियोजनाओं पर चर्चा की। रेवंत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। यह नहीं बताया गया है कि मुलाकात के दौरान क्या बातें हुईं, लेकिन माना जाता है कि विकास परियोजनाओं और राज्य को केंद्रीय सहायता से जुड़े मुद्दे एजेंडे में थे।

चंद्रबाबू ने एक्स पर पोस्ट किया, मैंने आंध्र प्रदेश के कल्याण और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ रचनात्मक बैठक की। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हमारा राज्य राज्यों के बीच शक्ति केंद्र के रूप में फिर से उभरेगा।

नायडू ने सात केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, मनोहर लाल, हरदीप पुरी, राम मोहन नायडू से भी मुलाकात हुई। उन्होंने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पानगढ़िया से भी मुलाकात की। शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेदेपा के सांसदों के साथ बैठक की।

हमने देश और राज्य की प्रगति में तेजी लाने से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की। राजग सरकार विकसित भारत और विकसित आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। आंध्र प्रदेश में सत्ता में आने के बाद सीएम नायडू की केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के साथ यह पहली बैठक थी। इससे पहले वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे।

कांग्रेस सांसद का आरोप

बिरला को पत्र लिख मोदी व ठाकुर पर कार्रवाई की मांग

मणिक्कम टैगोर ने कहा, लोकसभा में दिए गए गलत और भ्रामक बयान, टैगोर ने कहा, जीतने की शर्त पर था 8,500 देने का वादा

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने सदन में तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बयान दिए हैं। उन्होंने इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है।

सूत्रों ने बताया कि टैगोर ने बिरला को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि मोदी और ठाकुर द्वारा दिए गए बयानों पर निर्देश 115(1) के प्रविधानों को लागू किया जाए। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने महिलाओं को 8,500 रुपये प्रति माह देने का झूठा वादा किया था, जबकि पार्टी का वादा जीतने और सरकार गठन की शर्त पर था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस दावे को भी चुनौती दी कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत उन 16 राज्यों में कम हुआ है, जहां उसने अकेले चुनाव लड़ा था। टैगोर ने पत्र में कहा, ''हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तेलंगाना आदि में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है।'' उन्होंने मोदी की इस टिप्पणी को भी बेहद भ्रामक बताया कि कांग्रेस के समय सेना के लिए कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी।'' टैगोर ने कहा, ''जैकेट की कमी थी, ऐसा नहीं है कि जैकेट नहीं थे। यहां तक कि मुंबई हमलों की तरह पुलिस के पास भी बुलेट प्रूफ जैकेट थीं।'' उन्होंने प्रधानमंत्री के इस दावे को भी चुनौती दी कि कांग्रेस ने सेना को लड़ाकू विमान नहीं दिए। पत्र में लिखा है, ''हमारे पास जगुआर, मिग-29, एसयू-30, मिराज-2000 विमान थे।''

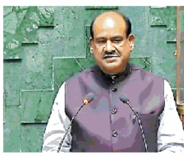
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। फाइल

टैगोर ने लोकसभा में अनुराग ठाकुर के एक जुलाई के भाषण में कथित अशुद्धियों की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा, ठाकुर ने दावा किया था कि जब कांग्रेस देश पर शासन कर रही थी, तब सेना को हथियार व लड़ाकू विमान नहीं दिए गए थे। टैगोर ने कहा, ''हमारे पास जगुआर, मिग-29, एसयू-30, मिराज 2000 थे... हमारे पास परमाणु बम, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और बाद में ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें थीं।''

टैगोर ने ठाकुर की इस टिप्पणी को भी गलत बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है और सवाल किया कि चुनाव प्रचार के लिए किस श्रेणी की छुट्टी ली जाती है। ज्ञात हो कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहले ही संबोधन में राहुल गांधी ने भाजपा-संघ के हिन्दुत्व को नफरत और हिंसा से जोड़ते हुए प्रहार किया। भाषण के दौरान नान-बायलाजिकल और परमात्मा से सीधे संवाद जैसे तंजों के सहारे उन्होंने पीएम मोदी पर हमले का मौका नहीं छोड़ा।

केंद्र दवाओं की आनलाइन बिक्री की नीति को जल्द अंतिम रूप दे : हाई कोर्ट

चेन्नई, प्रेट्र : मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दवाओं की आनलाइन बिक्री संबंधी नीति को जल्द अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि फिर उसे दिल्ली हाई कोर्ट के चार मार्च, 2024 के आदेशानुसार अधिसूचित करें। कोर्ट ने गुरुवार को एम/एस प्राक्टो टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड और सात अन्य की दायर अपील का निस्तारण करते हुए हाल के आदेश पर अपने दिशा-निर्देश दिए हैं। इन कंपनियों ने दिसंबर, 2018 के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की आनलाइन बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि जिस समय तक केंद्र सरकार नीति बना नहीं लेती या दिल्ली हाई कोर्ट मामले का निपटारा नहीं कर देती मौजूदा स्थिति बरकरार रहेगी। हालांकि दवाओं की आनलाइन बिक्री केवल लाइसेंसशुदा दवा विक्रेताओं की ओर से ही की जाएगी।

कह कर रहेंगे — माधव जोशी

****

2024 में राजस्थान की 25 लोकसभा की सीटों में से भाजपा ने 14 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 2019 के चुनावों में इसकी संख्या 24 थी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 5 जुलाई, 2024

राजस्थान के कृषि मंत्री ने निभाया वादा, भाजपा के खराब प्रदर्शन पर दिया इस्तीफा

किरोड़ी लाल मीणा ने कई दिन पहले सीएम को भेजा था इस्तीफा, गुरुवार को किया सार्वजनिक

जागरण संवाददाता● जयपुर

राजस्थान में लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राज्य के कृषि मंत्री डा. किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कई दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस्तीफा सौंपा था, लेकिन न तो मीणा ने और न ही सीएम ने इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा की थी। मीणा ने गुरुवार को इस्तीफा देने की जानकारी सार्वजनिक कर दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीणा के इस्तीफे पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था, 'रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई'।

72 वर्षीय किरोड़ी लाल मीणा पांच बार विधायक, राज्यसभा सदस्य और दौसा व सवाई माधोपुर से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने गुरुवार को एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान इस्तीफे

- प्रदेश सरकार और संगठन में बढ़ी हलचल, मीणा आज केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे मुलाकात

किरोड़ी लाल मीणा। फाइल

की आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा, मैंने गत आठ और 25 जून को सीएम को इस्तीफा भेजा था, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद मेल पर भेजा है। वह दो दिन पहले दिल्ली में थे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन किन्ही कारणों से उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। शुक्रवार को फिर दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मिलने जाऊंगा।

मीणा ने कहा, मुख्यमंत्री या संगठन से कोई नाराजगी नहीं है। कोई अपेक्षा भी नहीं है ना ही मुझे अब कोई पद चाहिए। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कहा था कि यदि भाजपा प्रत्याशी हार गए तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दूंगा। दौसा और टोंक-सवाईमाधोपुर सीट से भाजपा के प्रत्याशी चुनाव हार गए, इस कारण इस्तीफा दिया है। जनता ने मुझे निराश किया। मैं पार्टी को जीत नहीं दिला सका, यह मेरी असफलता है।

मीणा के इस्तीफे के बाद प्रदेश सत्ता और संगठन में हलचल बढ़ गई है। विधानसभा में उनके विभाग के सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी राज्यमंत्री केके बिश्नोई व ओटाराम देवासी को सौंपी गई है।

मुख्यमंत्री से नाराज थे मीणा: बताते हैं कि करीब छह महीने पहले प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही मीणा नाराज थे। उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया, लेकिन कृषि विपणन जैसा विभाग इससे अलग कर दिया गया। केवल कृषि विभाग ही दिया गया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग पहले एक ही मंत्री को दिए जाते थे। पार्टी नेतृत्व ने इन्हें दो भागों में बांट दिया और मीणा को कम महत्व का ग्रामीण विकास विभाग दिया गया।

लोकसभा चुनाव में मीणा ने अपने भाई जगमोहन मीणा के लिए दौसा सीट से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। मीणा इससे नाराज थे। वह पिछले दो महीनों से सरकारी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे थे। मंत्रिमंडल की पिछले दिनों हुई बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने सरकारी कार करीब दो महीने पहले ही लौटा दी थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की 25 सीटों में से 14 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 2019 के चुनावों में इसकी संख्या 24 थी।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग को लेकर राजस्थान विधानसभा में हंगामा

जागरण संवाददाता●जयपुर

राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस सहित संपूर्ण विपक्ष के विधायकों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की। विपक्ष के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गए और फिर दिलावर की तरफ बढ़े। इस बीच भाजपा के विधायकों ने भी दिलावर को घेर लिया। दोनों पक्षों के विधायकों के बीच धक्का-मुक्की हुई। सदन में शांति स्थापित करने के लिए अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मार्शल को बुलाया। काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों के विधायक अपनी-अपनी सीटों पर लौटे। बाद में दिलावर के इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्ष के विधायकों ने सदन से वाकआउट किया। हंगामें के बीच सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित की गई। विपक्ष के विधायकों ने दिलावर से माफी मांगने की भी मांग की।

दिलावर ने पिछले दिनों मीडिया में बयान दिया था कि आदिवासी हिंदू हैं। आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते हैं तो उनका डीएनए टेस्ट करवा लेंगे, जिससे

- सदन में शांति स्थापित करने के लिए अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मार्शल को बुलाया

मदन दिलावर। फाइल

मंत्री ने राहुल को मंदबुद्धि बालक बताया

विपक्ष के सदन से बहिष्कार के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा, राहुल गांधी एक तरफ तो कहते हैं डरो मत और दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक सदन से डरकर भाग रहे हैं। कांग्रेस विधायकों के लिए उन्होंने कहा, आप चर्चा में भाग लीजिए। आपके मंदबुद्धि बालक राहल गांधी ने हिंदू समाज को बदनाम किया है। उन्हें हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को धरातल की जानकारी नहीं है।

पता चल जाएगा कि उनका पिता कौन है। कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों ने दिलावर के खिलाफ हंगामा करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा, दिलावर ने माफी नहीं मांगी और ना ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनसे इस्तीफा लिया है। इस कारण विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया है।

मंत्री ने दी सफाई: अपने बयान को लेकर दिलावर ने कहा, आदिवासियों ने हमारी संस्कृति को बचाया है। आदिवासी समाज के बारे में कोई नकारात्मक चर्चा करना मेरे मन में कभी नहीं रहा है। मैं यह जानता हूं कि अनादि काल से इस देश में आदिवासी रहते आए हैं। आदिवासी समाज का सब सम्मान करते हैं। आदिवासी समाज का सब सम्मान करते हैं। आदिवासी मेरे पूज्य हैं। आदिवासी हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। मैं आदिवासी महापुरुषों को प्रणाम करता हूं। मैं श्रद्धा से उनका नाम लेता हूं। इस बीच उधोग मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने कहा, आदिवासी समाज हमेशा हिंदू था। महाराणा प्रताप के साथ रहकर मुसलमान आक्रांताओं के खिलाफ इसी समाज ने लड़ाई लड़ी थी। राठौड़ ने कहा, दिलावर के इस्तीफे की मांग करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में हिंदुओं को अहिंसक बताया है। कांग्रेस का सोच हमेशा से हिंदुओं के खिलाफ रही है।

आंध्र में भय का माहौल पैदा कर रहे सीएम चंद्रबाबू नायडू : जगन मोहन

नेल्लोर, प्रेट्र : वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू पर उन लोगों के बीच भय का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया था।

नेल्लोर केंद्रीय कारागार के बाहर पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा, 'पूरे राज्य में सिर्फ इसलिए कुछ लोगों की परिसंपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है और उनके विरुद्ध फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने तेदेपा एवं नायडू को वोट नहीं दिया। वे (सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य) अपने विरोधियों (वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के समर्थकों) के साथ मारपीट कर रहे हैं और पीड़ितों के विरुद्ध मामले दर्ज किए जा रहे हैं।'

जगन ने केंद्रीय कारागार में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता पी. रामकृष्ण रेड्डी से मुलाकात की। रामकृष्ण रेड्डी करमपुडी गांव में 14 मई को एक पुलिस इंस्पेक्टर पर कथित रूप से हमला करने मामले में जेल में हैं।

जगन ने यह भी आरोप लगाया कि

- कहा, तेदेपा को वोट नहीं देने वालों की परिसंपत्तियों को किया जा रहा नष्ट
- सत्तारूढ़ दल के लोग विरोधियों से कर रहे मारपीट, फर्जी मामले हो रहे दर्ज

जगन मोहन रेड्डी। फाइल

दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भय का माहौल पैदा करने की राजनीति दीर्घकाल में तेदेपा को ज्यादा दूर लेकर नहीं जाएगी। उन्होंने वर्तमान सरकार की तुलना अपने नेतृत्व वाली सरकार से करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया। जगन ने दावा किया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लोगों का कल्याण करने के बावजूद हार गई क्योंकि नायडू ने भ्रामक वादे किए और लोग बहक गए।

यूडीएफ ने एसएफआइ पर लगाया हिंसक गतिविधियों का आरोप

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : केरल विधानसभा में गुरुवार को विपक्षी कांग्रेस ने एसएफआइ पर राज्य में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री पी. विजयन ने वामपंथी छात्र संगठन का बचाव करते हुए कांग्रेस समर्थित केएसयू पर अत्याचार का आरोप लगाया।

कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और माकपा छात्र संगठन- स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआइ) को राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। दावा किया कि राज्यभर में विश्वविद्यालय परिसरों और उसके बाहर हिंसक और आपराधिक गतिविधियों के लिए एसएफआइ जिम्मेदार है।

विधायकों ने केरल विश्वविद्यालय परिसर में एसएफआइ द्वारा केरल छात्र संघ (केएसयू) के नेता की कथित तौर पर पिटाई के मामले पर सदन में चर्चा की मांग की। विपक्ष के प्रस्ताव को विजयन ने खारिज कर दिया। कहा कि पुलिस ने मंगलवार को केएसयू नेता की कथित पिटाई और बुधवार को श्रीकार्यम पुलिस थाने के बाहर दो छात्र समूहों के बीच संघर्ष के संबंध में मामले दर्ज किए हैं।

दिल्ली-हरियाणा विस चुनाव में कांग्रेस और आप में गठबंधन की गुंजाइश नहीं : जयराम

नई दिल्ली, प्रेट्र : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच गठबंधन की गुंजाइश नहीं है। लेकिन विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए महाराष्ट्र और झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में कहा कि राज्यों में चुनाव के लिए आइएनडीआइए का कोई एक फार्मूला नहीं है। कांग्रेस नेता और अन्य घटक दलों के साझीदार इस बात पर सहमत हैं कि राज्यों में सामूहिक रूप से लड़ेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइ एक साथ चुनाव लड़ेगा। जबकि पंजाब में कोई 'जनबंधन' नहीं है।

लोकसभा चुनाव में हरियाणा में हमने एक सीट आम आदमी पार्टी को दी थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में आइएनडीआइए एक साथ चुनाव नहीं लड़ेगा। दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन के लिए कोई स्कोप नहीं है। उल्लेखनीय

- कांग्रेस नेता ने कहा-विधानसभा में आइएनडीआइए का एक फार्मूला नहीं
- महाराष्ट्र-झारखंड में मिलकर लड़ेगा विपक्षी गठबंधन

जयराम रमेश। फाइल

'अंतरिक्ष से पहले मणिपुर जाएं गैर-जैविक प्रधानमंत्री'

नई दिल्ली, एएनआइ : कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अंतरिक्ष में जाने से पहले गैर-जैविक प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए। उन्होंने इसरो चीफ एस. सोमनाथ के एक पुराने बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री अंतरिक्ष में जाएं, तो अपने गगनयान में ही जाएं।

है कि कांग्रेस और आप ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ा था जबकि पंजाब में अलग-अलग चुनाव लड़ा था। रमेश ने कहा कि बंगाल के परिप्रेक्ष्य में भी आइएनडीआइए केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। लेकिन जहां-कहीं राज्य के हमारे नेता और विपक्षी घटक दलों के नेता एक साथ लड़ना चाहेंगे, विपक्षी गठबंधन कायम रहेगा। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन शिवसेना (यूबीटी) और राकांपा (एनसीपी) के साथ कायम रहेगा। झारखंड में भी हमारा गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) से है। इसके अलावा, जयराम रमेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी परजीवी है और इसने क्षेत्रीय दलों को खा लिया है।

अलगाववादी अमृतपाल को सशर्त पैरोल, राजनीतिक बयान देने की मनाही

जासं, तरनतारन : पंजाब के खडूर साहिब से लोकसभा सदस्य निर्वाचित अलगाववादी अमृतपाल सिंह को शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के चैंबर में शपथ दिलाई जाएगी। उसे चार दिन की सशर्त पैरोल मिली है। इस दौरान वह न तो कोई राजनीतिक बयान देगा और न ही उसका कोई वीडियो बनाया जा सकेगा। फोटो भी नहीं खींचे जा सकेंगे।

अमृतपाल सिंह।

अमृतपाल सिंह के विरुद्ध अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला करने के साथ ही कई आपराधिक केस दर्ज हैं। असम की डिब्रूगढ़ जेल में एनएसए के तहत बंद अमृतपाल सिंह को विमान से नई दिल्ली लाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के चैंबर में लोकसभा सदस्यता की शपथ लेने के बाद वहीं से डिब्रूगढ़ जेल ले जाया जाएगा। शपथ ग्रहण से संबंधित फोटो या वीडियो केवल लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही खींचे व बनाए जा सकेंगे।

बंगाल में अपने पुनरुत्थान के लिए जनमत संग्रह करने में जुटी माकपा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता : बंगाल में हाशिए पर आ चुकी माकपा अपने पुनरुत्थान के लिए अब जनमत संग्रह करने में जुट गई है। वामपंथी पार्टी लोगों से यह जानने का प्रयास कर रही है कि उससे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। वे पार्टी में क्या खामियां देख रहे हैं। उन्हें सुधारने के लिए क्या किए जाने की जरूरत है।

लोगों से ईमेल के माध्यम से उनका मत व्यक्त करने का अनुरोध किया जा रहा है। इसके साथ ही माकपा विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट लोगों का भी मत संग्रह करेगी। मालूम हो कि 2019 की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी माकपा बंगाल में एक सीट नहीं जीत पाई। इससे पहले 2021 के विधानसभा चुनाव में भी उसका खाता नहीं खुल पाया था। माकपा सूत्रों ने बताया कि पार्टी के बारे में मत व्यक्त करने वालों का परिचय गोपनीय रखा पर आगामी 23 से 25 अगस्त के दौरान नदिया जिले के कल्याणी में होने वाली माकपा की राज्य कमेटी की वर्द्धित बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की समीक्षा शुरू

अनिल ठाकुर● जागरण

शिमला : लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की समीक्षा शुरू हो गई है। पार्टी हाईकमान की ओर से गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों ने इसका फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। इस कमेटी में पीएल पुनिया और रजनी पाटिल शामिल हैं। रजनी पाटिल हिमाचल की प्रभारी रह चुकी हैं। वह प्रदेश की राजनीति व यहां की गुटबाजी से पूरी तरह परिचित हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के कई सदस्यों से फीडबैक लिया है।

13 जुलाई के बाद कमेटी सदस्य हिमाचल दौरे पर आएंगे। पहले शिमला में बैठक होगी। उसके बाद हमीरपुर, मंडी व कांगड़ा संसदीय क्षेत्रों में बैठकें होंगी। यह कमेटी प्रदेश कांग्रेस, जिला कांग्रेस के सदस्यों से फीडबैक लेगी। चारों संसदीय क्षेत्रों के प्रभारियों का भी फीडबैक लिया जाएगा। इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार

- पीएल पुलिया व रजनी पाटिल ने लिया कांग्रेस कमेटी सदस्यों से फीडबैक
- 13 जुलाई के बाद हिमाचल के दौरे पर आएगी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी

पीएल पुनिया।

रजनी पाटिल।

कर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को सौंपेगी। संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कहां पर सर्जरी की जरूरत है, कहां बदलाव किया जा सकता है, इस पर कमेटी की रिपोर्ट के बाद निर्णय होगा।

उपचुनाव जीते, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हीं क्षेत्रों में पिछड़े: वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर प्रदेश की सत्ता हासिल की थी। पार्टी के सत्ता में आने के 18 माह में ही 16 मार्च को लोकसभा सहित विधानसभा की छह सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई। सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस लोकसभा की चारों सीटों पर चुनाव हार गई। चुनाव में चौंकाने वाली बात यह रही कि जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस जीती, वहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पिछड़ गई। राज्य लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह कंगना रनौत से 74,755 मत के अंतर से चुनाव हार गए। कांगड़ा सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा 2,51,895 मत के अंतर से चुनाव हारे।

शिमला संसदीय सीट पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी 91,451 मत के अंतर से चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की संसदीय सीट हमीरपुर में भी कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा 1,82,357 मत के अंतर चुनाव हारे।

जम्मू कश्मीर में छह वर्ष बाद पूर्व मंत्री सैयद बशारत की पीडीपी में वापसी

राज्य ब्यूरो, जागरण● श्रीनगर : पूर्व मंत्री सैयद बशारत बुखारी गुरुवार को वापस पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा बन गए। उन्होंने छह वर्ष बाद घर वापसी करते हुए कहा कि सिर्फ महबूबा मुफ्ती सही मायनों में आम कश्मीरियों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। बुखारी के भाई पत्रकार शुजात बुखारी को वर्ष 2018 में आतंकियों ने श्रीनगर में मौत के घाट उतारा था।

सैयद ने अपना राजनीतिक कैरियर लगभग 22 वर्ष पहले पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ही शुरू किया था। वह उत्तरी कश्मीर में संग्रामा विधानसभा क्षेत्र से दो बार पीडीपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। वह कभी महबूबा मुफ्ती के करीबियों में एक थे। पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार में राजस्व मंत्री रहे सैयद की कुछ नीतिगत मामलों पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से बिगड़ गई थी। उन्हें वर्ष 2018 में पीडीपी प्रमुख ने संगठन विरोधी गतिविधियों के आरोप में संगठन से निष्कासित कर दिया था।

पंजाब में महिलाओं की निश्शुल्क बस सेवा पर चल सकती है कैंची

गहराया आर्थिक संकट

राज्य ब्यूरो, जागरण● चंडीगढ़

पंजाब में बढ़ते आर्थिक संकट के कारण महिलाओं को मिल रही निश्शुल्क बस सेवा को ज्यादा बनाए रखना आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। अब सरकार ने इसके विकल्प पर सोचना शुरू कर दिया है। इसका एक बड़ा कारण साल दर साल बढ़ती सब्सिडी है। राज्य में कांग्रेस की सरकार के दौरान जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस योजना को शुरू किया था, तब इस पर लगभग 600 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च आ रहा था, जो बढ़कर लगभग 750 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

महिलाओं के निश्शुल्क बस सेवा के लिए सरकार को हर महीने पंजाब रोडवेज और पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (पीआरटीसी) को 25-25 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं। ऐसे में इस समय जिस योजना पर आम सहमति बनती दिख रही है, वो है स्मार्ट कार्ड योजना, जिसके जरिये सरकार महिलाओं की निश्शुल्क बस सेवा को सीमित करेगी। यानी अब महिलाओं को हर माह निश्चित दिनों तक ही निश्शुल्क यात्रा की सुविधा होगी। इसके बाद यात्रा करने पर महिला से पूरे टिकट के पैसे लिए जाएंगे।

पंजाब पर है 3.27 लाख करोड़ का कर्ज

पंजाब पर मार्च 2024 तक 3.27 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। ऐसे में सरकार बिजली सब्सिडी के साथ-साथ अन्य सेक्टरों में दी जा रही सब्सिडी सीमित करने पर विचार कर रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रामण्यम से चर्चा की थी और उनसे राज्य को आर्थिक संकट से निकालने के बारे में सुझाव मांगे थे।

झारखंड

विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन का ही चेहरा होगा आगे, कांग्रेस को इससे बड़ी उम्मीदें, भाजपा ने अपने दो कद्दावर नेताओं को लगाया है मिशन झारखंड पर, सतर्क है महागठबंधन

हेमंत के सत्ता संभालने से गठबंधन का बढ़ा उत्साह

राज्य ब्यूरो, जागरण ● रांची

पांच माह पहले जब ईडी का शिकंजा हेमंत सोरेन के विरुद्ध कस रहा था तो सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकर्ता इसके विरोध में राजभवन के समक्ष प्रदर्शन में जुटे थे। राजधानी का यह वीवीआइपी इलाका कई दिनों तक कड़ी सुरक्षा घेरे में रहा। गुरुवार को परिस्थिति बदली हुई थी। हेमंत सोरेन राजभवन के अंदर तीसरी बार झारखंड की कमान संभाल रहे थे तो उनके समर्थकों का उत्साह चरम पर था। वे आतिशबाजी कर रहे थे। मिठाइयां भी बांटी गईं। हेमंत सोरेन की जेल से वापसी के एक सप्ताह के भीतर घटनाक्रम कुछ इस कदर बदला कि वह सीएम की कुर्सी संभालने के साथ-साथ अपनी रौ में पूरी तरह वापस लौट आए हैं। इससे उनके दल के साथ-साथ गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों में उत्साह है।

गठबंधन के विधायकों की संयुक्त बैठक में कांग्रेस ने आम सहमति बनाने से लेकर राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करने में हेमंत सोरेन का साथ दिया तो इसकी बड़ी वजह यह है कि आइएनडीआइए के दलों पर विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर राज्य की सत्ता में वापस लौटने का दबाव है। गठबंधन पिछले विधानसभा चुनाव की तरह हेमंत सोरेन के चेहरे को ही आगे कर चुनाव लड़ेगा। उनके फिर से सत्ता संभालने से कांग्रेस में उत्साह की बड़ी वजह लोकसभा चुनाव का परिणाम है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दो,

रांची में गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने पदभार ग्रहण किया। प्रेट्र

जबकि झामुमो के हिस्से में भी तीन सीटें आईं। सभी पांच आदिवासी सुरक्षित सीटों पर कब्जे की एक बड़ी वजह हेमंत के जेल जाने से पैदा हुई सहानुभूति को भी माना जा रहा है। ऐसे में हेमंत की मौजूदगी आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन के दलों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। सत्ता हस्तांतरण में भी कांग्रेस की सक्रियता इसी कारण दिखी।

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर यहां जमे रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी हर कदम पर हेमंत के साथ दिखे। ऐसे में गठबंधन में हेमंत के फिर सत्ता संभालकर पूरी तरह एक्शन में आने से गठबंधन में नए उत्साह का संचार हुआ है।

विशेष सत्र आठ को, विश्वास मत हासिल करेंगे हेमंत

प्रथम पृष्ठ से आगे

मुख्यमंत्री हेमंत की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें विधानसभा का विशेष सत्र आठ जुलाई, सोमवार को बुलाने का निर्णय लिया गया है। इसी दौरान मुख्यमंत्री हेमंत विश्वास मत हासिल करेंगे।

नौ जुलाई को होगा मंत्रिमंडल विस्तार: मुख्यमंत्री हेमंत नौ जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार में ज्यादा फेरबदल की संभावना नहीं है। विधानसभा में बहुमत परीक्षण के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसकी संभावना है कि चम्पाई सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल रहे मंत्रियों को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलेगी।

बन्ना हो सकते हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता : राज्य में कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में बन्ना गुप्ता की ताजपोशी हो सकती है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री रहे आलमगीर आलम की गिरफ्तारी और उनके इस्तीफे के बाद खाली यह पद खाली हुआ है।

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफार्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

धार्मिक ग्रंथों पर राहुल गांधी का प्रसारित बयान फर्जी

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

जेएनएन, नई दिल्ली: कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों पर विश्वास नहीं है।

पड़ताल: विश्वास न्यूज ने प्रसारित पोस्ट की जांच के लिए सबसे पहले वीडियो के असली वर्जन को सर्च किया। वीडियो के कीफ्रेम्स निकालने के बाद इन्हें गूगल लेंस टूल से सर्च किया। हमें एक यूट्यूब चैनल पर पूरा वीडियो मिला। इसे 10 सितंबर, 2023 को अपलोड किया गया था। वीडियो के कैप्शन में बताया गया कि राहुल गांधी ने पेरिस के साइंसेज पीओ यूनिवर्सिटी के छात्रों और फैकल्टी से संवाद किया। वीडियो के 18वें मिनट पर राहुल गांधी को कहते हुए सुना जा सकता है, 'मैंने गीता पढ़ी है। मैंने कई उपनिषद पढ़े हैं। मैंने कई हिंदू किताबें पढ़ी हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो करती है उससे हिंदू का कोई लेना-देना नहीं है। इनका हिंदुज्म से कोई संबंध नहीं है। उन्हें किसी भी कीमत पर पावर चाहिए। इसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं।'

क्या हो रहा है प्रसारित

फेसबुक यूजर मधुकर शर्मा ने चार जुलाई को एक वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, 'राहुल खुल्लम-खुल्ला बोल रहा है कि मुझे हिंदुओं के किसी भी धार्मिक ग्रंथ गीता भागवत रामायण शिव महापुराण पर कोई विश्वास नहीं है। कांग्रेस के ब्राह्मण नेता क्या अपना जनेउ तोड़ चुके हैं या नदियों में बहाकर तर्पण कर दिया है? क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेसी हिंदुओं को भावी मुसलमान कहना गलत होगा?' प्रसारित कंटेंट को यहां ज्यों का त्यों लिखा गया है।

निष्कर्ष: विश्वास न्यूज की पड़ताल में पता चला कि प्रसारित वीडियो में राहुल गांधी ने कहीं भी यह नहीं कहा था कि उन्हें किसी हिंदू धार्मिक ग्रंथ पर भरोसा नहीं है। हमारी जांच में प्रसारित पोस्ट फेक साबित हुई।

झूठी खबर और अफवाहों का सच जानने के लिए विश्वास न्यूज के वाट्सएप चैनल को फालो करने के लिए कोड स्कैन करें।

****

2 पुलिस निरीक्षकों को गुजरात के राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड मामले में सरकार ने निलंबित कर दिया है। पुलिस ने महानगर पालिका के शहर योजना अधिकारी मनसुख सागठिया को छह दिन के रिमांड पर लिया है।

सरकार बोली ▸ गाद निकालने में पुल-पुलिया का नहीं रखा गया ध्यान, ठेकेदार से वसूली जाएगी नए निर्माण की लागत

बिहार में इंजीनियरों-ठेकेदारों की कोताही से गिरे पुल-पुलिया

राज्य ब्यूरो, जागरण● पटना

बिहार सरकार भी मान रही कि गंडक नदी की शाखा (गंडकी) पर बनाए गए छह पुलों के ध्वस्त होने का कारण इंजीनियरों और ठेकेदारों की लापरवाही है। इनकी जगह बनाए जाने वाले पुलों की लागत राशि की वसूली ठेकेदारों से होगी। जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि ठेकेदारों ने गाद निकालने में पुलों के पाये और बुनियादी संरचना का ध्यान नहीं रखा तथा इंजीनियरों ने पुलों की नियमित देखरेख में लापरवाही बरती, जिसके कारण ये घटनाएं हुईं। विभाग का उड़नदस्ता जांच कर रहा है। 24 घंटे के भीतर यानी शुक्रवार तक जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। उस आधार पर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई तय है। तीन-चार जुलाई के बीच सिवान और सारण जिले में पहले से बने छह पुल-पुलिया ध्वस्त हो गए। आवागमन को सुचारु रखने के उद्देश्य से उनके स्थान पर नए पुल-पुलिया का निर्माण होगा। एक सप्ताह के भीतर कार्ययोजना बना ली जाएगी। पुल के निर्माण पर खर्च होने वाली राशि नदी की सफाई करने वाले ठेकेदार से ली जाएगी। यह एक तरह से हर्जाने की वसूली होगी।

विभाग के अपर मुख्य सचिव का मानना है कि प्रथमदृष्टया प्रतीत हो रहा कि इंजीनियरों द्वारा पुलों को सुरक्षित रखे जाने के लिए ऐहतियाती कदम नहीं उठाए गए। तकनीकी रूप से संतुष्ट होने के बाद ही पुल-पुलिया के पायों व संरचना के निकट खोदाई की जानी चाहिए, जिसका अनुपालन नहीं हुआ है। उड़नदस्ता टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

उल्लेखनीय है कि गंडक-अकाली नाला (छाड़ी)-गंडकी-माही (डबरा)-गंगा नदी जोड़ योजना का काम जल संसाधन विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

जर्जर पुलों को गिराकर होगा नया निर्माण: मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में जर्जर व खतरनाक हो चुके पुलों को ध्वस्त कर उनकी जगह नया निर्माण होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर 30 वर्ष से पुराने सभी पुलों का सर्वेक्षण होना है। संबंधित विभाग 15 दिनों के भीतर अपने दायरे वाले पुलों का सर्वेक्षण पूरा कर लेंगे। पुल निर्माण निगम की मेंटीनेंस पालिसी पहले से है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि 50 मीटर लंबाई तक वाले पुल ही ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाए जाएंगे। उससे अधिक लंबे पुलों को बनाने का दायित्व पुल निर्माण निगम का होगा।

गंडकी नदी पर बना एक और पुल हुआ ध्वस्त

जासं, बनियापुर (सारण)

बिहार में पिछले दो दिनों में गंडक नदी की शाखा (गंडकी) पर बना छठा पुल बुधवार रात ध्वस्त हो गया। यह पुल सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के सरेयां व सतुआ गांव के बीच मनरेगा के तहत पांच साल पूर्व बना था। लगभग 10 लाख रुपये की लागत वाले इस पुल के ध्वस्त होने से करीब आधा दर्जन गांवों के लोग प्रभावित हुए हैं।

दो पंचायतों को जोड़ने वाले इस पुल का निर्माण मनरेगा के तहत हुआ था। बुधवार की देर रात हल्की बारिश व गंडकी नदी के तेज बहाव से पुल गिर गया। गुरुवार को डीएम अमन समीर ने स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल को संयुक्त रूप से जांच कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। साथ ही गंडकी नदी पर बने सभी पुल/पुलिया की अद्यतन स्थिति की जांच का निर्देश दिया। मालूम हो कि प्रदेश में पिछले एक पखवाड़े में विभिन्न कारणों से 10 पुल ध्वस्त हो चुके हैं।

बिहार के सारण जिले के बनियापुर में गंडकी नदी पर बना ध्वस्त पुल। जागरण

फिर गिरा पुल, इसका दोष भी देंगे मुगल-अंग्रेज व विपक्ष को : लालू

राज्य ब्यूरो, जागरण● पटना

▸ तेजस्वी ने कहा - 18 जून से चार जुलाई के बीच ध्वस्त हुए 12 पुल

बिहार में पुल-पुलिया के गिरने की बढ़ती घटनाओं को लेकर राजद की ओर से सरकार पर हमले किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने चुटकी लेते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार इसका दोष भी मुगलों, अंग्रेजों और विपक्षियों को ही देंगे। बुधवार को एक दिन में पांच पुल ढहे। 15 दिन में 12 पुल गिर चुके हैं। पुलियों का कोई हिसाब-किताब ही नहीं।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि चार जुलाई की सुबह बिहार में एक पुल और गिरा। कल तीन जुलाई को अकेले ही पांच पुल गिरे। 18 जून से लेकर अब तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं।

अपने एक्स हैंडल पर तेजस्वी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश और निरुत्तर हैं। सोच रहे कि इस अमंगलकारी भ्रष्टाचार को जंगलराज में कैसे परिवर्तित किया जाए।

उन्होंने कहा कि सदैव भ्रष्टाचार, नैतिकता, सुशासन, जंगलराज, गुड गवर्नेंस पर राग अलाप दूसरों में गुण दोष के खोजकर्ता, कथित उच्च समझ के उच्च कार्यकर्ता, उन्नत कोटि के उत्कृष्ट पक्षकार सह उत्तम विचार के श्रेष्ठ लोग अंतरात्मा का गला घोट इन सुशासनी कुकृत्यों पर चुप्पी की चादर ओढ़ सदाचारी बन चुके हैं।

सारण से राजद उम्मीदवार रहीं लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य ने भी एक्स हैंडल पर लिखा कि डबल इंजन वाली सरकार के नेतृत्व में पुल-पुलिया के गिरने-टूटने, धंसने का इतिहास रच रहा है बिहार। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, यह बेहिसाब भ्रष्टाचार और खोखले दावों की सरकार है।

तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद। फाइल

खेत में गाड़ रखे थे नकली होलोग्राम, एसीबी ने खोदकर निकाला

नईदुनिया, रायपुर: छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने ढाई हजार करोड़ के आबकारी घोटाले में उपयोग किए गए नकली होलोग्राम बरामद किए हैं। नकली होलोग्राम की जब्ती रायपुर शहर से लगे धनेली के खेत से की गई है जो शराब घोटाले के आरोपित अनवर ढेबर के पिता के नाम पर है। सुबूत मिटाने के लिए होलोग्राम जलाने का प्रयास किया गया है। एसीबी ने करीब पांच बाक्स अधजले होलोग्राम जब्त किए हैं। इसके साथ ही नकली होलोग्राम भंडारण, वितरण और नष्ट किए जाने के मामले से संबंधित अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह, दीपक दुआरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों को 11 जुलाई तक एसीबी के रिमांड में सौंप दिया। अमित शराब घोटाले के आरोपित अरविंद सिंह भतीजा है। दीपक शराब सप्लाई का काम देखता था।

एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 से 2022 तक अनवर ढेबर और उसके सिंडीकेट ने सरकारी दुकानों से डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर अवैध शराब बेचकर शासन को करोड़ों की आर्थिक क्षति पहुंचाई थी। सिंडीकेट ने नोएडा से लाए फर्जी होलोग्राम, डिस्टिलरियों को वितरित किया था। वर्ष 2022 में ईडी की रेड के डर से अनवर ढेबर और अरविंद सिंह के कहने पर बचे हुए डुप्लीकेट होलोग्राम को नष्ट किया गया था। ईओडब्ल्यू की टीम ने गवाहों के समक्ष खोदाई कर उसे जब्त किया।

नीतीश की हाथ जोड़कर विनती, अगले साल जुलाई तक पूरा करें भूमि सर्वेक्षण का काम

राज्य ब्यूरो, जागरण● पटना

9,888

सर्वेकर्मियों की नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, सर्वेक्षण से समाज में कायम होगी शांति

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को एक कार्यक्रम में नवनियुक्त सर्वेकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रेट्र

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भूमि सर्वेक्षण पूरा करने का टास्क दिया है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2025 तक अगर भूमि सर्वेक्षण हो जाता है तो यह राज्य की बड़ी उपलब्धि होगी। भूमि विवाद समाप्त होगा। समाज में शांति आएगी, क्योंकि हिंसा की 60 प्रतिशत घटनाएं भूमि विवाद से जुड़ी होती हैं। नीतीश बुधवार को संवाद भवन में नवनियुक्त सर्वेकर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 9888 सर्वेकर्मियों की एकमुश्त नियुक्ति पर प्रसन्नता प्रकट की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 में सत्ता में आने के साथ ही उन्होंने भूमि विवाद समाप्त करने का प्रयास शुरू कर दिया था। पहला लक्ष्य यह था कि भूमि का स्वामित्व निर्धारित हो। इसके लिए भूमि सर्वेक्षण शुरू किया गया। 2013 में जमीन की एरियल फोटोग्राफी की गई। उन्होंने नव नियुक्त सर्वेकर्मियों से अपेक्षा की कि वे मन लगाकर तेजी से सर्वेक्षण कार्य को पूरा करेंगे। विभागीय मंत्री डा. दिलीप जायसवाल और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से कहा कि जुलाई 2025 तक सर्वेक्षण पूरा कर लें। उन्होंने इसके लिए अपर मुख्य सचिव से हाथ जोड़कर विनती भी की। कहा कि कई बार भूमि सर्वेक्षण की अंतिम तिथि तय की गई। हम उम्मीद करते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले यह काम हो जाएगा। सर्वेक्षण संबंधी काम जितना जल्दी पूरा हो जाएगा, जमीन विवाद समाप्त होगा और लोग आपस में शांति से रहेंगे।

कुल 9 हजार 888 को मिला नियोजन: विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए 9888 संविदाकर्मियों को नियोजित किया गया है। इनमें 353 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 758 कानूनगो, 742 विशेष सर्वेक्षण लिपिक एवं 8035 विशेष सर्वेक्षण अमीन हैं। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से 20 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। समारोह में कुल 75 नियुक्ति पत्र बांटे गए।

कांग्रेस ने कार्यालय पर हमले के विरोध में सड़कों पर उतरने का किया आह्वान

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान को लेकर भाजपा और कांग्रेस का टकराव दिल्ली से निकल कर गुजरात तक पहुंच गया है। अपने प्रदेश कार्यालय पर हुए हमले के विरोध में कांग्रेस ने शनिवार को अहमदाबाद की सड़कों पर उतरने का एलान किया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं।

गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने संसद में भगवान शिव का संदेश देते हुए भाजपा के नकली हिंदुत्व को उजागर किया तो पार्टी के अहमदाबाद कार्यालय पर हमला किया गया। उन्होंने राहुल गांधी को छह जून को अहमदाबाद आने का आमंत्रण दिया है। सात जुलाई को अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक 147वीं रथयात्रा निकलेगी। पुलिस हाई अलर्ट पर है। ऐसे में कांग्रेस का हल्ला बोल पुलिस के लिए मुसीबत बन सकता है। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान दोनों ओर से पथराव की घटना भी हुई थी।

नीट-यूजी रद करने की मांग का विरोध, 56 अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

जागरण ब्यूरो● नई दिल्ली

▸ याचिका दाखिल करने वालों में परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाला छात्र भी शामिल

▸ याचिकाकर्ताओं ने कहा- कड़ी मेहनत से हासिल की कामयाबी, दोबारा परीक्षा कराना तर्कसंगत नहीं

सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कई याचिकाएं पड़ी हैं जिसमें हाल में हुआ नीट-यूजी रद करने की मांग की गई है। अब इसके खिलाफ 56 छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पांच मई को हुई परीक्षा देने वाले 56 सफल छात्रों ने याचिका दाखिल कर मांग की है कि केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को पांच मई को हुए नीट-यूजी और चार जून को जारी हुआ उसका रिजल्ट रद करने से रोका जाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि एनटीए को निर्देश दिया जाए कि वह जांच करे और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों, पेपर लीक करने वालों और गैरकानूनी तरीके अपनाने वालों की पहचान करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। याचिका दाखिल करने वाले छात्रों में नीट-यूजी 2024 में प्रथम स्थान हासिल करने वाला छात्र भी शामिल है।

नीट-यूजी मामले में अब तक सुप्रीम कोर्ट दो दर्जन से ज्यादा याचिकाएं पहुंच चुकी हैं। ज्यादातर याचिकाओं में पांच मई को हुआ नीट-यूजी रद करके नए सिरे से परीक्षा कराने और परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच कराने की मांग की गई है। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी पहुंचे हैं जिनमें पूरी परीक्षा रद करने का विरोध किया गया है। उन्हीं में से यह नई याचिका है जो नीट देने वाले 56 अभ्यर्थियों ने दाखिल की है। इस याचिका पर सुनवाई की तिथि तो अभी तय नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नीट से जुड़ी सभी याचिकाओं पर आठ जुलाई को सुनवाई करेगा।

वैसे तो याचिका कुल 56 छात्रों की ओर से दाखिल की गई है लेकिन पहले याचिकाकर्ता छात्र का कहना है कि वह शुरू से मेधावी छात्र है और उसने कक्षा 12 में 96.60 प्रतिशत अंक अर्जित किए और अपने स्कूल में टाप किया। इसके अलावा नीट-यूजी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र भी मामले में याचिकाकर्ता है। याचिका में कहा गया है कि उन लोगों ने नीट-यूजी परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत की और वे सफल घोषित हुए। वे अपनी कड़ी मेहनत की सफलता का जश्न मना रहे थे कि तभी नीट-यूजी में गड़बड़ियों, पेपरलीक और ग्रेस मार्क के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल होने और नीट-यूजी रद कर नए सिरे से पूरी परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाएं दाखिल होने की मीडिया में खबरें आने लगीं। अब जो मीडिया में नीट-यूजी रद होने की खबरें आ रही हैं, उससे उन्हें बेवजह का मानसिक तनाव हो रहा है।

बंगाल में चोपड़ा कांड की जांच करने पहुंची मानवाधिकार आयोग की टीम

जागरण संवाददाता● इस्लामपुर

▸ पीड़ितों और उसके पड़ोसियों से की मुलाकात, थाना जाकर विभिन्न तथ्यों की ली जानकारी

▸ बर्बरता मामले में दो और आरोपित गिरफ्तार, तृणमूल नेता समेत अब तक सात गिरफ्तार

बंगाल के बहुचर्चित चोपड़ा कांड की जांच करने के लिए गुरुवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची। मालूम हो कि उत्तर दिनाजपुर जिले के अधीन चोपड़ा थाना इलाके के एक गांव में भरी पंचायत में एक युवक और युवती के साथ बर्बरता की गई थी। दोनों की पिटाई की गई थी और युवती के बाल खींचे गए थे। चोपड़ा पुलिस ने इस मामले में दो और आरोपितों को गिरफ्तार कर किया है। दोनों चोपड़ा ब्लाक के ही रहने वाले हैं। दोनों को इस्लामपुर एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस को कोर्ट से इन दोनों का पांच दिन का रिमांड मिला है। पुलिस इस घटना में मुख्य आरोपित तजीमुल इस्लाम उर्फ जेसीबी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जेसीबी स्थानीय तृणमूल नेता बताया जाता है। इसके अलावा चार अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान इस बर्बरता की चर्चा की थी।

टीम ने पीड़ितों के गांव पहुंचकर पीड़ित युवक और बाद में युवती से मुलाकात की। बाद में चोपड़ा थाने में पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर जरूरी जानकारी जुटाई। सबसे पहले पुलिस ने मुख्य आरोपित को गिरफ्तार किया था, इसके बाद प्रसारित वीडियो की जांचकर अमिरूल इस्लाम उर्फ बधुआ नामक आरोपित को पकड़ा। चोपड़ा कांड की पीड़िता ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम से इस घटना का वीडियो प्रसारित करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चार सदस्यीय टीम में एक महिला अधिकारी भी हैं।

बंगाल सरकार ने पिटाई की घटनाओं की रोकथाम को जारी किए दिशानिर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण● कोलकाता : बंगाल सरकार ने राज्य में सामूहिक पिटाई की एक के बाद एक सामने आ रहीं घटनाओं पर चिंता जताते हुए इसकी रोकथाम को 11-सूत्री दिशानिर्देश जारी किए हैं। मालूम हो कि हाल के दिनों में सिलसिलेवार तरीके से हुईं इन घटनाओं में अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन मामलों में पुलिस विभाग की भूमिका से बेहद नाराज हैं। जारी दिशानिर्देशों में लोगों को कानून अपने हाथों में नहीं लेने के प्रति जागरूक करने, सामूहिक पिटाई पर लगाम कसने के लिए ग्रामीण पुलिस व सिविल वालंटियरों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने व स्थानीय क्लबों की मदद लेने की बात कही गई है।

पुलिस को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से फैलने वालीं अफवाहों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। महिलाओं पर होने वाले अपराधों से सख्ती से निपटने को कहा गया है। ऐसे मामलों में अविलंब कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

ममता के खिलाफ मानहानि संबंधी राज्यपाल की याचिका पर 10 जुलाई को होगी सुनवाई

राज्य ब्यूरो, जागरण● कोलकाता

कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह बंगाल के राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। बोस ने 28 जून को मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की है कि राजभवन में हाल में हुई घटनाओं के कारण उन्हें वहां जाने में डर लगता है।

ममता बनर्जी। फाइल

राज्यपाल के वकील धीरज त्रिवेदी ने न्यायाधीश कृष्ण राव की अदालत के समक्ष मामले को प्रस्तुत किया, जिन्होंने बुधवार को मुकदमे की जल्द सुनवाई करने से इन्कार कर दिया था। यह टिप्पणी करते हुए कि मुकदमा खबरों के आधार पर दर्ज किया गया है, न्यायाधीश कृष्णा राव ने कहा कि इस मामले में जिन प्रकाशनों का संदर्भ दिया गया है, उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। याचिका में मुख्यमंत्री के अलावा तृकां के तीन और नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं।

बोस पर आरोप लगाने वाली महिला पहुंची सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो : बंगाल के राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस पर कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर संविधान के अनुच्छेद-361 के तहत राज्यपाल को आपराधिक मुकदमे से मिली छूट पर सवाल उठाया है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि बंगाल पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए। दाखिल याचिका में संविधान के अनुच्छेद-361 के तहत राज्यपाल को प्राप्त छूट पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि यह प्रविधान उस विक्टोरियन सोच से निकला है कि राजा कुछ गलत नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह यौन उत्पीड़न की पीड़िता है। उसके साथ घटना राजभवन में हुई, लेकिन संविधान के अनुच्छेद-361 में राज्यपाल को मिली पूर्ण छूट के चलते वह रैमेडीलेस (उपाय विहीन) हो गई है।

सीवी आनंद बोस।

मालूम हो कि संविधान का अनुच्छेद-361 राज्यपाल को आपराधिक कार्रवाई से पूर्ण छूट प्रदान करता है। पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती।

नीट पेपर लीक में जोधपुर एम्स के आरोपित छात्र की गिरफ्तारी पर रोक

जासं, मुजफ्फरपुर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से नीट पेपर लीक मामले में डीएवी स्कूल परीक्षा केंद्र पर प्रयागराज के नैनी के परीक्षार्थी राज पांडेय के बदले परीक्षा देने के आरोपित जोधपुर एम्स के छात्र हुकमा राम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। आरोपित की अग्रिम जमानत की अर्जी में एमबीबीएस के तीसरे वर्ष की परीक्षा में शामिल होने का हवाला देते हुए राहत देने की कोर्ट से प्रार्थना की गई थी। इसी पर सुनवाई के क्रम में उसकी गिरफ्तारी व अन्य दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पुलिस से केस डायरी मांगी है। दोनों की अग्रिम जमानत की अर्जी पर 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

हुकमा व राज के विरुद्ध जारी था वारंट: छात्र हुकमा राम व प्रयागराज के राज पांडेय के विरुद्ध कोर्ट ने वारंट जारी किया था। मामले के विवेचक दारोगा मिथुन कुमार ने दोनों के विरुद्ध वारंट जारी करने के लिए अर्जी दी थी।

भाजपा ने एमयूडीए घोटाले की सीबीआइ जांच की दोहराई मांग

बेंगलुरु, प्रेट्र : भाजपा ने मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) में कथित अनियमितताओं की सीबीआइ जांच की अपनी मांग गुरुवार को दोहराई। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने आरोप लगाया कि एमयूडीए के तत्कालीन अध्यक्ष और आयुक्त इस घोटाले में शामिल थे। बिचौलियों के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

अशोक ने कहा, ये अनियमितताएं तभी सामने आएंगी जब मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी जाएगी। भाजपा का आरोप है कि एमयूडीए में करीब 4,000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ जिनमें से एक लाभार्थी मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की पत्नी पार्वती भी हैं। आरोप है कि पार्वती को मैसूरु में आवंटित जमीन का मूल्य उनकी उस भूमि की तुलना में अधिक था। एमयूडीए ने पार्वती को उनकी तीन एकड़ से अधिक भूमि के बदले में 50:50 योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे।

बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला में पूर्व मंत्री की करीबी से पूछताछ करेगा आयकर विभाग

राज्य ब्यूरो, जागरण● कोलकाता

▸ अर्पिता के फ्लैट से बरामद हुए थे 50 करोड़ रुपये नकद

▸ बरामद धन के स्रोत का पता लगाना चाहता है आयकर विभाग

पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी। फाइल

शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी से आयकर विभाग पूछताछ करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक उसके फ्लैट से बरामद धन का स्रोत क्या है, घर में इतने पैसे क्यों रखे गए थे? ये सारी जानकारी मांगी जा सकती है। बता दें कि अर्पिता के फ्लैट से 50 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे।

अर्पिता फिलहाल अलीपुर महिला सुधार गृह में बंद है। माना जा रहा है कि वहां उससे पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ करने के लिए आयकर विभाग ने कोलकाता की विशेष ईडी अदालत में भी आवेदन किया है, उन्हें इजाजत भी मिल गई है। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप में 22 जुलाई 2022 को ईडी ने कोलकाता में पार्थ के घर पर छापेमारी की थी। लंबी तलाशी और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद ईडी ने अर्पिता के दो अन्य फ्लैट पर छापेमारी की, जहां से 50 करोड़ रुपये नकद, भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा और सोने के आभूषण बरामद हुए थे।

कोर्ट में रो पड़े टीएमसी विधायक मानिक भट्टाचार्य : शिक्षक भर्ती घोटला मामले में जेल में बंद तृणमूल विधायक मानिक भट्टाचार्य गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में जमानत मांगते समय में रो पड़े। उन्होंने कहा कि उनका जीवन समाप्त हो गया है। मानिक ने कहा कि 2016 में उनकी सर्जरी हुई थी। उस समय डाक्टरों ने कहा था कि वह अगले 10 साल तक जीवित रहेंगे। जस्टिस घोष ने ईडी से पूछा कि मानिक को जमानत क्यों नहीं दी जा सकती। शुक्रवार को इस मामले में फिर सुनवाई होगी।

ईडी ने एस बसु राय एंड कंपनी के दो कर्मचारियों से की पूछताछ : ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में एस बसु राय एंड कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी से प्रेसिडेंसी जेल जाकर पूछताछ की। एस बसु राय एंड कंपनी को भर्ती परीक्षा की उत्तर पुस्तिका यानी ओएमआर शीट देखने की जिम्मेदारी दी गई थी। आरोप है कि बड़े पैमाने पर ओएमआर शीट से छेड़छाड़ की गई थी।

मुझ पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ : अजीत पवार

राज्य ब्यूरो, मुंबई : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने द्वारा पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि उन पर लगने वाला भ्रष्टाचार का कोई आरोप अब तक सिद्ध नहीं हुआ है, न ही सिद्ध होगा। अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने ही विधानमंडल के मानसून सत्र में दो दिन पहले महाराष्ट्र सरकार का 2024-25 का बजट पेश किया। इस बजट में महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश की तर्ज पर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने की घोषणा की गई है।

लेकिन, विपक्षी दल अजीत पवार द्वारा पेश बजट की खामियां गिनाने से नहीं चूक रहे हैं। गुरुवार को एक वीडियो संदेश में अजीत पवार ने इन सभी आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों में मैंने कई योजनाएं शुरू कीं। कितनी नई पहलें कीं, इसकी लिस्ट लंबी है। फिर भी विपक्ष चिल्ला रहा है कि हमने कुछ नहीं किया।

हिमाचल की मांग, नाबार्ड से हो ई-बसों की फंडिंग, चाहिए 450 करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, जागरण ● शिमला

▸ हरित राज्य बनाने का है लक्ष्य, केंद्र सरकार से लगाई गुहार

▸ 2022 में रोप-वे निर्माण के लिए केंद्र ने नाबार्ड से की थी फंडिंग

प्रदेश सरकार ने 2026 तक हिमाचल को हरित राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए सरकार 300 से अधिक ई-बसों की खरीद करने जा रही है। प्रदेश ने वित्तीय संकट की स्थिति का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि ई-बसों की फंडिंग राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से करवाई जाए। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने वित्त मंत्रालय को अवगत करवाया है कि हिमाचल में 70 पंचायतों को रोप-वे सुविधा से जोड़ने के लिए 2022 में नाबार्ड से फंडिंग का प्रविधान हुआ था। तर्क दिया था कि सड़क निर्माण महंगा रहेगा और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते मुश्किल होगा। अब इसी तर्ज पर ई-बसों की फंडिंग करने का आग्रह किया गया है।

प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्तावित ई-बसों की खरीद के लिए 450 करोड़ रुपये चाहिए। नाबार्ड सामान्य तौर पर सड़क निर्माण, जल शक्ति विभाग की परियोजनाओं के लिए फंडिंग करता है। दो साल पूर्व पहली बार प्रदेश में रोप-वे निर्माण के लिए केंद्र ने नाबार्ड से फंडिंग करने की अनुमति प्रदान की। सड़क निर्माण में अधिक लागत की अपेक्षा रोप-वे पर आधी से कम लागत अनुमानित है। मुख्य सचिव का कहना है कि हिमाचल को हरित राज्य बनाने के लिए ई-वाहनों का उपयोग बढ़ाने की जरूरत है। प्रदेश सरकार अपने स्तर पर ई-बसें खरीदने में सक्षम नहीं है। ऐसे में केंद्रीय वित्त सचिव के समक्ष ई-बसों की खरीद के लिए नाबार्ड से ऋण के प्रविधान का मामला रखा है।

****

40 लाख रुपये के इनामी थे छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में दो दिन पहले मुठभेड़ में मारे गए पांच नक्सली। सभी पर आठ-आठ लाख रुपये का इनाम था।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 5 जुलाई, 2024

तीसरी व छठी की शेष पाठ्यपुस्तकें भी जल्द मिलेंगी

तैयारी ▸ एनसीईआरटी ने एनईपी के तहत तैयार होने वाली नई स्कूली पाठ्यपुस्तकों पर शिक्षा मंत्री को दी जानकारी

प्रधान ने नई पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने पर तेजी से काम करने व स्कूलों को समय से उपलब्ध कराने के भी दिए निर्देश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

धर्मेंद्र प्रधान। फाइल

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत स्कूलों के लिए तैयार होने वाली नई पाठ्यपुस्तकों की प्रगति की केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को समीक्षा की। इस दौरान एनसीईआरटी ने तीसरी और छठी कक्षा की बाकी बची आठ पाठ्यपुस्तकों को जल्द ही तैयार करने की जानकारी दी। साथ ही बताया कि तीसरी और छठी की अब तक नौ पाठ्यपुस्तकें तैयार हो चुकी हैं। जिन्हें स्कूलों को मुहैया कराया जा रहा है, बाकी पुस्तकों को तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। प्रधान ने एनसीईआरटी से बाकी पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने में तेजी लाने व समय से सभी पाठ्यपुस्तकों को स्कूलों को मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।

नई स्कूली पाठ्यपुस्तकों को लेकर बुलाई गई बैठक में प्रधान के साथ ही स्कूली शिक्षा सचिव संजय कुमार, एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी व सीबीएसई के अध्यक्ष सहित मंत्रालय के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। शिक्षा मंत्री प्रधान ने इस दौरान स्कूलों की तैयार होने वाली पाठ्यपुस्तकों की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही तीसरी और छठवीं कक्षा के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने की जानकारी ली। एनसीईआरटी ने बताया कि स्कूलों में नई पाठयपुस्तकों को लागू करने की तय योजना के तहत काम किया जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में तीसरी और छठवीं कक्षा की कुल 17 पाठ्य पुस्तकें तैयार की जानी थी। इनमें से अब तक नौ पाठ्यपुस्तकें तैयार कर ली गई है। जबकि बाकी आठ पाठ्य पुस्तकों को जल्द तैयार कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह नई पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने के साथ ही स्कूलों शिक्षकों को भी इन्हें पढ़ाने के लिए तैयार करें। उन्हें इसके लिए विशेष प्रशिक्षण अभियान शुरू किया जाए। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों से शिक्षकों के प्रशिक्षण के काम में तेजी लाने पर जोर दिया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में अगले दो साल के भीतर नई पाठ्यपुस्तकों को लागू किया जाना है। मौजूदा समय में इस पाठय पुस्तकों को तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है।

परीक्षा पर आनलाइन चर्चा से छात्रों से नजदीकी बढ़ाएगी मोदी सरकार

▸ **एनसीईआरटी ने 'परीक्षा पर चर्चा' के आनलाइन पोर्टल का रखा प्रस्ताव, छात्रों से परस्पर संवाद से लेकर 2डी/3डी सेल्फी का भी होगा इंतजाम**

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'परीक्षा पर चर्चा' सालाना कार्यक्रम को अब वर्चुअल प्लेटफार्म पर भी रचा जाएगा। 'परीक्षा पर चर्चा' का आनलाइन पोर्टल बनाने के एनसीईआरटी ने एक प्रस्ताव दिया है जिसमें पीएम मोदी के भाषणों के साथ ही छात्रों को परस्पर संवादात्मक अंदाज में उनके साथ 2डी/3डी मोड में सेल्फी लेने की भी सुविधा हो। मोदी सरकार 'परीक्षा पर चर्चा' के आनलाइन पोर्टल के जरिये छात्रों में अपनी पैठ बनाना चाहती है।

नेशनल काउंसिल फार एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) ने इस संबंध में इसी हफ्ते 'रुचि की अभिव्यक्ति' (ईओआइ) के दस्तावेज चयनित वेंडरों के समक्ष रखें हैं। ताकि 'परीक्षा पर चर्चा' की आनलाइन प्रदर्शनी का एक प्लेटफार्म विकसित किया जा सके। योजना के मुताबिक एक आनलाइन पोर्टल से दोतरफा संवाद स्थापित करने के लिए 2डी/3डी वातावरण तैयार किया जाएगा जिसमें यूजर जानकारी के आदान-प्रदान से लेकर सीधा संवाद स्थापित कर सकेगा। प्रस्ताव के अनुसार ऐसा पोर्टल तैयार करना है जिस पर सालाना कम से कम एक करोड़ विजिटर आ सकें। इसका उद्देश्य 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम को आनलाइन फारमैट में तैयार करना है। इस वर्चुअल प्रदर्शनी में एक एक्जीबिशन हाल, एक आडिटोरियम, एक सेल्फी जोन, क्विज जोन और एक नेता का पैनल होगा। डेडिकेटेड सेल्फी जोन का मतलब है कि यूजर छात्र पोर्टल पर पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने के साथ ही उसे वाल पर पोस्ट कर सकेगा या फिर डाउनलोड करके उसे इंटरनेट मीडिया पर जारी कर सकेगा। आडिटोरियम में पीएम और अन्य मंत्रियों के भाषण और संबोधन होंगे। साथ में वह चर्चाएं भी शामिल की जाएंगी जो छात्रों के लिए आवश्यक हैं।

वर्चुअल एक्जीबिशन हाल में बूथ होंगे जिसमें छात्रों की कला, कृतियों और वैज्ञानिक शोधों का प्रदर्शन होगा। प्रत्येक बूथ में छात्रों के 2डी/3डी अवतार होंगे। इसमें वह इसी फारमेट में चित्र व कलाकृतियां या कार्यक्रम की वीडियो रिकार्डिंग का प्रदर्शन कर सकेंगे। छात्रों का चयन आनलाइन प्रतियोगिता से होगा। उल्लेखनीय है कि यह कदम तब उठाया जा रहा है जब देश में परीक्षाओं की प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है।

लोकपाल की नियुक्ति न करने वाले 63 विश्वविद्यालय डिफाल्टर सूची में

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ **इन विश्वविद्यालयों में अकेले 46 राज्य विश्वविद्यालय, छह निजी और 11 मानद विश्वविद्यालय भी हैं शामिल**

▸ **शिकायतें सुनने को यूजीसी के नए नियमों के तहत सभी विश्वविद्यालयों को नियुक्त करना है लोकपाल**

छात्रों से जुड़ी शिकायतों पर गंभीर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अब तक लोकपाल की नियुक्ति न करने वाले 63 विश्वविद्यालयों के रवैए पर गंभीर नाराजगी जताई है। साथ ही सभी को नियमों का पालन न करने के चलते डिफाल्टर विश्वविद्यालयों की सूची में डाल दिया है। इनमें लगभग 46 राज्य विश्वविद्यालय, छह निजी विश्वविद्यालय और 11 मानद विश्वविद्यालय शामिल हैं।

यूजीसी ने इसके साथ ही सभी डिफाल्टर विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी कर नए नियमों के तहत जल्द लोकपाल की नियुक्ति करने सहित छात्रों से जुड़ी व्यवस्थाओं को जुटाने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालयों के रवैए को लेकर यूजीसी ने यह नाराजगी तब जताई है, जब उसके बार-बार निर्देश के बाद भी विश्वविद्यालयों ने छात्रों की शिकायतों से जुड़े नियमों को अपने यहां लागू नहीं किया। या फिर उसकी जानकारी नहीं दी। यूजीसी ने छात्रों की शिकायतों से जुड़े नए नियमों को 2023 में ही लागू किया था।

गौरतलब है कि छात्रों से जुड़े नए नियमों के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से लोकपाल की नियुक्ति करनी होगी। जहां संस्थान की ओर से गठित कमेटी की ओर से न्याय न मिलने पर लोकपाल के सामने उस फैसले को चुनौती दी जा सकेगी। लोकपाल के पद पर किसी रिटायर्ड जज, पूर्व कुलपति या प्रोफेसर को ही नियुक्ति किया जा सकता है। जो फीस, भेदभाव, रैंकिंग सहित छात्रों से जुड़े सभी मामले सुन सकेंगे।

डिफाल्टर की सूची में कर्नाटक, ओडिशा के सबसे अधिक विश्वविद्यालय

यूजीसी ने लोकपाल की नियुक्ति न करने के चलते देश के जिन 46 राज्य विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर की सूची में डाला है, उनमें सबसे अधिक आठ-आठ विश्वविद्यालय कर्नाटक और ओडिशा के हैं। इसके अतिरिक्त इस सूची में 17 अन्य राज्यों के भी विश्वविद्यालय शामिल हैं। यूजीसी के मुताबिक, इन सभी 63 विश्वविद्यालयों ने एक जुलाई तक लोकपाल की नियुक्ति करने की जानकारी नहीं दी है।

सैलाब को देख हर कोई था हैरान, पानी भरे खेतों में ही जमा लिया था डेरा

▸ **नेशनल हाईवे-91 से नजर आ रही थी भीड़ ही भीड़, हाईवे से वाहनों में गुजरे राहगीरों ने बनाए वीडियो, हादसे के बाद मदद की बजाय सेवादारों ने वर्दी उतारकर सामान्य कपड़े पहने और भाग गए**

दो जुलाई को हाथरस में सत्संग में विशाल संख्या में पहुंचे थे श्रद्धालु, जहां बाद में भगदड़ की घटना हुई। प्रेट्र

संतोष शर्मा ● जागरण

अलीगढ़ : हाथरस के सत्संग में जनसैलाब उमड़ पड़ा था। हर तरफ भीड़ थी। कार्यक्रम स्थल से लेकर आसपास के खेतों में बरसात का पानी भरा था, लेकिन बाबा के अनुयायी इससे जरा भी विचलित नहीं थे। उन्होंने पानी भरे खेतों में ही डेरा जमा लिया था। नेशनल हाईवे-91 पर कई जगह भंडारे की व्यवस्था की गई थी। इंटरनेट मीडिया पर कई वीडियो प्रसारित हो रहे हैं, जिसमें भीड़ और पानी भरे खेत दिख रहे हैं। भगदड़ के दौरान इनमें ही श्रद्धालु ऐसे फंसे कि निकलना मुश्किल हो गया। हादसे के बाद मदद की बजाय सेवादारों ने वर्दी उतारकर सामान्य कपड़े पहने और भाग गए।

हाथरस के फुलरई और मुगलगढ़ी गांव के पास 150 बीघा खेत में सत्संग के लिए व्यवस्था की गई थी। मैदान तो बड़ा था ही हाईवे होने के चलते अधिक भीड़ एकत्रित होने का मौका और मिल गया। जिस दिन हादसा हुआ, उससे पहले बरसात हुई थी। हादसे से पहले के इंटरनेट मीडिया पर कई वीडियो प्रसारित हो रहे हैं, जो भीड़ की भयावहता को दर्शा रहे हैं। प्रसारित हो रहे वीडियो को अलीगढ़ की ओर आ रही बस में सवार किसी यात्री ने बनाया है। वीडियो बनाने के दौरान यात्री भीड़ देखकर हैरान हैं। कह रहा है कि पता नहीं ये पब्लिक कहां से आई है? पानी भरे खेतों में शिविर लगाए हैं। इसी दौरान हाईवे पर खड़े सेवादार वीडियो बनाने का विरोध करते हैं।

हादसे के बाद हजारों की भीड़ हाईवे को पार कर खेत में पहुंच गई थी। इसका भी वीडियो प्रसारित हो रहा है। आसपास के मकानों से स्थानीयों ने वीडियो बनाए। इनमें जनसैलाब दिख रहा है। हाईवे पर यातायात एक ही दिशा में दिख रहा है। सेवादार लाठी लेकर यातायात को नियंत्रित करते दिखाई दे रहे हैं।

नहीं आने की अपील के बाद भी बागेश्वर धाम में हजारों उमड़े

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर

▸ **कथा वाचक धीरेंद्र शास्त्री ने की थी जन्मोत्सव पर न आने की अपील**

▸ **सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई जिलों का पुलिस बल लगाया गया**

उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे को देखते हुए कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री के जन्मोत्सव में शामिल न होने की अपील के बावजूद गुरुवार को बागेश्वर धाम पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। गुरुवार को चार जुलाई को पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी के जन्म दिवस पर धाम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसे में, बढ़ती भीड़ के कारण प्रशासन की मशक्कत बढ़ गई। अन्य जिलों से पुलिस बल बुलाकर तीन लेयर में सुरक्षा व्यवस्था करके भीड़ को नियंत्रित किया गया। बता दें, हाथरस हादसे में दो जुलाई को सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 121 की मौत हो गई थी। मामले की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है।

पिछले दो दिन से ही लोग बागेश्वर धाम पहुंच रहे थे। बुधवार को संगीत संध्या का कार्यक्रम था, वहीं गुरुवार को देश के विभिन्न स्थानों से संत और राजपीठ के सदस्य धाम में पहुंचे, इनमें ददरौआ धाम के महंत, अयोध्या से हनुमान गढ़ी के महंत, मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज भी शामिल हुए। गायक कीर्तिदान गढ़वी, शीतल पांडेय, मनोज तिवारी, अक्षरा सिंह की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुईं। हजारों लोगों को व्यवस्थित दर्शन दिलाकर उन्हें वहां से गंतव्य के लिए निकालना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहा।

अब रात में पैदल नहीं निकलेंगे संत प्रेमानंद महाराज

जागरण संवाददाता, वृंदावन (मथुरा) : श्री राधारानी के साधक और अपने प्रवचन से श्रद्धालुओं में अपनी अलग पहचान बनाने वाले संत प्रेमानंद महाराज अब रात में सड़क के रास्ते पदयात्रा करते हुए अपने श्रीराधा केलिकुंज आश्रम तक नहीं पहुंचेंगे। उनके दर्शन के लिए रात में आश्रम के रास्ते में सड़क किनारे हजारों श्रद्धालु खड़े रहते हैं। हाथरस के सत्संग में हुए हादसे के बाद संत प्रेमानंद के इस निर्णय की जानकारी आश्रम संचालकों ने दी है। प्रेमानंद महाराज ने हाथरस सत्संग में हुए हादसे में मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

साजिश कह असली मुद्दे से ध्यान हटाना चाहती है सरकार : अखिलेश

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ

हाथरस हादसे पर सपा अध्यक्ष का आरोप, सीएम व डिप्टी सीएम को घेरा

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि हाथरस में भगदड़ कोई साजिश नहीं थी। इसमें कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता है। राज्य सरकार असली मुद्दे से ध्यान हटाना चाहती है, किंतु वह अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। इस तरह का कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जगह-जगह ऐसे कार्यक्रम होते रहे हैं। कई बार आयोजकों को भी पता नहीं होता है कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे। यह जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है।

उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि हाथरस में यदि लोगों को समय पर उपचार मिल गया होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाल रहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर हमला बोला कि वह खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और आजकल इसी काम में दिन-रात लगे हैं। यही वजह है कि विभाग पर ध्यान देने के बजाय अपना राजनीतिक स्वास्थ्य बेहतर करने में जुटे हुए हैं। पता नहीं वह कौन सा राजनीतिक विटामिन चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बात को जानते हैं। इस कारण वह भी स्वास्थ्य विभाग के बजट में कटौती कर देते हैं। हाथरस की घटना के संदर्भ में उन्होंने कहा कि किसी पर आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। भाजपा के लोग इंटरनेट मीडिया पर कुछ तस्वीरें चलवा रहे हैं। भाजपा का यही काम है। इस लोकसभा चुनाव में तो उसे थोड़ी सीटें मिल गई हैं, अगली बार वह सभी सीटें हारेगी।

2008 से 2019 के बीच मृत्यु दर के आंकड़ों का अध्ययन

प्रथम पृष्ठ से आगे

अध्ययन में दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, शिमला 10 शहरों में पीएम 2.5 के संपर्क और वर्ष 2008 से 2019 के बीच मृत्यु दर की गणना के आंकड़ों का उपयोग किया गया। इन शहरों में प्रत्येक वर्ष होने वाली कुल मौतों में से 7.2 प्रतिशत (लगभग 33,000) पीएम-2.5 के कणों से जुड़ी हो सकती हैं। भारत से सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव, अशोका यूनिवर्सिटी व सेंटर फार क्रानिक डिजीज कंट्रोल, स्वीडन से कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट और अमेरिका से बोस्टन यूनिवर्सिटी एवं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी।

स्थिति में सुधार की जरूरत

- मौजूद वायु प्रदूषण नीति नान-अटेनमेंट सिटी ' पर केंद्रित है। यह शहरों को प्रदूषण से बचाने के लिए कारगर नहीं है। डब्ल्यूएचओ के मानक से अधिक प्रदूषण वाले शहरों के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।
- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जैसी नीतिगत तंत्र व क्रिया प्रणाली प्रदूषण की उच्चतम सीमा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्हें पूरे वर्ष कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

हज की खुशी मातम में बदली, हादसे में पिता, तीन बेटे सहित पांच की मौत

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद

▸ **मां-पिता को लेकर दिल्ली से लौट रहे थे स्वजन, डिवाइडर से टकरा बस से भिड़ी कार**

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार। जागरण

हज से लौटने की खुशी पल भर में मातम में बदल गई। दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर मूंढापांडे के पास कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन पर पहुंच गई। वहां रोडवेज बस से टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार हाजी और उनके तीन बेटों सहित पांच लोगों की मृत्यु हो गई। कार सवार सास और बहू घायल हैं। हाजी का छोटा बेटा आरिफ अन्य स्वजन के साथ दूसरी कार में पीछे था। उसने हादसा देखा, तो बेहोश होकर गिर गया। उसे भी चोट आई है।

उत्तर प्रदेश में रामपुर के गांव मुकरमपुर के अशरफ अली, पत्नी जैतून बेगम के साथ हज यात्रा पर गए थे। 40 दिन की इबादत कर दंपती बुधवार को दिल्ली लौटे। उनके बेटे नक्शे अली, आरिफ उर्फ महबूब अली, इंतेखाब अली, आसिफ अली और पुत्रवधू तबस्सुम व अन्य स्वजन दो कारों से उनको लेने दिल्ली गए थे। वहां से सभी गुरुवार सुबह लौट रहे थे। करीब आठ बजे आगे चल रही कार के चालक अहसान ने सामने पंक्चर वाहन को खड़ा देखकर ब्रेक लगाए। इससे कार डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद दूसरी लेन में जाकर सामने से आ रही रोडवेज बस से टकरा गई। हाजी अशरफ अली, इंतेखाब अली व चालक अहसान को रामपुर और बेटे नक्शे अली व आरिफ को गंभीर हालत में मुरादाबाद भेजा गया। पांचों की रास्ते में ही मौत हो गई। जैतून बेगम और पुत्रवधू की हालत गंभीर है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि चार मरने वाले एक ही परिवार के थे। रोडवेज बस का चालक फरार हो गया है।

महाराष्ट्र में आगनवाड़ी के भोजन के पैकेट में मिला मरा हुआ सांप, जांच शुरू

सांगली, प्रेट्र : महाराष्ट्र के सांगली जिला स्थित एक आंगनवाड़ी केंद्र के भोजन के पैकेट में छोटा मरा हुआ सांप पाए जाने से हड़कंप मच गया। मामला संज्ञान में आने के बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई है।

राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की उपाध्यक्ष आनंदी भोसले ने कहा कि घटना की सूचना सोमवार को एक बच्चे के माता-पिता ने दी। इसे बहुत ही गंभीर मामला बताते हुए कांग्रेस नेता और पलुस-कडेगांव विधायक विश्वजीत कदम ने मौजूदा मानसून सत्र में राज्य विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया।

अधिकारियों ने कहा है कि बच्चे के माता-पिता ने मृत सांप की तस्वीर लेने के बाद उसका निस्तारण कर दिया और उसकी फोटो को स्थानीय आंगनवाड़ी सेविका को भेज दिया। भोजन का नमूना एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। छह महीने से तीन साल की उम्र के बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से मध्याह्न भोजन के पैकेट दिए जा रहे हैं। ये पैकेट आंगनवाड़ी केंद्र में पहुंचने के बाद परिवारों को वितरित किए जाते हैं। सोमवार को भोजन के पैकेट वितरित किए गए थे।

पीडब्ल्यूडी और एनएचएआइ की लापरवाही से एक भी जान गई तो होगी कार्रवाई : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, शिमला

▸ **आदेश के बावजूद ब्यास नदी के बीच से चट्टानें न हटाने पर जताया दुख**

▸ **जून में कुछ नहीं किया, अब दिया जवाब-वर्षा में नहीं हो सकता काम**

प्रतीकात्मक

अगर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की लापरवाही से इस बार वर्षा के दौरान एक भी व्यक्ति की जान गई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने समय रहते राजमार्गों सहित जंगलों, नदियों और नालों का उचित रखरखाव न करने पर यह चेतावनी दी।

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा कि यह जानकर दुख होता है कि 12 जून, 2024 को हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के बावजूद ब्यास नदी के बीच से चट्टानों को अब तक नहीं हटाया गया है। इनसे टकराने से पानी का बहाव तट तक आ जाता है और सड़क को नुकसान पहुंचता है। जंगलों में फेंके मलबे से भूमि कटाव होता है और नदियों-नालों का बहाव रुक जाता है। यह एक सामान्य ज्ञान की बात है, इसलिए हर बार एनएचएआइ की ओर से स्थिति को स्टडी करने के बाद एक्शन में आने की बात समझ से परे है। कोर्ट ने मामले से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कहा कि उन्हें एनएचएआइ का नदी की स्थिति का अध्ययन करने के बाद यह कहना कतई स्वीकार्य नहीं है कि इस मानसून के दौरान नदी से बड़े पत्थरों को नहीं हटाया जा सकता है। एनएचएआइ के पास जून का पूरा महीना था, जब मानसून ने हिमाचल को नहीं छुआ था। उक्त अवधि में कुछ किया जा सकता था, लेकिन एनएचएआइ ने कुछ भी नहीं किया है।

अधिकारियों की निष्क्रियता से घटना घटी तो होगी कार्रवाई

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि एनएचएआइ की इस निष्क्रियता के कारण कोई अप्रिय घटना होती है तो अधिकारियों के विरुद्ध उचित निर्देश जारी किया जाएगा। मामले पर सुनवाई पहली अगस्त को निर्धारित की गई है। हाई कोर्ट ने 12 जून को प्रदेश सरकार को सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि एनएच के अलावा अन्य सड़कों की स्थिति अच्छी बनी रहे, ताकि नागरिकों को भोजन, ईंधन आदि की आवश्यक आपूर्ति बनाई रखी जा सके। एनएचएआइ को भी आदेश दिया था कि वह भी बरसात से पहले ब्यास नदी के बीच से चट्टानों को हटाए।

एनएचएआइ कार्यालय में छापा, पीडी के निजी सचिव समेत तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर

▸ **एनओसी के लिए 50 हजार लेते हुए पकड़ा, घर से 3.30 लाख रुपये मिले**

▸ **वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के डिप्टी मैनेजर, कार्यालय सहायक गिरफ्तार**

उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के पेट्रोल पंप आवंटी को एनओसी (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) देने के एवज में 1.50 लाख रुपये रिश्वत मांग रहे एनएचएआइ के परियोजना निदेशक (पीडी) के निजी सचिव बिजेंद्र सिंह को सीबीआइ ने 50 हजार रुपये रिश्वत लेते दबोच लिया। वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के डिप्टी मैनेजर जय प्रताप सिंह चौहान तथा कार्यालय सहायक मुकेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है।

सीबीआइ, लखनऊ की अलग-अलग टीमों ने बुधवार को गोरखपुर के एनएचएआइ कार्यालय के अलावा वाराणसी, लखनऊ में भी छापेमारी की। निजी सचिव के गोरखपुर, सहारा एस्टेट स्थित आवास से 3.30 लाख रुपये नकद, डायरी व अन्य दस्तावेज मिले। गुरुवार सुबह आरोपित को लेकर टीम लखनऊ रवाना हो गई।

कुशीनगर के रहने वाले भाजपा नेता धनंजय राय को लाटरी में पेट्रोल पंप का आवंटन हुआ है। नवंबर, 2023 में उन्होंने गोरखपुर के एनएचएआइ कार्यालय में एनओसी के लिए आवेदन किया। आरोप है कि पीडी का निजी सचिव बिजेंद्र सिंह एनओसी देने के लिए 1.50 लाख रुपये घूस मांग रहा था। उसका कहना था कि वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय तक रकम देनी पड़ती है। भागदौड़ के बाद भी काम न होने पर धनंजय राय ने एक जुलाई, 2024 को लखनऊ स्थित सीबीआइ कार्यालय में एसपी शिवानी तिवारी से शिकायत की थी।

महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ता को कहा ब्लैकमेलर, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मांगा आय का विवरण

जागरण संवाददाता, नैनीताल

▸ **महाधिवक्ता ने सीएम व मुख्य स्थायी अधिवक्ता को पक्षकार बनाने का किया विरोध**

कुछ विशेष मामलों में सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल काउंसिल बुलाने व राज्य सरकार की ओर से उन्हें प्रति सुनवाई लाखों रुपयों का भुगतान किए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने याचिका को निरस्त करने योग्य बताया। साथ ही मामले में मुख्यमंत्री व मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सीएससी) को पक्षकार बनाने का कड़ा विरोध किया। महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ता पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह आए दिन सरकार को ब्लैकमेल करता है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिकाकर्ता पर लगाए जा रहे आरोपों की पूरी रिपोर्ट 10 दिन के भीतर पेश करने को कहा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी 10 दिन के भीतर शपथपत्र देकर यह बताने को कहा है कि वह कितना आयकर देते हैं और अभी तक उनकी ओर से कितने सामाजिक कार्य किए गए हैं। कोर्ट ने मौखिक तौर पर याचिकाकर्ता से मासिक आय का विवरण आदि से संबंधित अन्य सवाल भी पूछे। मामले में अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता भुवन पोखरिया ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विपक्षियों को याचिका में इसलिए पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल काउंसिल नियुक्त करने के लिए न तो मुख्य सचिव और न ही न्याय विभाग से अनुमति ली गई है। स्पेशल काउंसिल नियुक्त कर उन्हें लाखों रुपये का भुगतान कर दिया गया। इसकी अनुमति शासनादेश नहीं देता, इसलिए इसकी जांच की जाए।

यहां तक कि विशेष काउंसिल नियुक्ति वाले मामलों में सरकार करीब 70 प्रतिशत केस हार गई। उनकी ओर से लगाए गए आरोप जांच योग्य हैं। साथ ही उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका प्रमाण वह पहले से ही कोर्ट में प्रस्तुत कर चुके हैं। अगर वह दोषी पाए जाते है तो उन्हें कोर्ट से ही जेल भेज दिए जाए। इधर, याचिकाकर्ता भुवन पोखरिया ने लिखित बयान जारी कर कहा है कि महाधिवक्ता की ओर से उन्हें खनन माफिया व खनन का ठेकेदार बताया गया है।

काफिला निकलते ही अनियंत्रित छोड़ दी भीड़

प्रथम पृष्ठ से आगे

आरोपितों का कहना है कि भीड़ नियंत्रण एवं सुरक्षा के लिए महिलाओं एवं पुरुष सेवादारों को विशेष ड्रेस दी जाती है। भीड़ नियंत्रण और व्यवस्था की जिम्मेदारी सेवादारों को सामूहिक रूप से दी जाती है। बाबा के अनुयायियों की मान्यता है कि चरण रज से बहुत सारे संकट दूर होते हैं। उस दिन भी भीड़ चरण रज लेने के लिए दौड़ी तो सेवादारों ने भीड़ को इसके लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की भी जानकारी मिली है। आपराधिक षड्यंत्र की भी जांच की जाएगी।

बाबा पर मुकदमे और गिरफ्तारी के सवाल पर आइजी शलभ माथुर बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा है कि अभी विवेचना चल रही है। हादसे के बाद बाबा को सेवादारों ने चार फोन किए और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। बाबा को पहला फोन दो जुलाई को दोपहर 2:48 बजे मधुकर के नंबर से किया गया। दोनों के बीच दो मिनट 17 सेकंड तक बात हुई। बाबा के फोन की लोकेशन तीन से 4:35 बजे तक मैनपुरी के आश्रम में थी। इस दौरान कुल तीन नंबरों से बाबा से बात की गई। इनमें पहला नंबर महेश चंद्र, दूसरा नंबर संजू यादव और तीसरा नंबर रंजना का है।

बाबा के वकील बोले-घटना की तह में जाना चाहिए पुलिस को : बाबा के वकील एपी सिंह ने हाथरस व अलीगढ़ जाकर घायलों का हाल जाना। बाबा कहां हैं, इस सवाल पर कुछ नहीं कहा। हालांकि, दावा किया कि जांच में बाबा सहयोग देंगे। दावा किया कि भीड़ में कुछ अराजकतत्व घुस आए, जिनके कारण भगदड़ मची।

न्यायिक आयोग ने शुरू किया काम : इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बृजेश कुमार श्रीवास्तव (द्वितीय) की अध्यक्षता में गठित न्यायिक जांच आयोग की पहली बैठक गुरुवार को लखनऊ में हुई। इसमें जांच के बिंदुओं पर विमर्श किए जाने के साथ ही कुछ औपचारिकताओं को पूरा किया गया। आयोग के दो दिनों में हाथरस पहुंचकर जांच शुरू करने की उम्मीद है।

****

30 विभिन्न देशों की 110 सुंदरियां गुरुवार को आगरा में ताजमहल देखने पहुंची। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्यटन पुलिस ने इंतजाम किया था।

न्यूज गैलरी

पीएम ने स्वामी विवेकानंद को पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को स्वामी विवेकानंद को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। स्वामी विवेकानंद का चार जुलाई 1902 को निधन हुआ था। एक्स पर पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, 'मैं स्वामी विवेकानंद को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी शिक्षाएं लोगों को ताकत देती हैं। हम एक समृद्ध और प्रगतिशील समाज के उनके सपने को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।' (प्रेट्र)

दीक्षा समारोह को संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति धनखड़

नई दिल्ली : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ छह और सात जुलाई को केरल के दौरे पर रहेंगे। उनके कार्यालय ने गुरुवार को बताया कि अपनी यात्रा के पहले दिन धनखड़ भारतीय अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइएसटी) के 12वें दीक्षा समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वह मेधावी छात्रों को उत्कृष्टता पदक प्रदान करेंगे। रविवार को उपराष्ट्रपति कोल्लम और अष्टमुदी बैकवाटर का दौरा करेंगे। (प्रेट्र)

केरल में दुर्लभ मस्तिष्कभक्षी अमीबा से किशोर की मौत

कोझिकोड : कोझिकोड के निजी अस्पताल में एक दुर्लभ मस्तिष्क संक्रमण अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस का इलाज करा रहे 14 वर्षीय किशोर की बुधवार रात 11:20 बजे मौत हो गई। दूषित पानी में पाए जाने वाले स्वतंत्र-जीवी अमीबा के कारण यह संक्रमण होता है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि केरल में इस घातक संक्रमण से हुई मौत का तीसरा मामला है। इससे पहले मई और जून में दो लड़कियों की मौत हो चुकी है। (प्रेट्र)

हत्यारोपित दर्शन की न्यायिक हिरासत 18 तक बढ़ाई

बेंगलुरु : बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को रेणुकास्वामी हत्या मामले में आरोपित अभिनेता दर्शन थूगुदीप और उनकी मित्र पवित्रा गौड़ा एवं अन्य की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ा दी। दर्शन और पवित्र समेत सभी 17 आरोपितों को बेंगलुरु एवं तुमकुरु जेल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित किया गया। अभिनेता के प्रशंसक रेणुकास्वामी ने गौड़ा को अश्लील संदेश भेजा था जिससे अभिनेता दर्शन भी क्रोधित हो गए थे। इसके बाद ही उसकी हत्या हुई। नौ जून को रेणुकास्वामी का शव पाया गया। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। (प्रेट्र)

दुष्कर्म का आरोपित 22 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा

पालघर : महाराष्ट्र के पालघर में 22 वर्ष से फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि दो जनवरी 2002 को माइकल उर्फ टीपू राम शिरोमण पांडेय समेत चार लोगों ने एक महिला का अपहरण करने के बाद नालासोपारा में दुष्कर्म किया था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि दो लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन माइकल और एक अन्य शंकर उस समय से फरार चल रहा था। माइकल उर्फ टीपू राम शिरोमण को गिरफ्तार कर लिया गया और शंकर की तलाश जारी है। (प्रेट्र)

केरल में अस्पताल के जेनरेटर के धुएं से कई बच्चे बीमार

कासरगोड़ : केरल के कासरगोड जिले में कन्हानगड़ में एक अस्पताल के जेनरेटर के धुएं से समीप स्थित स्कूल के बच्चे बीमार हो गए। सांस में धुआं जाने से असहज हुए बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जिले के कलेक्टर ने कन्हानगड सब-कलेक्टर को घटना की तत्काल जांच करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। लिटिल फ्लावर स्कूल में पढ़ने वाले 15 बच्चों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। (प्रेट्र)

बलिदानी के पिता बोले–सेना से 98 लाख मिल चुके

अग्निवीर अजय के पिता का यू-टर्न, पहले 48 लाख मिलने की बात कही, अब बोले– चेक नहीं किया था बैंक खाता

पीएम मोदी व राजनाथ की तारीफ की, बेटे के बलिदान पर राजनीति पर जताई आपत्ति

जागरण संवाददाता, खन्ना (लुधियाना)

जानकारी देते बलिदानी अजय के पिता चरणजीत सिंह। साथ में परिवार के अन्य सदस्य। जागरण

बलिदानी अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को मुआवजे को लेकर उनके पिता चरणजीत सिंह ने गुरुवार को यू-टर्न ले लिया। दो दिन पहले तक केवल 48 लाख रुपये मिलने की बात कह रहे चरणजीत अब सेना की ओर से 98 लाख रुपये मिलने की बात कह रहे हैं। चरणजीत सिंह ने कहा कि बैंक खाता चेक नहीं करने के कारण उन्हें गलतफहमी हो गई थी।

विदित हो कि 17 सिख लाइट इंफैंट्री के जवान 23 वर्षीय अजय सिंह जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के पोखरा में नियंत्रण रेखा के पास तैनात थे। 18 जनवरी, 2024 को फारवर्ड पोस्ट के पास बारूदी सुरंग विस्फोट में बलिदान हो गए थे। लुधियाना जिले के गांव रामगढ़ सरदारां निवासी चरणजीत सिंह ने कहा कि जनवरी में बेटे अजय के बलिदान होने के बाद फरवरी में ही 50 लाख रुपये आ गए थे। उन्हें इस राशि के बारे में जानकारी नहीं थी। 48 लाख रुपये सेना की तरफ से 10 जून को भेजे गए थे। इसके साथ ही एक लाख रुपये एक दिन पहले भी खाते में आए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में मामला उठाने के सवाल पर कहा कि बेशक राहुल राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वह परिवार की मदद भी करना चाहते हैं। कहा कि उनके बेटे के बलिदान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि वे अच्छा काम कर रहे हैं। उनके बेटे को सरकार की तरफ से बलिदानी का दर्जा मिले। एक बलिदानी के परिवार को मिलने वाली सारी सुविधाएं उन्हें मिलें, वह यही चाहते हैं।

सेना की तरफ से दिए जाएंगे 1.65 करोड़ रुपये

बता दें कि मामला गरमाने के बाद सेना ने भी बुधवार को एक्स पर पोस्ट कर स्थिति स्पष्ट की थी। सेना ने कहा था कि बलिदानी अजय के परिवार को कुल 1.65 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इनमें 98.39 लाख रुपये दिए जा चुके हैं और शेष राशि भी शीघ्र ही बलिदानी के परिवार को दी जाएगी।

लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान परिवार से मिले थे राहुल

लोकसभा चुनाव के दौरान आखिरी चरण में पंजाब में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी अचानक रामगढ़ सरदारां में बलिदानी अजय के घर पहुंचे थे। तब उन्होंने अजय के स्वजन को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया था। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना की निंदा करते हुए सरकार बनने पर इसे बंद करने की बात भी कही थी।

राहुल ने अग्निवीर के पिता का कथित वीडियो किया था साझा

राहुल गांधी ने बुधवार को कथित तौर पर अजय कुमार के पिता का एक वीड्यो एक्स पर साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है। राहुल ने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलिदानी अग्निवीरों के स्वजन को मुआवजे के मुद्दे पर संसद में झूठ बोला है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद सेना ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। अजय कुमार के स्वजन को 98.39 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। लगभग 67 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और अन्य लाभों का भुगतान पुलिस सत्यापन के तुरंत बाद अंतिम निपटान पर किया जाएगा। कुल राशि लगभग 1.65 करोड़ रुपये होगी।' सेना की पोस्ट को रि-पोस्ट करते हुए रक्षा मंत्री के कार्यालय ने भी कहा कि सेना अग्निवीरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

आगरा के वायुसेना परिसर में अग्निवीर ने गोली मार की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, आगरा : आगरा वायुसेना स्टेशन परिसर में तैनात अग्निवीर श्रीकांत चौधरी ने मंगलवार देर रात ड्यूटी के दौरान सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को बुधवार सुबह सात बजे वायुसेना स्टेशन की ओर से सूचना दी गई।

बलिया के 22 वर्षीय श्रीकांत चौधरी डेढ़ वर्ष पूर्व अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए थे। वर्तमान में आगरा वायुसेना परिसर में तैनात थे। मंगलवार रात श्रीकांत परिसर में ड्यूटी पर तैनात थे। रात लगभग डेढ़ बजे फायरिंग की आवाज सुनकर अन्य कर्मचारी दौड़े तो श्रीकांत के माथे में गोली लगी थी और सांसें थम चुकी थीं।

इंस्पेक्टर शाहगंज अमित मान सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह सात बजे अग्निवीर के आत्महत्या की जानकारी मिली। अग्निवीर ने राइफल से माथे के बीच में गोली मारी थी। स्वजन ने बताया कि श्रीकांत से एक दिन पहले ही बातचीत हुई थी। परिवार के लोगों से बातचीत में वह सामान्य लग रहे थे। कहीं से ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वह तनाव में थे। इंस्पेक्टर के अनुसार स्वजन शव को अंतिम संस्कार के लिए बुधवार शाम को बलिया लेकर चले गए थे।

इंडियन मुजाहिदीन का आंतकी गिरफ्तार, निशाने पर थे जवान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया • भोपाल

- मप्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई, लोन वुल्फ अटैक की थी योजना, कर रहा था रेकी

मध्य प्रदेश एटीएस ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई में खंडवा जिले से प्रतिबंधित संगठन- इंडियन मुजाहिदीन (आइएम) से जुड़े आतंकी फैजान को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पिस्टल, कारतूस और काफी जिहादी साहित्य बरामद किया गया है। फैजान के निशाने पर सुरक्षा बल के जवान थे। उसकी योजना लोन वुल्फ अटैक यानी अकेले ही हिंसक वारदात को अंजाम देने की थी। इसे अंजाम देने के लिए वह जवानों और उनके परिजनों की निगरानी व रेकी कर रहा था। आरोपित की पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है।

एटीएस के आइजी डा. आशीष ने गुरुवार को भोपाल पुलिस मुख्यालय में बताया कि इनपुट के आधार पर 34 वर्षीय आतंकी फैजान को खंडवा में सलूजा कालोनी के कंजर मोहल्ला स्थित उसके निवास पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। उससे बरामद मोबाइल फोन एवं डिजिटल डिवाइस में भी इंडियन मुजाहिदीन, आइएस, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा आदि आतंकी संगठन से संबंधित जेहादी साहित्य, वीडियो एवं फोटो प्राप्त हुए हैं। आतंकी के प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्यों से भी संपर्क था। उसके विरुद्ध धारा 13(1) (बी), 18, 20, 38 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का अपराध दर्ज किया गया है।

खुद को साबित करना चाहता था बड़ा मुजाहिद : फैजान लोन वुल्फ अटैक करके स्वयं को आइएम के यासीन भटकल एवं सिमी सरगना अबू फैजल की तरह बड़ा मुजाहिद साबित करना चाहता था। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उसके द्वारा स्थानीय अवैध हथियार कारोबारी तथा राज्य के बाहर के लोगों से संपर्क करके पिस्टल एवं कारतूस एकत्र किए जा रहे थे।

इंटरनेट मीडिया पर की थीं जिहादी पोस्ट

फैजान अपनी फेसबुक आइडी पर इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित जिहादी पोस्ट कर आइएम व आइएस की विचारधारा का प्रचार-प्रसार कर रहा था। इसके द्वारा पाकिस्तान में चल रहे मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंप की वीडियो, मसूद अजहर (जैश-ए-मोहम्मद) लश्कर-ए-तैयबा की तकरीर पोस्ट करते हुए कंधार विमान अपहरण की कहानी तथा मुल्ला उमर के बयान एवं अंसार गजवा-तुल-हिंद (एजीएच) से संबंधित पोस्ट इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे थे।

दहशत फैलाने को भूपतिनगर में किया गया था विस्फोट : एनआइए

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आरोपपत्र में छह लोगों को आरोपित बनाया
- दो दिसंबर, 2022 को हुए इस विस्फोट में तीन लोग मारे गए थे

बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के भूपतिनगर में हुए विस्फोट के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने गुरुवार को आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। 35 पन्नों के आरोपपत्र में एनआइए ने दावा किया है कि इलाके में दहशत फैलाने के लिए विस्फोट किया गया था, यह एक साजिश थी। भूपतिनगर में बम बनाये जा रहे थे। बता दें कि दो दिसंबर, 2022 को हुए इस विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई थी।

आरोपपत्र में बलाईचरण मैती और मनोब्रत जाना समेत छह लोगों को आरोपित बनाया गया है। उनमें से तीन की मौत हो गई।

दो दिसंबर, 2022 को भगवानपुर-2 ब्लाक के भूपतिनगर थाने के नायड़ाबिला गांव में रात करीब 11 बजे बम विस्फोट हुआ था। विस्फोट की इस घटना में तृणमूल बूथ अध्यक्ष, उनके भाई और एक अन्य की मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस इलाके में गई। पुलिस ने भी अपनी पहल पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बाद में कोर्ट के आदेश पर एनआइए ने पिछले साल जून में घटना की जांच अपने हाथ में ले ली।

इसी साल अप्रैल में घटना की जांच के दौरान एनआइए की जांच टीम पर हमला हुआ था। पूछताछ के लिए बलाईचरण और मनोब्रत को ले जाते समय ग्रामीणों ने केंद्रीय एजेंसी की गाड़ी को घेर लिया। वह बलाई और मनोब्रत को कार से उतारने की मांग करते रहे। इसके बाद एनआइए की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। घटना में एक अधिकारी घायल हुए थे।

अगले वर्ष अंतरिक्ष व गहरे समुद्र में पहला मानव मिशन भेजने की तैयारी

- गगनयान मिशन का लक्ष्य मानवयुक्त तीन दिवसीय मिशन अंतरिक्ष में भेजना है
- डीप-सी मिशन में तीन भारतीयों को हिंद महासागर में अभियान पर भेजा जाएगा

नई दिल्ली, आइएएनएस : केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत 2025 तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में पहले मानव मिशन को भेजने के लिए तैयार है। भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चार यात्रियों को चुना गया है। इनमें वायु सेना के ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं।

इसरो गगनयान मिशन का लक्ष्य मानवयुक्त तीन दिवसीय मिशन को अंतरिक्ष में भेजना है, जो पृथ्वी से 400 किमी ऊपर परिक्रमा करने के बाद वापस आएगा। वहीं, भारत का डीप-सी मिशन 2025 में तीन भारतीयों को लेकर गहरे समुद्र में जाएगा। समुद्रयान के रूप में जाना जाने वाला पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल मत्स्य 6000 पर हिंद महासागर में 6,000 मीटर की गहराई तक चालक दल मिशन भेजा जाएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष क्षेत्र में हालिया प्रगति पर भी प्रकाश डाला। जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2022 में हमारे पास केवल एक अंतरिक्ष स्टार्टअप था और 2024 में निजी भागीदारी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खोलने के बाद हमारे पास लगभग 200 स्टार्टअप हैं और उनमें से कई के पास वैश्विक क्षमता है। कुछ महीनों में ही अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र का 1,000 करोड़ का निवेश आया है।

जितेंद्र सिंह फाइल

गैंगस्टर एक्ट में अफजाल की सजा रद होगी या बढ़ेगी, आदेश सुरक्षित

विधि संवाददाता • जागरण

- विवेचक का बयान उल्लेखित कर बचाव पक्ष ने कार्रवाई को द्वेषवश बताया

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ सपा सांसद अफजाल अंसारी की अपील और इस सजा को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार तथा पीड़ित पीयूष राय की अपील पर सुनवाई पूरी कर ली है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने सपा सांसद के वकीलों की शेष बहस को सुनने के बाद मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है।

अफजाल अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी, डीएस मिश्र और उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने जो गैंग चार्ट बनाया है, उसमें कई सदस्य बनाए गए, लेकिन गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई केवल तीन लोगों पर की गई। ट्रायल कोर्ट में विवेचक के बयान से स्पष्ट है कि ऐसा राजनीतिक द्वेषवश किया गया। जिस मूल मुकदमे के आधार पर अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाई गई, उसमें बरी किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट ने अफजाल अंसारी को कम सजा सुनाई है। ऐसा आयु (70 वर्ष) तथा उनके दो बार सांसद एवं कई बार विधायक चुने जाने के दृष्टिगत किया है। कानून के मुताबिक ट्रायल कोर्ट को अभियुक्त की आयु उस समय की देखना चाहिए थी, जब अपराध हुआ था, तब उम्र 58 वर्ष थी। जिन पर देश का भविष्य बनाने का दायित्व है, वह ही अगर अपराध करें तो उन्हें अधिकतम दंड दिया जाना चाहिए था। दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय के अधिवक्ता सुदिष्ट कुमार ने सरकार की तरफ से प्रस्तुत तर्कों पर सहमति जताई थी।

अफजाल को गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। अफजाल ने इसे रद करने के लिए अपील दाखिल की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व में सजा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर स्थगनादेश देते हुए हाई कोर्ट को अपील का निस्तारण 30 जून तक करने का निर्देश दिया था।

मानसूनी वर्षा में कमी घटकर रह गई अब तीन प्रतिशत

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले कुछ दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश के कारण देश में कुल मानसूनी बारिश में कमी 11 प्रतिशत (30 जून तक) से घटकर बृहस्पतिवार को केवल तीन प्रतिशत रह गई है।

मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा की कमी 33 प्रतिशत से घटकर वीरवार को 14 प्रतिशत, मध्य भारत में 14 प्रतिशत से घटकर आठ प्रतिशत तथा पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में 13 प्रतिशत से घटकर दो प्रतिशत रह गई है। दक्षिण भारत में अब तक मानसून के दौरान अतिरिक्त बारिश (13 प्रतिशत) दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि देश के 24 प्रतिशत उपमंडल क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हुई। 45 प्रतिशत में सामान्य वर्षा हुई तथा 31 प्रतिशत में कम वर्षा हुई। एक जून को चार महीने का मानसूनी सीजन शुरू होने के बाद से देश में अब तक 190.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य बारिश 196.9 मिमी होती है।

उधर, असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। बाढ़ से 29 जिलों के साढ़े 16 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। प्रदेश में अधिकांश प्रमुख नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। असम के प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अब तक 17 जानवरों की डूबने से मौत हो चुकी है, जबकि 72 अन्य को बाढ़ के पानी से बचाया गया है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सब कुछ अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। प्रभावित लोगों को राहत प्रदान की जा रही है और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत के साथ-साथ बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

30 जून तक देश में मानसूनी वारिश में दर्ज की गई थी 11 प्रतिशत की कमी

प्रतीकात्मक

पहाड़ से मैदान तक भारी वर्षा का अलर्ट

जागरण टीम, नई दिल्ली

- उत्तराखंड में मानसून की बारिश बनी आफत, पहाड़ से मैदान तक दुश्वारियां
- पूर्वी उप्र में भारी बारिश, 40 से अधिक जिलों में वज्रपात का अलर्ट

देश के कई हिस्सों में झमाझम वर्षा के बाद धीमे पड़ गए मानसून के फिर जोर पकड़ने की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग ने पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के कुमाऊं में रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार टिहरी और पौड़ी जिलों के लिए आरेंज अलर्ट और उत्तरकाशी, चमोली व रुद्रपयाग जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। कहीं-कहीं हल्के से मध्यम भूस्खलन एवं चट्टान गिरने की आशंका है।

उत्तर प्रदेश में पिछले चार-पांच दिनों से रुक-रुककर लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को पूर्वी उप्र समेत 10 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है, जबकि 40 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बरसात होगी और वज्रपात की भी संभावना है। बिहार के उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ छिटपुट वर्षा की संभावना है। शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल में भारी वर्षा की चेतावनी है। गुरुवार को दिल्ली से सटे हरियाणा के अंबाला, नूंह, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फतेहाबाद और हिसार में जमकर वर्षा हुई।

लगातार वर्षा से उत्तराखंड में दुश्वारियां बढ़ गई हैं। चमोली में लामबगड़ नाले के उफान पर आने के कारण बदरीनाथ हाईवे करीब दो घंटे अवरुद्ध रहा। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में चीड़वासा नाले के उफान पर आने से अस्थाई पुलिया बह गई। इस दौरान दो कांवड़ यात्री भी बह गए। दोनों दिल्ली के बताए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ में निजी बाइक व कार से आदि कैलास गए 35 यात्री तीन दिन से तवाघाट में फंसे हैं।

जम्मू-कश्मीर की स्थिति थोड़ी अलग है। जम्मू में गुरुवार तड़के काफी बारिश हुई। शुक्रवार को भी वर्षा के आसार हैं। वहीं, कश्मीर के अधिकांश क्षेत्र जम्मू संभाग से अधिक तप रहे हैं।

स्वच्छता अभियान में कचरे के बदले दिया सोना, फिर आकर्षित होने लगे पर्यटक

कश्मीर के सैदीवारा का जनांदोलन, अभियान बन दक्षिण भारत में तेलंगाना तक पहुंचा

जागरण विशेष

नवीन नवाज • जागरण

सैदीवारा पंचायत के पूर्व सरपंच फारूक अहमद गनई और अन्य कूड़ा एकत्र करते हुए • स्वयं

श्रीनगर: दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित सैदीवारा कभी ट्रेकरों और सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र होता था। वेरीनाग जाने वाले पर्यटक भी यहां रुकना पंसद करते थे, लेकिन कचरे के फैलते ढेर ने जहां सैदीवारा से पर्यटकों को दूर कर दिया, वहीं स्थानीय लोगों को गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी बांटनी शुरू कर दी। ऐसे में चार वर्ष पूर्व तत्कालीन सरपंच फारूक अहमद गनई ने दूसरों को नसीहत देने से पहले खुद कचरा उठाने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने कचरा लाओ सोना ले जाओ नाम से एक अभियान भी शुरू किया था। यह अभियान जनांदोलन बना और आज दक्षिण कश्मीर की सैदीवारा पंचायत प्लास्टिक और कचरा मुक्त होकर एक बार फिर पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी है। यह जनांदोलन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य तक भी पहुंच गया है।

दैनिक जागरण से बातचीत में फारूक अहमद गनई ने कहा कि यह धरती हमारा आखिरी और असली बिछौना है। हम कैसे इसे कचरे का ढेर बना रहने दें। हमारे गांव के पास से झेलम की सहायक नदी गुजरती है, जो गंदा नाल बन गई थी। आज यह नदी सवाल करती है कि कोई मुझे साफ क्यों नहीं करता? इसलिए मैंने अभियान शुरू किया कि कचरा फेंके नहीं, उससे कमाएं। यही सोचकर मैंने पालिथीन का कचरा जमा करने वालों को सोने का सिक्का देने का फैसला किया। अब यहां कोई कचरा नहीं फैलाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी पंचायत इस प्रदेश की पहली पंचायत होगी, जहां हमने घर-घर से शुल्क जमा कर सफाई साथियों को तैनात किया।

एनजीओ सोशल रिकंस्ट्रक्शन सेंटर कश्मीर के संचालक एडवोकेट फारूक ने कहा कि कचरे से कमाई की प्रेरणा मुझे मेरी पत्नी से मिली। एक दिन मैं कचरा जमा कर रहा था तो मेरी बीबी ने मुझे गत्ता, लोहा और प्लास्टिक अलग-अलग करने को कहा। उसने कहा कि इसे कबाड़ी को बेचेंगे। मैंने यह बात अपने साथियों से की और कहा कि वह घर-घर जाकर बताएं कि कचरा फेंकने से पहले वह देखें कि किसे बेचा जा सकता है और किसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका भी हमें लाभ हुआ और लोग कचरे को घर में ही छांटने लगे।

क्या है पालिथीन लाओ-सोना पाओ योजना: पालिथीन लाओ-सोना पाओ, योजना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा प्लास्टिक का कचरा सबसे ज्यादा निकलता है और औरतों को अपने बच्चों के बाद सिर्फ सोना प्यारा होता है। मैंने इस विषय में जिला उपायुक्त से बातचीत की और उन्होंने कहा कि विचार अच्छा है। सात जनवरी को मैंने इस पर काम करना शुरू किया, शिविर आयोजित किए और अपने गांव के आसपास के एक किमी के इलाके में 10 जगह पर सफाई कराई। नदी को भी साफ किया। स्थानीय युवा क्लब, आकाफ समिति और मजहबी नेताओं को हमने इसमें जोड़ा। हमने 20 क्विंटल प्लास्टिक कचरा लाने वाले को सम्मानित करने व सोने का सिक्का देने का फैसला किया। सोने के सिक्के का वजन नहीं उसके पीछे की भावना ज्यादा अहम है। इसके अलावा हम पदक और ट्राफियां भी दे रहे हैं। सोने का पहला सिक्का हमारे ही गांव के शौकत हुसैन और दूसरा गवास पंचायत के पूर्व डिप्टी सरपंच शाहिद हुसैन को मिला है। हमने नकद पुरस्कार भी बांटे हैं।

पत्नी ने दिया सिक्के के लिए सोना

उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने जब सुना कि मैंने सोने का सिक्का देने का एलान किया है तो उसने ही पहले दो सिक्कों के लिए सोना मुझे दिया। शबनम फारूक ने कहा कि यह सोना मुझे तो हक-ए-मेहर के समय मेरे ही पति ने मुझे दिया है। वह अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। प्लास्टिक के कचरे को ठिकाने लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बालिंग मशीन सादीपोरा पंचायत को उपलब्ध कराई है। फारूक अहमद ने कहा कि हम एक ही जगह प्लास्टिक कचरा जमा करते हैं और उसे छांट कर उसके अलग-अलग बैग बनाकर, रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। इससे होने वाली कमाई गांव की भलाई पर ही खर्च होती है।

> मेरी पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राजनीतिक विचारधारा कहीं मेल नहीं खाती। इसके बावजूद आम लोगों के कल्याण के प्रति जो उनका जज्बा है। उससे ही मुझे यहां काम करने की प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आधुनिक भारत के सबसे बड़े सोशल इंजीनियर हैं।
> – **फारूक अहमद गनई**, पूर्व सरपंच

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

सलेम को तलोजा से नासिक जेल भेजा गया

राज्य ब्यूरो, जागरण, मुंबई : गैंगस्टर अबू सलेम को गुरुवार को भारी सुरक्षा के बीच तलोजा से नासिक जेल स्थानांतरित कर दिया गया। 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किए गए सलेम को 1993 के मुंबई के सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में उसकी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

अबू सलेम को नई मुंबई की तलोजा जेल के अति सुरक्षित बैरक में रखा गया था। उस बैरक की मरम्मत का काम होना है, इसलिए जेल प्रशासन ने उसे तलोजा जेल से नासिक केंद्रीय कारागर भेजने का निर्णय किया। इस स्थानांतरण के विरुद्ध अबू सलेम ने मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उसने कोर्ट से अपील की थी कि उसे तलोजा जेल की ही किसी अन्य बैरक में स्थानांतरित कर दिया जाए। बता दें तलोजा जेल में भी उस पर दो बार हमला हो चुका है। बुधवार को सलेम द्वारा दायर अपील को हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

****

दैनिक जागरण

समस्या को समझना उसके समाधान की पहली कड़ी है

झूठ का पर्दाफाश

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए सेना को आगे आकर यह स्पष्ट करना पड़ा कि उनके इस दावे में कोई दम नहीं कि बलिदानी अग्निवीर अजय सिंह के स्वजनों को किसी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं की गई है। हालांकि राहुल गांधी के इस झूठे दावे का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में उसी समय खंडन कर दिया था, जब उन्होंने कहा था कि अग्निवीरों के स्वजनों को किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाता, लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा और वह अपने झूठ पर अड़े रहे। राहुल गांधी ने अपने झूठ को सच की शक्ल देने के लिए ही अग्निवीर अजय सिंह के पिता के पुराने बयान का हवाला देते हुए इसी पर जोर दिया कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है। आखिरकार सेना को यह साफ करना पड़ा कि उनके परिवार वालों के बैंक खातों में इसी वर्ष फरवरी और जून में क्रमशः 50 और 48 लाख रुपये जमा करा दिए गए थे। होना तो यह चाहिए था कि रक्षा मंत्री के बयान के बाद इस प्रकरण पर राहुल गांधी कुछ कहने से पहले वस्तुस्थिति पता कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं समझी। हैरानी नहीं कि इसलिए न समझी हो, क्योंकि वह झूठ बोलने के आदी हो गए हैं। वह राफेल विमान सौदे को लेकर भी झूठ बोले थे। हालांकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने चेतने से इन्कार किया।

राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष भले ही बन गए हों, लेकिन वह इस पद की महत्ता समझने को तैयार नहीं। कायदे से देश को जानबूझकर गुमराह करने और साथ ही अग्निवीरों एवं उनके परिवार वालों का मनोबल गिराने की कोशिश पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यदि ऐसी कोई पहल होती है तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता यह दुष्प्रचार करते हुए आसमान सिर पर उठा लेंगे कि बोलने की आजादी पर हमला किया जा रहा है। यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जानबूझकर झूठ बोला जाएगा तो इससे लोकतंत्र के समक्ष गंभीर खतरे ही पैदा होंगे। अग्निपथ योजना में संशोधन-परिवर्तन की मांग समझ आती है- इसलिए और भी कि स्वयं रक्षा मंत्री इस योजना पर विचार करने की बात कह चुके हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उसे लेकर जानबूझकर झूठ फैलाया जाए और सेना की छवि खराब की जाए। दुर्भाग्य से राहुल गांधी ऐसा ही कर रहे हैं। अच्छा हो कि कोई उन्हें बताए कि रक्षा-सुरक्षा के मामले में झूठ की राजनीति का सहारा लेना गैर जिम्मेदारी की पराकाष्ठा है। यदि राजनीति के इस लोकतंत्रघाती चलन को रोका नहीं गया तो राहुल गांधी जैसे नेता संकीर्ण स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए छल-कपट और झूठ का सहारा लेने के मामले में किसी भी हद तक जा सकते हैं।

आर्थिक स्वावलंबन

उत्तराखंड राज्य निर्माण और फिर उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मातृशक्ति के उत्थान के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम सराहनीय हैं। राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, सहकारी समितियों में प्रबंध समिति सदस्यों एवं सभापति पदों पर 33 प्रतिशत आरक्षण, महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिये आजीविका विकास और लखपति दीदी जैसी योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। इसके साथ ही सरकार ने अब राज्य में एकल निराश्रित महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का निश्चय किया है। योजना के दायरे में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्तता, किन्नर और अपराध एवं एसिड हमलों से पीड़ित एकल निराश्रित महिलाओं को रखा गया है। महिलाओं के इस वर्ग को सामाजिक सुरक्षा के साथ ही उसके आर्थिक स्वावलंबन पर ध्यान केंद्रित किया जाना समय की मांग है। इसी कड़ी में गत वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की घोषणा की थी। इसके बाद योजना के क्रियान्वयन का खाका भी विभाग ने खींचा, लेकिन इसमें चयनित महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दिए जाने वाले ऋण में सब्सिडी समेत अन्य बिंदुओं को लेकर अड़चन भी आई। इसे देखते हुए मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई। अब उपसमिति ने इसके तमाम पहलुओं पर अध्ययन शुरू कर दिया है। साथ ही यह भी साफ किया है कि इसी वर्ष से राज्य में एकल निराश्रित महिलाओं के लिए यह योजना लागू की जाएगी। राज्य के सभी 95 विकासखंडों में एकल निराश्रित महिलाओं को योजना से लाभान्वित किया जाएगा। निश्चित रूप से यह बेहतर पहल है और इससे राज्य में चार लाख से ज्यादा एकल निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया जा सकेगा। सरकार को चाहिए कि वह योजना के सही ढंग से क्रियान्वयन के लिए गंभीरता से आगे बढ़े।

संसद के न चलने का खतरा

राहुल वर्मा

जनादेश का सुविधाजनक निहितार्थ दोनों पक्षों के बीच तकरार की वजह बनकर संसदीय गतिरोध को बढ़ाता दिख रहा है

लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य उभरा, उसकी अनुगूंज बीते दिनों संसद में भी सुनाई पड़ी। 18वीं लोकसभा गठन के बाद आयोजित संसद के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रत्युत्तर के बाद दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मूल रूप से नए लोकसभा सदस्यों की शपथ विधि और लोकसभा अध्यक्ष चुनाव के नाम रहा यह सत्र इस बात के संकेत भी दे गया कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार और तल्ख होती जाएगी। संसद में हुई इस गहमाहमी को दो नजरियों से देखा जा सकता है। एक इसका सकारात्मक पक्ष भी है और वह यह कि हालिया चुनाव के बाद विपक्षी दलों विशेषकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का संख्याबल बढ़ा है। इससे संसद में विपक्ष की आवाज मुखर हुई है, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए एक सकारात्मक संकेत कहा जा सकता है। पिछली दो लोकसभा में विपक्ष की स्थिति बहुत लचर थी। मुख्य विपक्षी दल को नेता-प्रतिपक्ष का पद हासिल करने की अर्हता जितनी सीटें भी नहीं मिलीं। इस दौरान विपक्ष हाशिये पर रहा और सरकार का पूरा दबदबा रहा।

संसद के बीते सत्र में तकरार के नकारात्मक पहलू अधिक हैं। इससे संसदीय लोकतंत्र पर आशंकाओं के बादल मंडराते दिख रहे हैं। इस तकरार के पीछे एक प्रमुख वजह यह भी है कि सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों ने हाल के संसदीय जनादेश के वास्तविक मर्म को नहीं समझा है। जहां भाजपा अपनी सीटें घटने एवं पूर्ण बहुमत न मिलने के बावजूद गठबंधन सरकार को अपनी पारंपरिक आक्रामक शैली में चलाने के संकेत दे रही है, वहीं विपक्ष को लगता है कि यदि उसने सरकार के साथ थोड़ी भी सहजता दिखाई तो चुनावों में उसे जो संजीवनी मिली है, उसका असर धीरे-धीरे जाता रहेगा। एक ओर भाजपा को यह लगता है कि उसकी अपेक्षा से कम सीटों के पीछे कुछ स्थानीय पहलू प्रभावी रहे और वह फिर से राष्ट्रीय विमर्श खड़ा करके अपनी राजनीतिक ताकत वापस हासिल कर लेगी। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों को लगता है कि उन्होंने सरकार का एक स्तंभ हिला दिया है और अगली बार थोड़ा अधिक जोर लगाकर वह उसे गिराकर सत्ता में वापसी भी कर लेंगे। जनादेश का यही सुविधाजनक निहितार्थ दोनों पक्षों के बीच तकरार की वजह बनकर संसदीय गतिरोध को बढ़ा रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष में तकरार बढ़ती दिखे तो उस पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। चूंकि केंद्र में अभी एक गठबंधन सरकार सत्ता में है अतः सहयोगी दलों को साधकर रखना उसके लिए बहुत आवश्यक है। गठबंधन सरकारों के दौर में सहयोगी दलों के साथ-साथ विपक्षी दलों के साथ समन्वय बनाना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कई मामलों पर सहमति बनानी पड़ती है। हालांकि दोनों पक्षों को देखकर लगता नहीं कि संसद में किसी प्रकार का राजनीतिक सौहार्द बनता दिखाई देगा।

अवधेश राजपूत

किसी भी लोकतंत्र को उस अवस्था में आदर्श कहा जा सकता है, जब सत्तापक्ष और विपक्ष राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए किसी साझा दृष्टिकोण पर सहमत हों। संभव है कि राजनीतिक मुद्दों पर सहमति न बन पाए, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, जिन्हें राजनीति से परे रखा जाना चाहिए। सुरक्षा बलों का विषय भी ऐसा ही एक क्षेत्र है, लेकिन पिछले कुछ समय से विशेष रूप से सेना में अग्निपथ योजना और किसी अग्निवीर के बलिदान होने की स्थिति में मुआवजे को लेकर सत्तापक्ष-विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। ऐसे ही एक मामले के तूल पकड़ने के बाद भारतीय सेना को औपचारिक रूप से स्पष्टीकरण तक देना पड़ गया। मुआवजे के साक्ष्य रखने पड़े। इस पर भी यह मामला रफा-दफा होता नहीं दिख रहा। राजनीति में विचारों की लड़ाई सामान्य मुद्दा है, लेकिन फिलहाल सत्तापक्ष और विपक्ष एक दूसरे को राजनीतिक विरोधी न मानकर शत्रु मान बैठे हैं। इसी कवायद में वे एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं कर रहे। जो विपक्षी सांसद संसद परिसर में संविधान की प्रतियां लहराने में लगे हुए हैं, क्या उन्होंने उसमें उल्लिखित मूल्यों को भी आत्मसात करने का कोई प्रयास किया है? इसी प्रकार हिंदुत्व को लेकर सत्ता पक्ष के एकाधिकार वाले आक्रामक रवैये का भी बहुत सकारात्मक संदेश नहीं जाता।

पहले टीवी और बाद में इंटरनेट मीडिया के आगमन ने भी संसद में बहस की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। ऐसा लगता है कि नेता अब किसी विषय पर संवाद करने के बजाय व्यक्तिगत हमलों से जुड़ी टीका-टिप्पणियों को प्राथमिकता देते हैं। संसद में उनकी उपस्थिति से आभास ही नहीं होता कि वे नीति-निर्माण के सर्वोच्च मंच पर अपनी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके बजाय उनके आचरण से यही अनुभूति होती है कि संसद में भी उनका चुनावी-मोड आन है और वे अपने मतदाताओं को संबोधित कर रहे हैं। सदन में आसन के निकट आकर हंगामा करना और तख्तियां लहराना ही मानो विपक्षी सांसदों का प्रिय शगल बन गया है। सत्तापक्ष के सांसद भी कम नहीं हैं। उनका ध्यान भी ऐसी राजनीतिक बयानबाजी में रहता है, जो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो सके। निजी और दलगत आस्था से जुड़े सांसदों के इस आचरण से व्यापक हितों की बलि चढ़ रही है।

अच्छी बात है कि अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर एवं सुदृढ़ बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद देश के समक्ष कायम चुनौतियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। देश में जाति, मजहब, क्षेत्र और समाज जैसी तमाम विभाजक रेखाओं के अलावा रोजगार एवं महंगाई जैसी तमाम शाश्वत समस्याएं भी हैं। इन सभी का समय रहते उपाय तलाशना बेहद जरूरी है। चूंकि संसद भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए नीति निर्माण की सबसे बड़ी इकाई है, इसलिए इस मोर्चे पर उसका दायित्व और बढ़ जाता है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में जिस प्रकार की स्थितियां आकार लेती दिख रही हैं उससे बहुत उम्मीद नहीं जगती।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो हैं)

response@jagran.com

अपेक्षाओं के अनुरूप आपराधिक कानून

आशुतोष पाण्डेय

न्याय प्रणाली की लेटलतीफी से जुड़ा 'तारीख पे तारीख' वाला जुमला अब इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली अब एक नए युग में प्रवेश कर गई है। इस प्रणाली के सभी तंत्रों जैसे कोर्ट, पुलिस, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कारागार और अभियोजन आदि का डिजिटलीकरण हो चुका है। इन्हें एक वृहद एकीकृत प्लेटफार्म से सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के लिए भी जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही ब्रिटिशकालीन आपराधिक कानूनों आइपीसी, सीआरपीसी एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में व्यापक परिवर्तन कर इन्हें वर्तमान की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया गया है। ये तीनों कानून यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने के बाद न्याय प्रणाली की लेटलतीफी पर कटाक्ष के रूप में बोला गया जुमला 'तारीख पे तारीख' आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ट्रायल के दौरान होने वाले विलंब को समाप्त करने का प्रविधान किया गया है। पुलिस द्वारा 60 एवं 90 दिन में न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित करने के उपरांत विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। सबसे पहले न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर अपराध का संज्ञान लिया जाता है। संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के 90 दिनों (जो 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है) के अंदर सेशन कोर्ट को सुपुर्द कर दिया जाएगा। यह समयबद्धता पूर्व में नहीं थी। सुपुर्द करने के पूर्व अभियुक्त के कोर्ट में प्रस्तुत होने के 14 दिनों के भीतर पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि दी जाएगी। पूर्व में यह समयबद्धता नहीं थी। ये प्रतिलिपियां अभियुक्तों को इलेक्ट्रानिक रूप में दी जा सकती हैं, जिसका पहले प्रविधान नहीं था। कोर्ट में ट्रायल प्रक्रिया आरोप तय करने से शुरू होती है। अब अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पर सुनवाई की पहली तारीख से 60 दिनों के भीतर आरोप तय किया जाएगा। ऐसी समय सीमा पहले नहीं थी। पहले कोर्ट में आरोप तय करने के समय अभियुक्त की उपस्थिति अनिवार्य थी, परंतु अब इलेक्ट्रानिक साधनों से अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया जा सकता है। इससे अभियुक्त को न्यायालय, विभिन्न जनपदों से न्यायालय लाने या उपस्थित करने की परेशानी समाप्त हो गई है। शातिर अपराधी तिकड़म भिड़ाकर आरोप तय होने की कार्यवाही को पूर्ण नहीं होने देते थे, क्योंकि आरोप तय होने पर ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। अपराधी आरोप तय होने की तिथि पर कोर्ट में नहीं उपस्थित होने के लिए अन्य मामलों में तिथि निश्चित कराकर दूसरे जनपदों में चले जाते थे। इससे लंबे समय तक आरोप तय नहीं हो पाता था। अब जहां ट्रायल शुरू नहीं होने देने के प्रयासों पर कुठाराघात हुआ है, वहीं त्वरित ट्रायल एवं प्रभावी अभियोजन की परिकल्पना साकार हुई है।

लागू हो गए नए आपराधिक कानून। प्रेट्र

आरोप तय होने से लेकर ट्रायल समाप्त होने तक वादी एवं साक्षियों का परीक्षण, क्रास इक्जामिनेशन और री-इक्जामिनेशन, अभियुक्त के बयान आदि की प्रक्रिया को सरल, त्वरित एवं प्रभावी बनाने के लिए इन सभी कार्यों को आडियो-वीडियो के माध्यम से कराने का प्रविधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किया गया है। इसमें न्यायालय में व्यक्ति इलेक्ट्रानिक माध्यम से भी उपस्थित हो सकता है। इलेक्ट्रानिक या डिजिटल रिकार्ड एवं वीडियो रिकार्डिंग को भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्राथमिक साक्ष्य माना गया है। नए कानून में इन इलेक्ट्रानिक्स रिकार्ड की ग्राह्यता एवं विधि मान्यता का प्रविधान किया गया है। न्यायिक प्रक्रियाओं को त्वरित बनाने के लिए समन या वारंट को इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजे जाने का भी नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रविधान किया गया है, जिससे कोर्ट द्वारा आदेश जारी होते ही संबंधित थाने में तत्काल पहुंच जाए और बिना विलंब के समन एवं वारंट तामील हो जाएं।

शातिर अपराधी फरार होकर भी न्यायिक प्रक्रिया को विलंबित करने में भरपूर जोर लगाते हैं। ऐसे अपराधियों की अनुपस्थिति में भी ट्रायल आरोप तय होने के 90 दिन के बाद शुरू करने एवं उस पर निर्णय देने का प्रविधान नए कानून में जोड़ा गया है। इससे फरार अभियुक्तों वाले मामलों में भी समयबद्धता के साथ निस्तारण में मदद मिलेगी। ऐसे भगोड़े अभियुक्तों के लिए संयुक्त रूप से ट्रायल किया जाएगा। सरकारी सेवकों के अभियोजन स्वीकृति के मामलों में भी अधिकतम 120 दिनों की समयसीमा निर्धारित की गई है, अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि अभियोजन स्वीकृति प्राप्त हो गई है। ट्रायल के त्वरित निस्तारण के लिए न्यायश्रुति नामक वीडियो कांफ्रेंसिंग ग्रिड विकसित किया गया है, जिस पर कोर्ट, कारागार, अभियोजन, पुलिस आदि संवाद कर सकते हैं। तलाशी, जब्ती (सर्च एवं सीजर) एवं घटनास्थल की वीडियोग्राफी के लिए ई-साक्ष्य मोबाइल एप विकसित किया गया है, जिससे साक्ष्यों को शीघ्र साबित कराया जा सकेगा। एक त्रिस्तरीय अभियोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, जिससे मामलों का त्वरित निपटान एवं निगरानी हो सके।

कोर्ट द्वारा ट्रायल के दौरान समस्त कार्यवाहियां एवं जिरह पूर्ण होने पर 30 दिनों के अंदर एवं अधिकतम 45 दिनों के अंदर निर्णय दिए जाने का प्रविधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किया गया है। निर्णय की प्रति को सात दिनों के अंदर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। निर्णय देने में भी समयबद्धता का प्रविधान किया गया है। आशा है कि विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाओं के अनुपालन में ये तीनों नए कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को जनता एवं नए युग की अपेक्षाओं के अनुरूप त्वरित, सरल, विश्वसनीय एवं प्रभावी बनाने में सफल होंगे।

(लेखक उत्तर प्रदेश आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन के विशेष अपराध अनुसंधान दल में अपर पुलिस महानिदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

दृष्टिकोण

जैसे-जैसे मनुष्य का सोच विकसित हुआ वैसे-वैसे उसकी दृष्टि ने व्यापक स्वप्न देखे और उन्हें साकार भी किया। यह मनुष्य की अद्भुत क्षमताओं को दर्शाता है, किंतु ऐसा कुछ ही मनुष्य कर पाते हैं, तो क्या इसके पीछे भाग्य की बड़ी भूमिका है? क्या इसको लेकर उनकी नियति पहले से ही तय होती है या उनके अंदर कोई विशिष्ट गुण होता है?

मनुष्य का दृष्टिकोण उन्हें विशिष्ट बनाता है। परिस्थितियों को देखने की उनकी सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टि बड़ा अंतर पैदा करती है। अगर किसी सामान्य मनुष्य के जीवन में भगवान श्रीराम सी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो अधिकतम व्यक्ति अपना धैर्य खो देंगे, जीवन को लेकर विश्वास खो देंगे और फिर निराशा से घिर जाएंगे। वह भगवान श्रीराम का कठिन परिस्थितियों को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण ही रहा जिसने सामान्य मनुष्य की क्षमताओं के साथ बिना किसी चमत्कार के उनकी जीत सुनिश्चित की। विशिष्ट व्यक्ति भी किसी परिस्थिति में हारा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन वे अपने दृष्टिकोण और विश्वास से हार को भी अपनी जीत में बदल लेते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि आपके विश्वास आपके विचार बनते हैं, आपके विचार आपके शब्द बनते हैं, आपके शब्द आपके कर्म बनते हैं, आपके कर्म आपकी आदतें बनती हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बनते हैं और आपके मूल्य आपकी नियति बनते हैं।

इस प्रकार, जीवन या प्रकृति आपके समक्ष जो भी परिस्थिति लाती है, आप उसका किस दृष्टिकोण और विश्वास के साथ सामना करते हैं सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। सकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद आपका नकारात्मक रवैया आपको निराश करने वाला परिणाम देगा, जबकि नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद आपका सकारात्मक रवैया आपकी हार को भी जीत में बदल देगा।

लवली आनंद

रोकनी होगी रैगिंग की बर्बरता

डा. मोनिका शर्मा

स्कूलों से लेकर व्यावसायिक कालेजों तक में रैगिंग की बेहूदा घटनाओं का जारी होना दुर्भाग्यपूर्ण है

नए सत्र में परिचय और वरिष्ठता की हनक दिखाने के नाम पर रैगिंग की भयावह परंपरा हर साल अनगिनत विद्यार्थी के लिए मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न का कारण बन रही है। गत दिनों राजस्थान के डुंगरपुर में स्थित मेडिकल कालेज के एमबीबीएस प्रथम वर्ष के एक छात्र को भयावह रैगिंग के कारण किडनी संक्रमण हो गया। रैगिंग के दौरान द्वितीय वर्ष के सात छात्रों ने पीड़ित विद्यार्थी से चिलचिलाती धूप में 350 बार उठक-बैठक कराई थी। ऐसे वाकये भावी प्रतिभाओं को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को आघात पहुंचाने वाले हैं। जाने यह कैसा दुर्भाग्यपूर्ण सालाना रिवाज है कि देश के हर हिस्से में स्कूल-कालेज आए नए बच्चे भय और चिंता झेलने को विवश रहते हैं। जबकि ऐसे किसी दस्तूर की जरूरत ही क्या है? भविष्य बनाने के नए पड़ाव पर संस्थान के अपरिचित परिवेश में पहले ही भय से जूझ रहे छात्रों का मनोबल तोड़ना कहां तक उचित है?

कैसी विडंबना है कि छात्रों को निर्वस्त्र करना, यौन उत्पीड़न, घृणित स्तर का मजाक, अपशब्द कहना और जबरन नशा करवाना तक अब रैगिंग का हिस्सा बन गए हैं। जीवन तक छीन लेने वाले इस बर्बर बर्ताव में सीनियर छात्र अपनी हनक दिखने के नाम पर निम्नतम स्तर की विकृत मानसिकता का परिचय देते हैं, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कितने ही छात्रों के भविष्य निर्माण में बाधक बन रही है। दुखद है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासित व्यवहार अपनाने के बजाय वरिष्ठ छात्र ऐसा अमानवीय और अनुशासनहीन व्यवहार कर अपना दबदबा बनाने की कोशिश में इंसानियत ही भूल जाते हैं। यह बर्ताव पीड़ित बच्चों के मानवाधिकारों का हनन भी है जिसमें बिना किसी अपराध के कनिष्ठ विद्यार्थी प्रताड़ित किए जाते हैं। यह विद्यार्थियों में अपराध एवं प्रतिशोध की भावना पैदा करती है। नतीजतन आगे चलकर वे भी छात्र-छात्राओं को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से नहीं चूकते।

ध्यातव्य है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2001 से ही रैगिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इतना ही नहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी कई नियम लागू किए गए हैं। यूजीसी ने कालेजों में रैगिंग रोकने के लिए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लिखे पत्र में कहा था कि प्रास्पेक्टस में रैगिंग रोकने के नियमों और उससे जुड़े कानूनों को भी प्रकाशित करवाएं। इतना ही नहीं कुछ साल पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी स्कूलों में रैगिंग के बढ़ते मामलों और खतरों को देखते हुए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए थे। बावजूद इसके ऐसी बर्बर घटनाओं का होना जारी है। ऐसे में इन मामलों में लिप्त विद्यार्थियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी आवश्यक है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

नहीं बदला माननीयों का आचरण

'संसद की गरिमा बचाने की कठिन चुनौती' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में गिरीश्वर मिश्र ने सही लिखा है कि बीते कुछ समय से सड़क पर राजनीतिक दमखम दिखाने वाले नजारे संसद के दोनों सदनों में भी दिखने लगे हैं। देखा जाए तो आज यह देश के समक्ष एक अत्यंत गंभीर मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में जाने से लोगों के मन में एक नई आशा की किरण जगी थी, लेकिन अफसोस कि सिर्फ संसद का भवन बदला, माननीयों का आचरण नहीं। देश की जनता ने सांसदों को जिन जिम्मेदारियों और उम्मीदों के साथ जिताकर लोकतंत्र के मंदिर में भेजा, क्या माननीय सांसद अपने आचरण से उस मंदिर की गरिमा को बढ़ा रहे हैं? क्या संविधान और देश की जनता माननीयों से ऐसे ही आचरण की अपेक्षा रखती है? अभिव्यक्ति की आजादी के तहत क्या सिर्फ एकालाप करने की आजादी होती है? क्या विमर्श का यही तरीका होता है कि दूसरे पक्ष को न ही सुनना है और न ही बोलने देना है? क्या तथाकथित 'लोकतंत्र की रक्षा' करने का यही उचित तरीका है? आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? किसी की अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाएं वहीं तक होती हैं जहां तक कि वह किसी अन्य की अभिव्यक्ति की आजादी का अतिक्रमण न करने लगे। यह बात सभी माननीय सांसदों को समझनी होगी। इस संदर्भ में कुछ कठोर नियम और कानून बनाने और उनको कड़ाई से लागू करवाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

क्षितिज उपाध्याय, नेवादा, जौनपुर

मेलबाक्स

परीक्षा प्रणाली में हो व्यापक परिवर्तन

'केवल कठोर कानून पर्याप्त नहीं' शीर्षक से लिखे आलेख में प्रो. कपिल कपूर ने जिन तीन-चार बिंदुओं पर ध्यानाकर्षण करवाया है उनमें सबसे प्रमुख है कि इतनी बड़ी परीक्षाओं का आयोजन किसी एक संस्था द्वारा किए जाने से गड़बड़ी की संभावना अधिक रहती है। यद्यपि ऐसी गड़बड़ी उन प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं में भी सामने आते रहती है जिनका आयोजन राज्यों के अधीन होता है। लिहाजा उनके प्रमुख सुझावों में से अमल में लाने लायक जो बातें हैं वे हैं कि ऐसे नेटवर्क पर कार्रवाइयों में निरंतरता बनी रहे, जो परीक्षा में ऐसी गड़बड़ी करने के लिए विशेष तंत्र विकसित कर चुके हैं। फिर जाने-अनजाने ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलने से उनका मनोबल बढ़ता है। ऐसे में जरूरत है भर्ती या प्रवेश परीक्षा के आयोजन करने वाले संस्थान का अपना खुद का तंत्र हो और उसमें कार्यरत लोगों की योग्यता एवं ईमानदारी का भी खास महत्व है। मगर ऐसे लोगों की नियुक्ति की जिम्मेदारी राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन है। सबसे अहम है कि पहले भी इस तरह की भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाएं होती थीं मगर तब इतनी गड़बड़ियां नहीं होती थीं। अब इतनी गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं, यह व्यापक बदलाव की तरफ संकेत कर रही है। जो इस गड़बड़ियों के प्रेरक तत्व हैं उन्हें जड़ से मिटाने की जरूरत है।

मुकेश कुमार मनन, पटना

झूठ की राजनीति

आज संसद से लेकर सड़क तक नेताओं की किस बात पर कितना विश्वास किया जाए इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है राजनीति में वे दिन लद गए जब नेता सच्चाई और अपनी सच्ची बात के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। आज तो केवल थोड़े से राजनीतिक फायदे या सत्ता के लिए हर झूठ को नेता पचा जाते हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ वे झूठ को बयां करते हैं ऐसे में जनता भी कई बार असमंजस में रहती है कि ये बात सच है या झूठ। नेताओं की कथनी और करनी अलग-अलग हो चुकी है। आज राजनीति में छोटी-बड़ी सभी चर्चाओं में सभी अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए हजारों झूठ बोल जाते हैं। झूठ को भी वे सच के रूप में स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे में जनता भी असमंजस की स्थिति में रहती है कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है? आज यह जरूरी है कि झूठ की राजनीति के मजबूत होते पैरों को रोका जाए।

हरीश कुमार शर्मा, डोहर खुर्द

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

आजकल

कम समय में अधिक वर्षा का बढ़ता पैटर्न

पिछले लगभग एक माह हीटवेव से परेशान और मानसून का इंतजार करने वाले लोग अचानक उसके आगमन से कुछ सहमे हुए भी दिखते हैं। वस्तुत: पिछले कुछ वर्षों से मानसून के दौरान कई जगहों पर वर्षा दिवसों में कमी तो कुछ जगहों पर इनकी संख्या अपेक्षा से बहुत अधिक हो गई है। बारिश का कहीं कम या ज्यादा होना पहले भी होता रहा है, परंतु कम समय में अत्यधिक वर्षा एक नया मौसमी चलन है, जो हमारे लिए नई चिंता का विषय है

संजय श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार

कम समय में अपेक्षाकृत अधिक बारिश होने की बढ़ती प्राकृतिक घटना से अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हैं सामने। फाइल

लंबे समय से गर्मी से त्रस्त जनता को मानसून के आने से राहत मिली है। परंतु वर्षा संबंधी आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि देश के अधिकांश क्षेत्रों में पूरे साल की बारिश एक दिन एक सप्ताह या कुछ घंटों में हो जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बारिश का पैटर्न बदलने का कारण क्या है? क्या यह मानव निर्मित है और उसके द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है या मानवीय नियंत्रण से बाहर पूर्णतया प्राकृतिक प्रक्रिया है? अतिवृष्टि से सबसे ज्यादा सामान्यजन ही प्रभावित होते हैं, लेकिन वे अलनीनो प्रभाव, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, मानसून टर्फ, आरोग्राफिक लिफ्टिंग जैसे तमाम तकनीकी कारकों को नहीं जानते है, न उसकी तह में जाना चाहते हैं। जागरूकता के अभाव में उनके लिए यह बस मौसम की मर्जी है।

अनियमित मानसून पैटर्न : जलवायु विज्ञानियों का दावा है कि आगे से वर्षा ऋतु में भारी वर्षा वाले दिन ज्यादा होंगे और इसका दौर साल दर साल बढ़ता जाएगा। ऐसे में इस अचानक और भारी वर्षा के पीछे क्या कारक हैं, उसके संभावित निवारक तत्व क्या हो सकते हैं और उससे उपजने वाली समस्याओं के खिलाफ भविष्य में क्या तैयारियां अपेक्षित हैं? जानना जरूरी होगा और सरकार तथा आमजन दोनों को अपने कार्य व्यवहार के लिए उसके अनुरूप छोटे तथा दीर्घावधि वाले लक्ष्य तय करने होंगे। क्लाइमेट चेंज पर अंतर-सरकारी पैनल की रिपोर्ट कहती है कि 1950 के बाद से संसारभर में भारी वर्षा की घटनाएं बढ़ी हैं। एक अध्ययन बताता है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान पिछले 10 वर्षों में देश के 55 प्रतिशत हिस्से में बारिश में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि 11 प्रतिशत क्षेत्र में बारिश में कमी आई है। पर्यावरणविदों के अनुसार, कम समय में अधिक बारिश होने की अधिकांश वजहें मानव-जनित जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई हैं, जिनके चलते भारी वर्षा के मुख्य कारण वातावरण में नमी की मात्रा और वायुमंडलीय तापमान प्रभावित होता है, ज्यादा नमी और ठंडे वायुमंडलीय तापमान का मतलब है, भारी बारिश।

नासा ने दो वर्ष पहले कहा था कि धरती के तापमान में हर एक डिग्री की बढ़त वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा लगभग सात प्रतिशत बढ़ाता है। इससे थोड़े समय में भारी बारिश की आशंका बढ़ती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार वर्ष 1901-2018 के दौरान देश में सतह की हवा का तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जिसके चलते वायुमंडलीय नमी में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 1951-2015 के दौरान हिंद महासागर में समुद्री सतह का तापमान एक डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है, बीते बरसों से समुद्री सतह के तापपान में तेज बढ़त जारी है। पहले मानसून के दौरान इसका तापमान गिरता था, लेकिन अब नहीं। सो ये असामान्य ताप वृद्धि नमी में बढ़ोतरी कर मानसून का नियमित पैटर्न बिगाड़ देती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लोबल वार्मिंग के चलते वायुमंडल की नमी बढ़ती है, इस नम हवा को पहाड़ियां रोकती और उठाती हैं, इस आरोग्राफिक लिफ्टिंग के कारण पर्वतों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी तबाही आती है। इसके अलावा जब ठंडी हवा वातावरण में ऊपर की तरफ जाती है, तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बनती है और ज्यादा बारिश होती है। इसी तरह मानसून के दौरान कम दबाव वाले क्षेत्र में इकट्ठा हुई हवाएं मानसून टर्फ बना लेती हैं, पश्चिमी विक्षोभ से यह मानसून टर्फ टकराता है तो भीषण वर्षा होती है।

अनियोजित विकास : तापमान और नमी में वृद्धि के साथ-साथ अचानक भारी वर्षा का दौर बढ़ने वाला है। हमारा नियंत्रण इससे संबंधित बहुत सी परिस्थितियों पर नहीं है। परंतु जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और इनकी वजह से गड़बड़ाए वर्षा के पैटर्न के दुष्प्रभावों, समस्याओं से निपटने के उपाय हम अवश्य कर सकते हैं। बरसों अनियोजित विकास ने बारिश से होने वाली आपदा को रोकने वाली जिन प्राकृतिक सुरक्षा को नष्ट कर दिया है, हमें उन्हें पुनर्जीवित करना होगा। व्यापक बाढ़ और सूखे जैसी खतरनाक परिस्थितियों के शिकार होने से पहले नेतृत्व को सचेत होना होगा और देश को अपना हरितक्षेत्र बढ़ाने, हरित ईंधन पर जोर देने के साथ उन सभी पर्यावरणीय नियमों, उपायों को अपनाना होगा, जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके और धरती का ताप न बढ़े। बेशक इसमें सरकार की सक्रियता, सदिच्छा जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है। जलवायु पैटर्न को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए सरकार को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना को पूरी ईमानदारी से लागू करना होगा।

मौसम विभाग को मौसम संबंधी पूर्वानुमानों की सटीकता, विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अधिक अवलोकन केंद्र स्थापित करने होंगे, अधिक संसाधनों में बड़ा निवेश करना होगा। संचार चैनलों को बढ़ावा देकर प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को सशक्त, समुदाय-आधारित और सर्वग्राही बनाना होगा। मानवीय प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के अलावा कुछ पर्यावरणीय कानून भी लाने होंगे। मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश करना होगा। टिकाऊ शहरी डिजाइन अवधारणाओं के तहत शहरी नियोजन को नए सिरे से देखना और भूमि उपयोग प्रबंधन के सुविचारित नियम बनाना भी आवश्यक होगा, जैसे उन क्षेत्रों को निर्माण से अलग रखना जहां बाढ़ आ सकती है या वर्षा का जल इकट्ठा होता है। नष्ट होती जा रही प्रभावी प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों की पुनर्स्थापना करनी होगी। समस्या का पानी सिर के ऊपर से गुजरे इससे पहले सरकार को सचेत होकर विकास के नाम पर वातावरण की उपेक्षा करने की बजाय इस आसन्न समस्या पर गंभीरता से विमर्श कर समाधान के व्यावहारिक उपाय तलाशना चाहिए। (ईआरसी)

हरित क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिए अभियान

ज्ञानेंद्र रावत
पर्यावरणविद

समूचे विश्व में जिस तेजी से वृक्षों की संख्या कम होती जा रही है। इससे पर्यावरण तो प्रभावित हो ही रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, कृषि और मानवीय जीवन के अलावा भूमि की दीर्घकालिक स्थिरता पर भी भीषण खतरा पैदा हो गया है। जंगलों की क्षय होती स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वह दिन दूर नहीं, जब दुनिया से जंगलों का नामोनिशान मिट सकता है। विश्वभर के विज्ञानी बार-बार इस बारे में चेतावनी दे रहे हैं कि इंसान जैवविविधता को समाप्त करने पर तुला हुआ है। जबकि जैवविविधता का संरक्षण ही हमें बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निबाहता है। इसीलिए जैवविविधता का संरक्षण बेहद जरूरी है। वनों की कटाई पर यदि पर्याप्त अंकुश नहीं लगाया गया तो प्रकृति की लय बिगड़ जाएगी और उस स्थिति में वैश्विक स्तर पर तापमान में दो डिग्री की वृद्धि को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सूखा और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम से आर्थिक हालात और भी प्रभावित होंगे जिसकी भरपाई आसान नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह कि वृक्षों का होना हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह हमें गर्मी से राहत प्रदान करता है और जैवविविधता को बनाए रखने, कृषि की स्थिरता सुदृढ़ करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और जलवायु को स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह सब जानते-समझते हुए भी हम वृक्षों का संरक्षण क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यह समझ से परे है।

वस्तुतः आज जो देश-दुनिया की स्थिति है, वह सब मानव के लोभ का परिणाम है। अपने सुख-संसाधनों की अंधी चाहत में मनुष्य ने प्रकृति से इतनी छेड़छाड़ की है जिसका दुष्परिणाम हमारे सामने मौसम में आए भीषण बदलाव के रूप में आया। इससे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र समेत आर्थिक-सामाजिक ढांचा चरमरा गया है। यह बदलाव अचानक नहीं आया है। इस बारे में बीते कई बरसों से दुनिया के विज्ञानी, पर्यावरणविद और जीवविज्ञानी चेता रहे हैं। लंबे समय से वे हमें इस बारे में आगाह कर रहे हैं। यदि देश के हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ही बात करें तो यहां बीते लगभग एक दशक के दौरान ढाई लाख से अधिक वृक्ष काट दिए गए हैं। अनेक विकास परियोजनाओं के नाम पर ऐसा हुआ है। उत्तराखंड तो एक उदाहरण है, जबकि विकास के नाम पर पेड़ों के काटने का सिलसिला पूरे देश में जारी है। दुखदाई स्थिति यह है कि जिस गति से पेड़ों का अस्तित्व मिटाया जा रहा है, उसके अनुपात में पेड़ों के लगाने के दावे तो किए जा रहे हैं, परंतु वास्तविकता इसके उलट है। इतना ही नहीं, वृक्ष लगाए जाने से संबंधित जो सरकारी दावे किए जा रहे हैं, वे भी बेबुनियाद हैं।

सरकारी दावों की वास्तविकता का पता इसी से लग जाता है कि हर साल एक से सात जुलाई तक देश में वन महोत्सव के नाम पर करोड़ों की संख्या में पौधारोपण किया जाता है। ऐसे में देश में हरित संपदा में बेशुमार बढ़ोतरी होती, लेकिन धरातल पर कुछ दिखता नहीं है। वास्तविकता यह है कि पौधारोपण का कोटा अधिकारी से लेकर साधारण कर्मचारी, पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी और शिक्षक, यहां तक कि स्कूलों के लिए भी निर्धारित कर दिया जाता है कि उन्हें उसी अनुपात में पौधे लगाने के लिए दे दिए जाते हैं। जबकि पौधे दिए जाने के स्तर से ही उसमें कटौती की जाती है। फिर जो बची-खुची संख्या में मिले पौधे कितने लगाने लायक होते हैं और वह किस सीमा तक रोपित किए जाते हैं, यह बड़ा सवाल है। इसका प्रमाण पौधारोपण का दायित्व निबाहने वाले आखिरी सीढ़ी के कर्मचारी आपको बखूबी बता सकते हैं। ऐसी स्थिति में हरित संपदा में बढ़ोतरी का दावा कितना सही है, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है, जबकि ऐसी आंकड़ों की बाजीगरी के चलते देश में हरित क्षेत्र हर साल बढ़ोतरी के कीर्तिमान स्थापित करता जाता है।

खरी-खरी

साहित्यानुरागी

पूरन सरमा

मैं सरकार बदलने का ही इंतजार कर रहा था। चुनाव हुए और सरकार बदल गई। मेरी नजर प्रदेश साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर थी। मैं शासन सचिवालय के गलियारों में चक्कर लगाने लगा। पुराने ब्यूरोक्रेट्स से मिलना-जुलना प्रारंभ किया, लेकिन इससे बात बन नहीं रही थी। सभी का कहना था कि मैं सीएम से मिलूं तो बात बन सकती है। फाइनल वही करेंगे। मैंने नजर फैलाई की सीएम तक कैसे पहुंचा जा सकता है? दयाल जी का ख्याल आया। पुराने घाघ हैं राजनीति के। उनकी शरण में गया तो बोले, 'एकदम सही समय पर आए हो। नई सरकार बन गई है, चाहो तो प्रदेश की साहित्य अकादमी पर कब्जा कर सकते हो। तुम वैसे भी साहित्यानुरागी हो।'

'सर, आपके मुंह में घी-शक्कर। मैं इसी संबंध में आपसे बात करने आया हूं। लिखने-पढ़ने का तो मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन साहित्यकारों के बीच उठता-बैठता जरूर हूं। मेरे नाम पर कोई विवाद भी नहीं होगा। आप मेरा नाम सीएम साहब के कान में डाल दो तो आपके गुण गाऊंगा।'

दयाल जी बोले, 'ठीक है, लेकिन पहले यह तो बताओ अकादमी का वार्षिक बजट कितना है?' मैंने कहा, 'सर, अभी तो एक करोड़ का है।'

'मेरे पास और कोई काम नहीं है। मेरे बारे में क्या सोचा है यह भी बता ही दो। बाकी समझ लो अध्यक्ष तो तुम बन गए।' दयाल जी ने कहा तो मैं बोला, 'सर, जितना बन पड़ेगा आपके लिए अर्पित कर दूंगा। 20 प्रतिशत तो कम से कम।'

दयाल जी बोले, 'ठीक है, मैं एप्रोच लगाता हूं।'

अकादमी अध्यक्ष पद पर मेरी नियुक्ति की घोषणा हो गई। मैं दयालजी के पास पहुंचा, आभार व्यक्त करने, तो बोले, 'आभार से क्या होता है? माल चाहिए।'

मैंने कहा, 'मैं अपने वादों पर कायम हूं सर। चिंता न करें, मिल-बांट कर सब सेट कर लेंगे।' दयाल जी बोले, 'भाई, एक बार सीएम साहब से भी मिल लो।'

सीएम से मिलने गया तो वे बस यही बोले, 'सब को साथ लेकर चलना। सब खुश रहेंगे तो हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। दयाल जी को मत भूल जाना। उनके कहने पर ही मैंने तुम्हें लगाया है।'

पोस्ट

सुधा मूर्ति जी का संसद में पहला भाषण सभी को एक बार जरूर सुनना चाहिए। प्रत्येक सांसद ऐसे अपनी बात रखने लगें तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
अनामिका जैन अंबर@anamikamber

मैंने कई बार देखा है कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे अपनी बात रख रहे होते हैं तो जयराम रमेश बीच में दखल देने लगते हैं। यह बताता है कि खरगे भले ही पार्टी अध्यक्ष या राज्यसभा में नेता-विपक्ष हों, लेकिन पार्टी में असली पावर किसी और के ही पास है।
अरविंद कुमार@arvind_kumar_

अग्निवीर एक ऐसा मुद्दा है, जिसके कई पहलुओं पर बहस हो सकती है, लेकिन जब सेना बोल रही है कि अग्निवीर के बलिदान होने की स्थिति में उसके परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाता है तो इसे मान लेना चाहिए।
सत्या चौधरी@satyagodara

राहुल गांधी की अपरिपक्वता के कारण सेना को स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। भगवान शिव की फोटो पीछे रखकर कुछ भी बोलना राजनीति नहीं है। वीर जवान के स्वजन को करीब 99 लाख मिल चुके हैं और लगभग 67 लाख मिलने भी वाले हैं।
रंगनाथ सिंह@rangnathsingh_

जागरण जनमत कल का परिणाम

सत्तापक्ष-विपक्ष में टकराव के चलते संसद की गरिमा गिरने का खतरा बढ़ गया है?

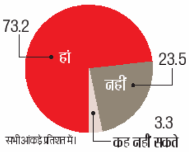

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या हेमंत सोरेन का फिर से मुख्यमंत्री बनने का फैसला सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

अटलबिहारी जी रहे जब नेता प्रतिपक्ष,
संसद का माहौल था कितना निर्मल-स्वच्छ।
कितना निर्मल-स्वच्छ बहस चलती थी दिन भर,
पर कटुता की बात नहीं दिखती थी तिल भर।
हे नेता प्रतिपक्ष! कीजिए कुछ तैयारी,
ताकी रहिए याद जिस तरह अटलबिहारी!!
- ओमप्रकाश तिवारी

हेमंत की ताजपोशी के राजनीतिक मायने

शशि शेखर
संपादकीय प्रभारी, रांची

झारखंड डायरी

पांच महीने जेल में बिताकर जमानत पर बाहर आते ही हेमंत सोरेन ने एक बार फिर झारखंड में सत्ता की कमान संभाल ली है। जेल जाने से पहले वह सोरेन परिवार के विश्वस्त माने जाने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता चम्पाई सोरेन को सीएम की कुर्सी सौंपकर गए थे। हेमंत सोरेन 28 जून को जमानत पर के जेल से बाहर आने के बाद बदलाव की सुगबुगाहट तो थी, लेकिन यह सब पांच दिनों के भीतर ही हो जाएगा, इसकी उम्मीद कम लोगों को थी। तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच बुधवार को विधायक दल की बैठक में हेमंत को नया नेता चुन लिया गया और शाम में चम्पाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। इसके अगले दिन गुरुवार को हेमंत ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली।

हेमंत सोरेन की ताजपोशी के गंभीर राजनीतिक मायने भी हैं। झामुमो समेत उसकी सहयोगी कांग्रेस झारखंड में लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर उत्साहित है। दोनों दलों ने मिलकर राज्य की आदिवासी सुरक्षित पांच सीटें जीत ली हैं। विधानसभा चुनाव में आइएनडीआइए को और बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है। झारखंड महागठबंधन के सर्वमान्य बड़े नेता हैं, जिनका राज्यभर में प्रभाव है। यह तय है कि इस वर्ष के अंत में राज्य में होनेवाले विधानसभा चुनाव में वही आइएनडीआइए का चेहरा होंगे। सरकार की कमान हाथ में होने पर वह उस अनुरूप फैसले अभी से लेंगे और लोगों में माहौल बनाने तथा संदेश देने का काम करेंगे। हेमंत के जेल जाने को लेकर सहानुभूति वोट मिलने की भी उम्मीद है। जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन भाजपा पर हमलावर हैं और अपने खिलाफ हुई साजिश होने के आरोप जोर-शोर से लगा रहे हैं। इस बात को जितनी मजबूती से जनता के बीच वह ले जा सकते हैं, दूसरे नेता शायद नहीं ले जा पाते। उन्हें जमानत देने के दौरान हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ईडी के पास हेमंत के विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं है। यह बात हेमंत को ताकत दे रही है। इसका राजनीतिक लाभ लेने की भी भरपूर कोशिश होगी।

तीसरी बार सीएम बनने के बाद हेमंत सोरेन का स्वागत करतीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। जागरण

दूसरी ओर चम्पाई सोरेन ने अपने 153 दिनों के अपने कार्यकाल में जहां तेजी से काम किया, वहीं हेमंत की अनुपस्थिति में संगठन को भी धार दी। उन्होंने जहां संकट के दौर में सरकार की कमान संभाली, वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए प्रभावी अभियान भी चलाया। हेमंत के जेल से वापस आने पर बिना हिचकिचाहट सीएम की कुर्सी भी छोड़ दी। उन्होंने यह भी कहा कि वह झामुमो के हर निर्णय के साथ हैं।

हेमंत का यह कार्यकाल बड़ा उथल-पुथल वाला रहा। 29 दिसंबर 2019 को उनके सीएम के रूप में शपथ लेने के कुछ दिनों बाद कोरोना महामारी और लाकडाउन में दो वर्षों तक कामकाज लगभग ठप रहा। बीमारी से निपटने पर ही सबका ध्यान था। बाद में विकास के काम होने शुरू हुए। इस बीच उस समय के राज्यपाल रमेश बैस का अचानक तबादला हो गया। उनका कार्यकाल काफी विवादों से भरा रहा। हेमंत मुख्यमंत्री थे और उनकी जुड़े आफिस आफ प्राफिट केस लेकर दोनों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। स्थानीयता नीति से संबंधित विधेयक लौटाने से लेकर सरकार गिराने के आरोप-प्रत्यारोप भी लगे। सोरेन से जुड़े खनन पट्टा लीज मामले में चुनाव आयोग के मंतव्य को राज्यपाल ने कभी सार्वजनिक नहीं किया। इस चिट्ठी ने प्याले में तूफान की तरह राज्य में हलचल मचाई। इस बीच राज्यपाल का तबादला हो गया। हालांकि सदस्यता के संबंध में चुनाव आयोग के गोपनीय पत्र ने हेमंत को मजबूत बनाया। हेमंत को पूर्वानुमान हो गया था कि वह जेल जा सकते हैं और इसके बाद वे क्षेत्र का दौरा करने लगे और विकास की पोटली खोल दी। वह अपनी बात अपने लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे कि भाजपा आदिवासी नेता को जेल भेजना चाहती है। आदिवासियों में यह बात पैठ गई कि भाजपा आदिवासी नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इस तरह चार साल हेमंत का बीत गया। विकास की बात कागजों पर ही होती रही। जेल जाने से पहले उन्होंने आदिवासियों से जुड़े सरना धर्म कोड का मुद्दा भी उछालते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार आदिवासियों को उनका हक-अधिकार नहीं देना चाहती। उन्हें सहानुभूति भी मिली। 31 जनवरी 2024 को जब इस्तीफा देकर जेल गए तब चम्पाई सीएम बनाए गए थे। अब देखना है कि हेमंत का अगला कदम क्या होगा और राज्य की राजनीति में क्या नया रंग देखने को मिलता है।

मंथन

यूरोपीय संसद चुनाव और भारत

यूरोपीय संसद के चुनाव परिणाम भारत-ईयू संबंधों के विविध पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं। संभावित चुनौतियों को समझते हुए भारत को इन बदलावों के अनुरूप रणनीति बनानी होगी

डा. शक्ति प्रसाद श्रीचंदन
असिस्टेंट प्रोफेसर, यूरोपीय अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

यूरोपीय संसद का चुनाव एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक आयोजन है जो हर पांच साल में होता है। इससे यूरोपीय संघ (ईयू) के नागरिकों को यूरोपीय संसद में अपने 720 प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर मिलता है। ईयू के संस्थागत ढांचे के भीतर एकमात्र सीधे निर्वाचित निकाय के रूप में, संसद ईयू कानून को आकार देने, बजट को मंजूरी देने और अन्य ईयू संस्थानों की निगरानी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करके आयोजित किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इस चुनाव में 27 सदस्य देशों के मतदाता भाग लेते हैं, जो इसे लोकतांत्रिक जुड़ाव और ईयू के भीतर विविध राजनीतिक परिदृश्य का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बनाता है। इन चुनावों के परिणाम यूरोपीय संघ की नीतियों की दिशा को प्रभावित करते हैं। बीते माह पूरे यूरोपीय संघ में यह चुनाव आयोजित किया गया था और नई संसद 11 जुलाई से अपना काम शुरू करेगी।

भारत पर प्रभाव : चूंकि चुनाव के साथ ही नए आयुक्त और उनकी टीम नियुक्त की जाएगी जो विभिन्न क्षेत्रों की देखरेख करेंगे, इसलिए इसका भारत के हितों पर गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। यूरोपीय संसद के चुनावों ने राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसमें दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी दलों को पर्याप्त लाभ हुआ है। इस परिवर्तन से भारत के लिए कई परिणाम सामने आ सकते हैं, जो व्यापार संबंधों, भू-राजनीतिक संरेखण और विभिन्न द्विपक्षीय पहलों को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी दलों के उदय के परिणामस्वरूप यूरोपीय संघ के भीतर अधिक संरक्षणवादी रुख हो सकता है। व्यापार नीतियां अधिक कठोर हो सकती हैं, जो संभावित रूप से यूरोप में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही यूरोपीय संघ के साथ मजबूत व्यापार संबंधों से जुड़े भारत के लिए अनुकूल व्यापार समझौतों पर बातचीत करने या मौजूदा समझौतों को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते (बीटीआईए) पर बातचीत में संरक्षणवाद और कड़े नियामक मानकों की ओर बदलाव के कारण इसमें देरी हो सकती है। दूसरे, पर्यावरण और जलवायु नीतियों के प्रति यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण में परिवर्तन भारत की जलवायु कूटनीति को प्रभावित कर सकता है। पिछले यूरोपीय आयोग की एक प्रमुख पहल ग्रीन डील, यदि दक्षिणपंथी दलों का प्रभाव जारी रहता है, तो उसकी गति कुछ धीमी हो सकती है। यह सतत विकास परियोजनाओं और जलवायु परिवर्तन पहलों पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को प्रभावित कर सकता है। वैश्विक जलवायु मंचों और पहलों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे भारत को इन बदलावों के जवाब में अपनी रणनीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है।

रोजगार बाजार : राष्ट्रवादी दलों के प्रभाव में प्रवासन नीतियों के सख्त होने की संभावना है। सख्त प्रवासन नियंत्रण और विदेशी श्रमिकों एवं छात्रों के लिए कम अवसर यूरोप में भारतीय प्रवासियों को प्रभावित कर सकते हैं। कई भारतीय छात्रों और पेशेवरों को वीजा या वर्क परमिट हासिल करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है, जिससे भारत और यूरोपीय संघ के बीच शैक्षिक आदान-प्रदान का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। इससे यूरोपीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में कमी आ सकती है और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संबंधों पर इसका असर पड़ सकता है।

यूरोपीय संघ के देशों में बड़ी संख्या में कार्यरत हैं भारतीय कामगार। फाइल

रणनीतिक साझेदारी : भूराजनीतिक रूप से यूरोपीय संसद में दक्षिणपंथी बदलाव यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्राथमिकताओं को बदल सकता है, विशेष रूप से चीन और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में। यूरोपीय संघ चीन के प्रति अधिक टकरावपूर्ण रुख अपना सकता है, जिससे वह अमेरिका और भारत सहित उसके सहयोगियों के साथ अधिक निकटता से जुड़ सकता है। यह भारत के लिए यूरोपीय संघ के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के अवसर प्रस्तुत कर सकता है, विशेष रूप से रक्षा, समुद्री सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक में बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में।

तकनीकी सहयोग : यूरोपीय संघ की डिजिटल और तकनीकी नीतियों में बदलाव भारत के उभरते तकनीकी क्षेत्र के लिए उपयोगी हो सकता है। डाटा गोपनीयता, डिजिटल संप्रभुता और प्रौद्योगिकी मानकों के लिए यूरोपीय संघ का नियामक दृष्टिकोण यूरोप में काम करने वाली भारतीय आइटी कंपनियों को प्रभावित कर सकता है। वैसे नए नियम का अनुपालन भले ही बोझ लग सकता है, परंतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसी उभरती तकनीकों में सहयोग के लिए रास्ते भी खोल सकते हैं।

****

थ्रेड्स के 17.5 करोड़ यूजर, भारत सबसे सक्रिय देश

नई दिल्ली: इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म मेटा ने कहा है कि उसकी इंटरनेट नेटवर्किंग सेवा 'थ्रेड्स' के लिए भारत सबसे सक्रिय देशों में से एक है। थ्रेड्स के वैश्विक स्तर पर 17.5 करोड़ से अधिक मासिक सक्रिय यूजर हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्म का संचालन करने वाली मेटा की तरफ से आई यह जानकारी इस लिहाज से अहम है कि ट्विटर (अब एक्स) के प्रतिद्वंद्वी के रूप में थ्रेड्स को आधिकारिक रूप से पेश किए जाने के लगभग एक साल पूरे होने जा रहे हैं। (प्रेट्र)

आरबीआइ का निर्यात एवं आयात लेनदेन को कवर करने वाले नियमों को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव व्यापारियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाएगा।
– अजय सहाय, महानिदेशक, फियो

सेंसेक्स	80,049.67	▲ 62.87
निफ्टी	24,302.15	▲ 15.65
सोना प्रति दस ग्राम	₹73,080	▲ ₹530
चांदी प्रति किलोग्राम	₹92,500	▲ ₹1,200
डालर	₹83.50	▲ ₹0.01
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$86.89	

एक नजर में

बैंक आफ महाराष्ट्र का ऋण वितरण 19 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली: बैंक आफ महाराष्ट्र का चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में ऋण वितरण 19 प्रतिशत बढ़कर 2.09 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। 30 जून, 2023 के अंत तक बकाया ऋण 1.75 लाख करोड़ रुपये था। बैंक की कुल जमा सालाना आधार पर 9.44 प्रतिशत बढ़कर 2.67 लाख करोड़ रुपये हो गई है। यह पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 2.44 लाख करोड़ रुपये थी। (प्रेट्र)

रियल एस्टेट कारोबार को अलग करेगी रेमंड

नई दिल्ली: कपड़ा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी रेमंड लिमिटेड शेयरधारकों के लिए मूल्य बढ़ाने तथा संपत्ति बाजार में वृद्धि की संभावनाओं का दोहन करने के लिए अपने रियल एस्टेट कारोबार को अलग करेगी। व्यवस्था के अनुसार, रेमंड लिमिटेड के प्रत्येक शेयरधारक को रेमंड लिमिटेड में प्रत्येक एक शेयर के बदले रेमंड रियल्टी का एक शेयर मिलेगा। (प्रेट्र)

कोयला क्षेत्र ने मई में दर्ज की 10.2 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली: आठ प्रमुख उद्योगों में कोयला क्षेत्र ने मई में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। कोयला उद्योग का सूचकांक मई में 184.7 अंक पर पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी माह में यह 167.6 अंक था। वृद्धि के पीछे मुख्य वजह कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी को माना जा सकता है। उत्पादन में वृद्धि ऊर्जा और विनिर्माण उद्योगों की बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षेत्र की क्षमता बताती है। (प्रेट्र)

एआइ में हो रही क्रांति की अगुआई करे भारत: कांत

नई दिल्ली: नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने गुरुवार को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) क्रांति में भारत को न केवल भाग लेना चाहिए, बल्कि उसका नेतृत्व करना चाहिए। नासकाम का हवाला देते हुए कहा कि 70 प्रतिशत स्टार्टअप अपने विकास को गति देने के लिए एआई को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह स्टार्टअप परिवेश में एआइ की भूमिका को बताता है। (प्रेट्र)

भारत पर भरोसा बढ़ने से बाजार में तेजी जारी

सेंसेक्स पहली बार 80,000 के पार बंद हुआ, निफ्टी ने भी नए शिखर को छुआ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आर्थिक सूचकांक में तेजी और बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर और खपत में बढ़ोतरी को लेकर बड़े आवंटन की उम्मीद से बाजार में तेजी जारी है। गुरुवार को बीएसई सेंसेक्स 62.87 अंक की बढ़त के साथ अब तक के उच्चतम स्तर 80,049.67 पर बंद हुआ। यह पहली बार है जब सेंसेक्स 80 हजार के पार बंद हुआ है। कारोबार के दौरान एक समय यह 405.84 अंक की तेजी के साथ 80,392.64 अंक तक चला गया था, लेकिन बाद में मुनाफावसूली से यह नीचे आया। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 15.65 अंक यानी 0.06 प्रतिशत की तेजी के साथ नए शिखर 24,302.15 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 114.5 अंक चढ़कर 24,401 अंक तक गया था।

पीएचडी चेंबर के कैपिटल मार्केट कमेटी के चेयरमैन बीके सभरवाल के मुताबिक आर्थिक बुनियाद की मजबूती के साथ नई सरकार की स्थिरता पर पूर्ण भरोसे की वजह से बाजार में बढ़ोतरी का रुख जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बजट तक छोटी-मोटी गिरावट हो सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से बाजार में तेजी का ही रुख रहेगा। मंत्रालय के आवंटन से लेकर लोकसभा चेयरमैन के चुनाव तक में सरकार ने अपनी ताकत दिखाई और इसका बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

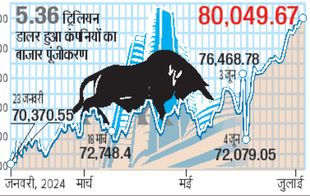

लाभ में रहने वाले शेयर

एचसीएल, आइसीआइसीआइ, टाटा मोटर्स, सन फार्मास्युटिकल्स, टीसीएस, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा

गिरकर बंद होने वाले शेयर

एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडसइंड बैंक

खुदरा निवेशक पहले की तुलना में बड़ी मात्रा में बाजार में कर रहे हैं निवेश

विशेषज्ञों मान रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया का भरोसा बढ़ता जा रहा है। एसएमसी ग्लोबल की निदेशक श्रुति अग्रवाल ने बताया कि भारत आर्थिक शक्ति का केंद्र बन गया है। निवेशक सरकारी नीतियों के जारी रहने से अब सरकारी के साथ निजी पूंजीगत व्यय में भी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआइआइ) के साथ खुदरा निवेशक पहले की तुलना में बड़ी मात्रा में बाजार में निवेश कर रहे हैं। इससे बाजार को बल मिल रहा है और बाजार विदेशी संस्थागत निवेशकों पर निर्भर नहीं रह गया है। जुलाई माह के पहले तीन दिनों में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3,641 करोड़ रुपये का निवेश किया जबकि विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से 3057 करोड़ का निवेश किया गया। जून में डीआइआइ ने शेयर बाजार में 28,633 करोड़ रुपये की खरीदारी की।

सोने के भाव में 530 रुपये की तेजी, चांदी 1,200 उछली

फेडरल रेट में कटौती की उम्मीद से सोने में भी तेजी का रुख दिख रहा है। दूसरी तरफ गुरुवार को 24 कैरेट सोने के भाव में 530 रुपये की तेजी आई और यह 73,080 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। चांदी भी 1200 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी के साथ 92,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

निवेश के लिहाज से रक्षात्मक माने जाने वाली आइटी और औषधि क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में लिवाली देखी गई। अमेरिका में मुद्रास्फीतिक दबाव कम होने, तिमाही आधार पर आय परिदृश्य में सुधार तथा 10 साल के बांड प्रतिफल में तेज गिरावट से इन शेयरों में खरीदारी की गई। -**विनोद नायर**, रिसर्च हेड, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज

पहली छमाही में घरों की बिक्री 11% बढ़कर 10 साल के शिखर पर

नई दिल्ली, प्रेट्र: देश में 2024 की पहली छमाही में मकानों की बिक्री 11 प्रतिशत बढ़कर 10 साल के उच्च स्तर 1.73 लाख इकाई पर पहुंच गई। कुल बिक्री में प्रीमियम आवास की हिस्सेदारी 34 प्रतिशत रही। रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक के अनुसार, इस दौरान देश के आठ प्रमुख शहरों में कार्यालय की मांग 33 प्रतिशत बढ़कर रिकार्ड 3.47 करोड़ वर्ग फुट पर पहुंच गई।

मुंबई में आवासीय बिक्री जनवरी-जून 2024 में सालाना आधार पर 16 प्रतिशत बढ़कर 47,259 इकाई रही, जबकि शहर में कार्यालय स्थान की मांग 79 प्रतिशत बढ़कर 58 लाख वर्ग फुट हो गई। इसी तरह, दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवासीय बिक्री चार प्रतिशत घटकर 28,998 इकाई रह गई, हालांकि कार्यालय स्थान की मांग 11.5 प्रतिशत बढ़कर 57 लाख वर्ग फुट हो गई। बेंगलुरु में आवासीय बिक्री में चार प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और यह 27,404 इकाई हो गई जबकि कार्यालय मांग 21 प्रतिशत बढ़कर 84 लाख वर्ग फुट हो गई। पुणे में आवासीय बिक्री 13 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 24,525 इकाई रही, जबकि कार्यालय स्थान की मांग 88 प्रतिशत बढ़कर 44 लाख वर्ग फुट हो गई। चेन्नई में आवासीय मांग में उछाल और कार्यालय स्थान की मांग में इस अवधि में गिरावट आई।

मजबूत आर्थिक बुनियाद तथा स्थिर सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भारत का रियल एस्टेट बाजार पिछले कुछ तिमाहियों में तेजी से बढ़ा है।
-**शिशिर बैजल**, चेयरमैन, नाइट फ्रैंक इंडिया

विभिन्न मूल्य बिंदुओं पर आवासीय संपत्तियों की मांग मजबूत है। डेवलपर इस मांग का लाभ उठाने के लिए नई परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं। -**प्रदीप अग्रवाल**, चेयरमैन, सिग्नेचर ग्लोबल

दूरसंचार कंपनियों के शुल्क दरें बढ़ाने से मुद्रास्फीति 0.2% बढ़ेगी

मुंबई, प्रेट्र: दूरसंचार कंपनियों द्वारा शुल्क दर में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करने से वित्त वर्ष 2024-25 में मुख्य मुद्रास्फीति 0.20 प्रतिशत बढ़ सकती है। डायचे बैंक के विश्लेषकों ने मूल (कोर) मुद्रास्फीति को 0.20 प्रतिशत बढ़ाकर 3.8 प्रतिशत कर दिया है। मूल मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन का प्रभाव शामिल नहीं होता।

शुल्क दरों में वृद्धि का असर जुलाई से दिखना शुरू होगा और इस बढ़ोतरी से मासिक आधार पर मुख्य मुद्रास्फीति में 0.85 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा, 'कुल मिलाकर, दूरसंचार शुल्क दरें बढ़ने के कारण चालू वित्त वर्ष (2024-25) में मूल मुद्रास्फीति में 0.20 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इसको देखते हुए हमने अपने चालू वित्त वर्ष के मूल मुद्रास्फीति के अनुमान को पहले के 3.6 प्रतिशत औसत से संशोधित कर 3.8 प्रतिशत कर दिया है।'

- डायचे बैंक ने मूल मुद्रास्फीति को 0.20% से बढ़ाकर 3.8% किया
- कम बारिश भी मुद्रास्फीति में वृद्धि का हो सकती है एक कारण

रिपोर्ट में कहा गया है कि जून माह में मुख्य मुद्रास्फीति 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो मई माह की तुलना में 0.13 प्रतिशत अधिक होगी। इसमें कहा गया है कि खुदरा मुद्रास्फीति जून में 4.96 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो मई में 4.75 प्रतिशत थी।

चीफ जस्टिस बोले, सतर्क रहें सेबी व सैट

मुंबई, प्रेट्र: भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मार्केट रेगुलेटर सेबी और सैट को शेयर बाजारों में उल्लेखनीय उछाल के बीच सावधानी बरतने की गुरुवार को सलाह दी। चीफ जस्टिस ने यहां नए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) परिसर का उद्घाटन करते हुए अधिकारियों से सैट की नई पीठें खोलने पर विचार करने का आग्रह किया, क्योंकि अधिक मात्रा में लेन-देन तथा नए नियमों के कारण कार्यभार बढ़ गया है।

बीएसई के 80,000 अंक का आंकड़ा पार करने को उल्लास से भरा क्षण बताने वाली खबरों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं नियामक प्राधिकरणों के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देती हैं कि जीत के बीच हर कोई अपना 'संतुलन व धैर्य' बनाए रखे। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'आप शेयर बाजार में जितनी अधिक तेजी देखेंगे, मेरा मानना है कि सेबी तथा सैट की भूमिका उतनी ही अधिक होगी। ये संस्थान सतर्कता बरतेंगे, सफलताओं का जश्न मनाएंगे लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इसकी नींव स्थिर रहे।' वित्तीय क्षेत्र में समय पर कार्रवाई और त्रुटियों को सुधारना बेहद महत्वपूर्ण है।

मुंबई में गुरुवार को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के नए कार्यालय परिसर के उद्घाटन के दौरान सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच के साथ प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ● प्रेट्र

बाजार के शरारती तत्वों के बारे में अवगत कराएं: बुच: सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने बाजार प्रतिभागियों से पूंजी बाजार में मौजूद शरारती तत्वों के बारे में जानकारी देने को कहा है। कहा, नियामक का हित किसी गलत आचरण पर जल्द कार्रवाई करने में है।'

धोखाधड़ी रोकने के लिए सेबी ने अनिवार्य की संस्थागत व्यवस्था

नई दिल्ली, प्रेट्र: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए शेयर ब्रोकिंग कंपनियों को धोखाधड़ी यानी बाजार के दुरुपयोग को रोकने और उसका पता लगाने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए कहा है।

सेबी ने गुरुवार को एक परिपत्र में ब्रोकिंग कंपनियों के लिए कारोबारी गतिविधियों और आंतरिक नियंत्रण की निगरानी के लिए प्रणालियां लागू करने और व्हिसल-ब्लोअर नीति की शुरुआत को अनिवार्य कर दिया है। ये सभी प्रविधान सेबी (शेयर ब्रोकर) (संशोधन) विनियम, 2024 का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य बाजार की अखंडता और निवेशक सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करना है। मानकों का कार्यान्वयन शेयर ब्रोकर के आकार पर निर्भर करेगा। 50,000 से अधिक सक्रिय विशिष्ट ग्राहक कोड वाले ब्रोकर के लिए एक जनवरी, 2025 तक इसका अनुपालन करना जरूरी है। इसके अलावा 2,001 से लेकर 50,000 तक सक्रिय यूसीसी वाले ब्रोकर को एक अप्रैल, 2025 तक इसका अनुपालन करना होगा। सके अलावा पात्र शेयर ब्रोकर को संचालन और ग्राहक व्यवहार की निगरानी के लिए अपने मौजूदा दायित्वों पर विचार करते हुए एक अगस्त, 2024 तक इन शर्तों का पालन करना होगा।

50,000 से अधिक ग्राहक कोड वाले ब्रोकर को अगले साल तक करना होगा इसका अनुपालन

राष्ट्रीय फलक

गुमराह होने की जगह मुल्क के लिए काम करें मुस्लिम युवा : मदनी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मुस्लिम युवाओं का आह्वान किया कि वे जज्बाती नारों और भावनाओं से गुमराह होने की जगह मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। अपने हालात बदलें। वह अदालत, कला, शिक्षा, खेल, व्यापार और नौकरियों समेत अन्य क्षेत्रों में मेहनत कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, क्योंकि सिस्टम से बाहर रहकर अपना भविष्य और अपने बारे में लोगों के विचार नहीं बदले जा सकते हैं। उन्होंने मौजूदा राजनीतिक व सामाजिक माहौल का जिक्र करते हुए मुस्लिम युवाओं को चेताया कि मायूसी के इस दौर में गुमराह करने वाली स्वार्थी शक्तियां व अपना फायदा चाहने वाले संगठन भावनाओं को हाईजैक करने का प्रयास कर सकते हैं। उनसे सावधान रहें।

मौलाना महमूद मदनी दिल्ली में आइटीओ स्थित जमीयत मुख्यालय में गुरुवार को शुरू हुए दो दिवसीय राष्ट्रीय प्रबंधक समिति अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोकसभा चुनावों में 'घुसपैठिए' और 'अधिक बच्चे पैदा करने वाला' जैसे बयानों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब मुल्क के बड़े लोग चुनाव में छोटे राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का बयान देते हैं तो देश का दीर्घकालिक बड़ा नुकसान होता है। लोग गुमराह होते हैं। ऐसे बयानों से मुस्लिम समाज बेइज्जत महसूस कर रहा है। दूरियों के साथ सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, जो देशहित में नहीं है। फिर भी हम बातचीत की हिमायत करते हैं। ऐसा करके ही मतभेद और दूरियों को कम किया जा सकता है।

मदनी ने कहा कि इस्लाम, मुसलमान, इबादतगाहों और इबादत के तरीकों को लेकर दूसरे समाज में गलतफहमी है। ये गलतफमियां तभी दूर होंगी जब संवाद हो। हमारे दरवाजे सभी राजनीतिक दलों के लिए खुले हैं। उन्होंने कहा, नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं, बल्कि प्यार से किया जा सकता है। उन्होंने उन्मादी हिंसा पर चिंता जताई और कहा इसे वैश्विक स्तर पर देश की छवि धूमिल होती है।

अधिवेशन में विभिन्न राज्यों से ढाई हजार से अधिक पदाधिकारी शामिल हुए हैं, जिनकी मौजूदगी में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत और उकसावे पर प्रस्ताव पारित करते हुए इसके लिए अलग कानून की मांग की गई। सूर्य नमस्कार को इस्लाम विरुद्ध बताते हुए स्कूलों में इसे मुस्लिम बच्चों पर लागू करने की आलोचना की गई।

- जमीयत अध्यक्ष ने कहा, अदालत, शिक्षा, खेल, व्यापार और नौकरियों में मेहनत कर बदलें देशवासियों के विचार
- दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में संवाद के जरिये मुस्लिम समाज को लेकर मतभेदों को दूर करने का किया आग्रह

जमीयत उलेमा ए हिंद के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए मौलाना महमूद मदनी। जागरण

अध्यक्ष बने रहेंगे महमूद मदनी

अधिवेशन में एक सत्र में प्रस्ताव आया कि कोई व्यक्ति सिर्फ दो कार्यकाल के लिए जमीयत का अध्यक्ष होगा, लेकिन बहुमत के साथ कोर कमेटी में यह प्रस्ताव गिर गया। अब आगे भी मौलाना महमूद मदनी जमीयत के अध्यक्ष बने रहेंगे। उन्होंने नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देकर अगले चार-पांच साल में अध्यक्ष पद छोड़ने की ख्वाहिश जाहिर की।

कोटा में जेईई की तैयारी कर रहे बिहार के छात्र ने की आत्महत्या

जासं, जयपुर : देश में कोचिंग हब के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान के कोटा में गुरुवार को एक और छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बिहार के नालंदा निवासी 16 वर्षीय छात्र संदीप कुमार कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। वह एक हास्टल में रहता था। गुरुवार सुबह सात बजे संदीप के कमरे की खिड़की खुली थी तो उधर से गुजर रहे अन्य छात्रों की नजर पड़ी। छात्रों ने देखा कि संदीप पंखे से फंदे पर लटका हुआ था।

पुलिस के मुताबिक, संदीप पिछले दो साल से कोटा में रह रहा था। उसका छोटा भाई संजीत भी कोटा में ही अलग कमरा किराए पर लेकर रहता था। वह इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। पढ़ाई में व्यवधान नहीं हो, इसलिए दोनों भाई अलग-अलग रहते थे। उल्लेखनीय है कि कोटा में इस साल अब तक 12 छात्र-छात्राओं ने आत्महत्या की है।

पाक्सो एक्ट में पीड़िता की पहचान गुप्त रखने का अदालतों को सख्त निर्देश

विधि संवाददाता, जागरण ● शिमला

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पाक्सो एक्ट (बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम) से जुड़े मामलों में पीड़ित की पहचान गुप्त रखने के लिए जिला अदालतों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने इन अदालतों को पाक्सो एक्ट के प्रविधानों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने को कहा है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने पाक्सो से जुड़े मामले का निपटारा करते हुए कहा कि मौजूदा मामले में ट्रायल कोर्ट के रिकार्ड पर ऐसा तथ्य नहीं है, जो यह दर्शाता हो कि अधिनियम की धारा-36 के तहत स्क्रीनिंग की प्रक्रिया का पालन पीड़ित का साक्ष्य दर्ज करवाने के समय किया गया हो।

कोर्ट ने रिकार्ड के अवलोकन के बाद पाया कि मुकदमे के दौरान पीड़िता, उसकी बहनों, मां के साथ-साथ उसके गांव और स्कूल का नाम सार्वजनिक किया गया है, जो वैधानिक जनादेश का उल्लंघन है। इसलिए, कोर्ट ने हिमाचल की सभी विशेष अदालतों को पाक्सो अधिनियम के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करने का निर्देश दिया है। उक्त अधिनियम की धारा 36 के तहत पीड़ित बच्चे को इस तरह से साक्ष्य देने की अनुमति देती है कि वह साक्ष्य दर्ज करते समय आरोपित के संपर्क में न आए और ऐसे बच्चे को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से या एकल दृश्यता दर्पण या पर्दे का उपयोग करके बयान दर्ज करने की अनुमति देती है। अधिनियम की धारा 37 में कहा गया है कि पीड़ित बच्चे के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में बंद कमरे में की जाएगी।

- हाई कोर्ट ने आदेश की कापी हर न्यायालय को भेजने का दिया निर्देश
- सुनवाई पीड़ित बच्चे के माता-पिता की उपस्थिति में बंद कमरे में हो

अभिनेत्री स्मृति बिस्वास का निधन

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई: चांदनी चौक, दिल्ली का ठग और बाप रे बाप फिल्मों की अभिनेत्री स्मृति बिस्वास अब नहीं रहीं। बुधवार देर रात नासिक स्थित आवास पर उनका निधन हो गया। अपने जीवन के 100 वसंत पार कर चुकीं स्मृति बिस्वास के निधन का कारण स्वास्थ्य समस्याओं को बताया जा रहा है।

सिनेमा जगत में स्मृति बिस्वास ने अपना सफर बतौर बाल कलाकार शुरू किया था। उन्होंने 1930 में प्रदर्शित बांग्ला फिल्म संध्या से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने बतौर अभिनेत्री गुरुदत्त, बिमल राय, बीआर चोपड़ा और राज कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों और फिल्मकारों के साथ कई हिंदी और बांग्ला फिल्मों में काम किया। 1960 में प्रदर्शित फिल्म माडल गर्ल उनकी आखिरी फिल्म थी। दरअसल, फिल्मकार एसडी नारंग से शादी करने के बाद उन्होंने अभिनय को अलविदा कह दिया था। साल 1986 में पति के निधन के बाद वह नासिक में रहने लगी थीं।

येदियुरप्पा को 15 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए समन

बेंगलुरु, प्रेट्र : बेंगलुरु की एक अदालत ने पाक्सो मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को 15 जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया है। सीआइडी ने 27 जून को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भाजपा नेता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

येदियुरप्पा के खिलाफ एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही सीआइडी ने आरोप पत्र में कहा है कि वह और तीन अन्य ने पीड़िता और उसकी मां को चुप रहने के लिए पैसे दिए थे। अन्य तीन सह आरोपितों के नाम अरुण वाई एम, रुद्रेश एम और जी मारिस्वामी है।

इस साल 14 मार्च को 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि येदियुरप्पा ने दो फरवरी को अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। सीआइडी ने 17 जून को येदियुरप्पा से तीन घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगाने वाली 54 वर्षीय पीड़िता की मां की फेफड़ों के कैंसर के कारण मई में एक निजी अस्पताल में मृत्यु हो चुकी है। येदियुरप्पा ने अपने ऊपर लगे आरोप से इन्कार किया है। उन्होंने कहा है कि वह कानूनी तौर इसका सामना करेंगे।

- नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का है आरोप

बीएस येदियुरप्पा। फाइल

महाराष्ट्र विधान परिषद ने नेता प्रतिपक्ष दानवे की निलंबन अवधि घटाई

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र विधान परिषद ने गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे की निलंबन अवधि को पांच दिन से घटाकर तीन दिन कर दिया। अब दानवे शुक्रवार से सदन की कार्यवाही में भाग ले पाएंगे। शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता दानवे को सोमवार शाम सदन में चर्चा के दौरान भाजपा विधायक प्रसाद लाड के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग पर पांच दिनों के लिए विधान परिषद से निलंबित कर दिया गया था।

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दानवे को निलंबित करने के फैसले को एकतरफा बताया। उन्होंने इसे पूर्व नियोजित साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि यदि दानवे की टिप्पणी से महिलाओं को ठेस पहुंची है तो वह शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख होने के नाते माफी मांगते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि सदन के बाहर ऐसी टिप्पणी करने वाले भाजपा और शिवसेना नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।

नए आपराधिक कानून लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे : मेघवाल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

केंद्रीय विधि व न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नए आपराधिक कानून नागरिकों के जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये कानून न्याय प्रदान करने में तेजी लाएंगे और मुकदमेबाजी के दौरान सभी हितधारकों के महत्वपूर्ण समय की बचत करेंगे। भारत के दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जिक्र करते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में सुधार होने से आने वाले कुछ वर्षों में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर लेगा। वह सीबीआइ अकादमी में अलंकरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

इस दौरान सीबीआइ की भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि समाज में न केवल सीबीआइ के महत्व को मान्यता मिल रही है, बल्कि इसकी जांच भी सर्वश्रेष्ठ है। मेघवाल ने इस बात पर जोर दिया कि सीबीआइ को सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी माना जाना सही मायने में उचित है, जो विभिन्न हितधारकों द्वारा जटिल एवं संवेदनशील मामलों में सीबीआइ जांच की मांग से परिलक्षित होता है। इस अवसर पर 39 सीबीआइ अधिकारियों/कर्मियों को विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किए। इस मौके पर सीबीआइ के निदेशक प्रवीण सूद भी मौजूद रहे।

- कहा-सभी हितधारकों के महत्वपूर्ण समय की बचत करेंगे

अर्जुन राम मेघवाल। फाइल

मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में सीएम महिला सम्मान का अध्ययन करेंगे अधिकारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली: मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के मानदंडों को अंतिम रूप देने से पहले दिल्ली सरकार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लागू योजनाओं का अध्ययन करेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने विभागीय अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिए हैं। योजना को अंतिम रूप देने के लिए गहलोत ने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की और योजनाओं से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की।

इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री आतिशी ने की थी। उन्होंने कहा था कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। उन्हें प्रति माह एक हजार रुपये दिए जाएंगे। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को दोनों राज्यों का दौरा कर यह अध्ययन करने की सलाह दी कि वहां योजना कैसे लागू की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि योजना के लाभार्थियों की पहचान उनकी आय के आधार पर की जाएगी।

****

38 हजार से अधिक फलस्तीन मारे गए हैं इजरायल और फलस्तीन के युद्ध में अब तक। जबकि 87,445 घायल हुए हैं। बता दें दोनों देशों में 29 महीने पहले युद्ध शुरू हुआ था।

आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों को अलग–थलग व बेनकाब किया जाए : भारत

एससीओ शिखर बैठक ▸ अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो बन सकता है शांति के लिए खतरा

कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान आवश्यक

अस्ताना में गुरुवार को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में बोलते विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रेट्र

अस्ताना, प्रेट्र : भारत ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उन देशों को अलग-थलग और बेनकाब करने का आह्वान किया जो आतंकियों को पनाह देते हैं, उन्हें सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। भारत ने चीन और पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर आतंकवाद पर अंकुश नहीं लगाया गया तो यह क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की शिखर बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भाषण पढ़ा। इसमें उन्होंने याद दिलाया कि आतंकवाद से लड़ाई एससीओ के मूल उद्देश्यों में से एक है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एवं अन्य नेताओं की उपस्थिति में उन्होंने कहा, 'हममें से कई लोगों को ऐसे अनुभव हुए हैं, जो अक्सर हमारी सीमाओं से परे होते हैं। हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो यह क्षेत्रीय व वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। आतंकवाद को किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता।' उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उन देशों को अलग-थलग व बेनकाब करना चाहिए जो आतंकियों को पनाह देते हैं, उन्हें सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। उनका इशारा स्पष्ट रूप से पाकिस्तान और उसके सदाबहार मित्र चीन की ओर था। उन्होंने आगे कहा, ''सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है और आतंकवाद के वित्तपोषण एवं आतंकियों की भर्ती से दृढ़ता से निपटा जाना चाहिए। एससीओ को अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस संबंध में हम दोहरे मापदंड नहीं अपना सकते।'' साथ ही कहा कि पिछले वर्ष भारत की अध्यक्षता के दौरान इस विषय पर जारी संयुक्त बयान नई दिल्ली की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर चीन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, आर्थिक विकास के लिए मजबूत कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। यह हमारे समाजों के बीच सहयोग और विश्वास का मार्ग भी प्रशस्त कर सकती है। कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान आवश्यक है। इसी तरह गैर-भेदभावपूर्ण व्यापारिक अधिकार और पारगमन व्यवस्था भी आवश्यक है। एससीओ को इन पहलुओं पर गंभीरता से विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है।'' उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास में भारत द्वारा की गई प्रगति न केवल भूमि से घिरे मध्य एशियाई देशों के लिए बहुत मूल्यवान है, बल्कि इससे भारत व यूरेशिया के बीच कारोबार को भी जोखिम मुक्त किया जा सकेगा। यह शिखर सम्मेलन महामारी के प्रभाव, बढ़ते तनाव, विश्वास की कमी और दुनियाभर में हाटस्पाट की बढ़ती संख्या की पृष्ठभूमि में हो रहा है।

आतंकवाद से संयुक्त प्रयासों से निपटा जाए : शहबाज

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एससीओ बैठक में आतंकवाद को चिंता का प्रमुख मुद्दा बताते हुए कहा कि इसके सभी रूपों से संयुक्त प्रयासों से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति कायम रखना आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। साथ ही अफगान तालिबान सरकार के साथ सार्थक बातचीत का आह्वान किया। शहबाज ने यह भी कहा कि अफगान तालिबान को यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए कि उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी देश के विरुद्ध आतंकवाद के लिए न हो। कश्मीर मुद्दे का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमें संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और लोगों के आत्मनिर्णय के मौलिक अधिकार के सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के प्रति सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव हमारे क्षेत्र सहित दीर्घकालिक विवादों को हल करने के लिए एक व्यावहारिक ढांचा प्रदान करते हैं। सीपीईसी को उन्होंने एससीओ के विजन के अनुरूप बताया और क्षेत्र के भीतर आपसी समझौतों में राष्ट्रीय मुद्राओं को बढ़ावा देने की पैरवी की।

भारतीय नौसेना प्रमुख की बांग्लादेशी समकक्ष से हुई मुलाकात

ढाका, प्रेट्र : भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने बांग्लादेश के नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल वकर-उज-जमान से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देने और दोनों सशस्त्र बलों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर चर्चा की।

दोनों देशों के नौसेना प्रमुखों ने दीर्घकालिक और मजबूत संबंधों और रक्षा सहयोग बढ़ाने और बांग्लादेश और भारत के सशस्त्र बलों के बीच प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यास के क्षेत्रों में आगे के रास्ते तलाशने की पहल पर चर्चा की।

भारतीय नौसेना प्रमुख ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए द्विपक्षीय संबंधों के एक माडल के रूप में देखा जा सकता है।

अपनी यात्रा के दौरान, भारतीय नौसेना प्रमुख त्रिपाठी ने बांग्लादेश वायु सेना के चीफ आफ एयर स्टाफ एयर मार्शल हसन महमूद से भी बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे और मजबूत संबंधों पर प्रकाश डाला और प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और अंतरसंचालनीयता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की पहल पर चर्चा की गई। भारतीय नौसेना प्रमुख ने ढाका में अपने समकक्ष एडमिरल एम नजमुल हसन के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी की।

ब्रिटेन में डाले गए वोट, नतीजों का इंतजार

- ओपिनियन पोल लेबर पार्टी की बड़ी जीत का लगा रहे हैं अनुमान
- दबाव में है 14 वर्ष से शासन कर रही कंजरवेटिव पार्टी

नार्थ यार्कशायर में गुरुवार को आम चुनाव के लिए एक बूथ पर मतदान करने के बाद प्रस्थान करते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तथा उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति। एपी

लंदन, रायटर : ब्रिटेन में गुरुवार को करोड़ो मतदाताओं ने नई सरकार चुनने के लिए मतदान किया। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टर्मर ने मतदान की शुरुआत में ही वोट डाला। मतदान के लिए देश भर में 40,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने यार्कशायर में रिचमांड एंड नार्थलर्टन निर्वाचन क्षेत्र में मतदान किया। मतदान के बाद स्टर्मर ने कहा' आज ब्रिटेन नया अध्याय शुरू कर सकता है।' उन्होंने कहा' हम कंजरवेटिव पार्टी को सरकार चलाने के लिए और पांच वर्ष का समय नहीं दे सकते हैं लेकिन बदलाव के लिए आपको लेबर पार्टी को वोट देना होगा।'

लेबर पार्टी के नेता कीर स्टर्मर ने छह सप्ताह के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान लोगों से उनकी मध्य-वामपंथी पार्टी को मौका देने और बदलाव के लिए मतदान करने का आग्रह किया था। विश्लेषकों और राजनेताओं सहित अधिकांश लोगों को उम्मीद है कि वे ऐसा करेंगे। लोगों में सुनक के प्रति कुछ नराजगी है, वे उनपर सभी वादों को पूरा न करने का आरोप लगाते हैं। हालांकि, सुनक ऐसा नहीं मानते। चुनाव में कंजरवेटिव व लेबर पार्टी के अलावा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ग्रीन पार्टी व यूके रिफार्म पार्टी जैसे दल भी किस्मत आजमा रहे हैं। ब्रिटेन में अब तक हुए ओपिनियन पोल के अनुसार चुनाव में लेबर पार्टी बहुमत हासिल कर सकती है। वहीं कंजरवेटिव पार्टी को उसके इतिहास में सबसे कम सीटें मिल सकती हैं। विश्लेषकों का मानना है कि मतदाता चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं इसकी वजह से मतदान का प्रतिशत कम रह सकता है। कुछ हद तक मतदाता दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों कंजरवेटिव और लेबर से निराश नजर आ रहे हैं। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि चुनाव में लेबर पार्टी को बढ़त लोकप्रिय नीतियों की वजह से नहीं बल्कि कंजरवेटिव पार्टी की आंतरिक कमजोरियों के कारण मिल रही है।

हिजबुल्ला ने इजरायल पर एक घंटे में दागे 200 से अधिक राकेट

- हिजबुल्ला कमांडर के मारे जाने के जवाब में किया गया हमला
- इस बीच, इजरायली जेट के सोनिक बूम भी लेबनान में सुनाई दिए

दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस में विस्थापित फलस्तीनियों को आश्रय देने वाले संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित स्कूल पर इजरायली सेना के हवाई हमले के बाद अपनी जान बचाकर भागते लोग। रायटर

बेरूत, एपी : लेबनान के हिजबुल्ला समूह ने वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद नामेह नासिर की मौत के जवाब में गुरुवार को इजरायल के कई सैन्य ठिकानों पर राकेट और ड्रोन से हमला बोला। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने एक घंटे के भीतर 200 राकेट दागे। ईरान समर्थित आतंकी समूह का हमला लेबनान-इजरायल सीमा पर महीनों चले संघर्ष में सबसे बड़े हमलों में से एक है। हताहतों की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर हमास व इजरायल के बीच संघर्ष विराम होता है तो वह अपने हमले रोक देगा। हिजबुल्ला के हमले के बाद इजरायल ने भी दक्षिणी लेबनान के विभिन्न शहरों पर हमला बोला। इजरायली सेना ने कहा, उसने सीमांत कस्बों रामयेह व होउला में उसके ठिकानों पर हमला बोला। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि इस बीच इजरायली जेट विमानों की सोनिक बूम कई क्षेत्रों में सुनाई दी।

इजरायल ने हमास संग बंधक समझौते पर वार्ता को प्रतिनिधिमंडल भेजा: इजरायली सरकार के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा, हमास संग बंधकों की रिहाई के समझौते पर वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजा गया है। गुरुवार को यह निर्णय हमास द्वारा चरणबद्ध संघर्ष विराम के अमेरिका समर्थित प्रस्ताव पर नई प्रतिक्रिया के एक दिन बाद आया है।

इस बीच, गाजा में संभावित युद्धविराम समझौते पर हमास की नई स्थिति पर चर्चा के लिए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाने वाले हैं। बैठक से पूर्व वह युद्धविराम वार्ता टीम के साथ परामर्श भी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा मई के अंत में सार्वजनिक किए गए प्रस्ताव पर इजरायल को बुधवार को हमास की ओर से प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें गाजा में रखे गए 120 बंधकों की रिहाई और फलस्तीनी क्षेत्र में युद्धविराम शामिल होगा। एक फलस्तीनी अधिकारी ने कहा, हमास के लचीलापन दिखाने से इजरायल संग समझौते पर पहुंचा जा सकेगा। युद्ध में अब तक 38 हजार से अधिक फलस्तीन मारे गए हैं, जबकि 87,445 घायल हुए हैं।

वेस्ट बैंक की बस्तियों में 5,300 नए घरों की योजना को मंजूरी: इजरायल के एंटी-सेटलमेंट निगरानी समूह का कहना है कि सरकार ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 5,300 नए घर बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। यह वेस्ट बैंक पर इजरायल के नियंत्रण को मजबूत करने और भविष्य में फलस्तीनी बस्तियों की स्थापना को रोकने का नया कदम है।

अस्पताल के भरने के बाद चर्च ने खोला द्वार: सेंट फिलिप चर्च ने अस्पताल के भरने के बाद अपना द्वार घायलों व बीमारों के लिए खोल दिया है। पादरी मुन्थर इसहाक ने कहा, हमारी प्राथमिकता हर इंसान की जान बचाना है। उपलब्ध स्थानों की कमी के कारण प्रार्थना के लिए निर्दिष्ट स्थान को क्लिनिक में बदल दिया गया है।

यूक्रेन का एक और शहर रूस के हाथ आया

- रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चासिव यार पर रूसी सेना का कब्जा
- जेलेंस्की बोले, हमारी 14 ब्रिगेड सेना के पास पर्याप्त हथियार नहीं

डोनेस्ट क्षेत्र के चासिव यार में रूसी सेना के हवाई हमलों में तबाह इमारतों का एरियल व्यू। रायटर

कीव, रायटर : महीनों की लड़ाई के बाद रूसी सेना ने आखिरकार यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत का चासिव यार शहर जीत लिया। यूक्रेन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस शहर से अपनी सेना को वापस बुलाने की घोषणा की है, जबकि रूस ने कहा है कि उसने बुधवार रात शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया था। इस तरह 29 माह से जारी लड़ाई में एक और शहर यूक्रेन के हाथ से निकल गया है। रूस अभी तक यूक्रेन के 20 प्रतिशत से ज्यादा भूभाग पर कब्जा कर चुका है।

रूसी सेना के कब्जे में आया चासिव यार शहर रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इस शहर के हाथ आने से यूक्रेन के दो महत्वपूर्ण शहरों- क्रैमेटोर्स्क व स्लोवियांस्क पर कब्जे की लड़ाई में रूस को आसानी होगी। यूक्रेन ने कहा है कि सैनिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें वापस बुलाना बेहतर समझा गया, इसलिए चासिव यार को छोड़ने का निर्णय लिया गया। रूस समर्थक यूक्रेन के विद्रोहियों का डोनेस्क के एक हिस्से पर 2014 से कब्जा है। फरवरी 2022 से छिड़े युद्ध के बाद रूसी सेना ने इस प्रांत में अपना कब्जा बढ़ाया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उनकी सेना की 14 ब्रिगेड के पास लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं है। इसका रूस को लाभ हो रहा है।

पश्चिम की मिसाइलों पर भारी रूसी एस-350 : रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनका एस-350 एयर डिफेंस सिस्टम पश्चिमी देशों की मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें आकाश में ही नष्ट करने में सक्षम है। कहा,यह सिस्टम पश्चिमी देशों की बैलेस्टिक व क्रूज मिसाइलों को नाकाम करने में सक्षम है। साथ ही लड़ाकू विमानों, हेलीकाप्टर, ड्रोन और 16 इंच तक के हथियार से होने वाले हमलों को भी विफल कर रहा है।

फ्रांस सरकार की प्रवक्ता प्रिस्का थेवेनोट पर चुनाव कैंपेन के दौरान हमला

फ्रांस सरकार की प्रवक्ता प्रिस्का थेवेनोट। फाइल/एएफपी

पेरिस, एपी : फ्रांस सरकार की प्रवक्ता प्रिस्का थेवेनोट पर चुनाव कैंपेन के दौरान हमला बोला गया। पीएम ग्रेबियल अटल ने कहा, सात जुलाई को होने वाले चुनाव से पूर्व थेवेनोट पार्टी कार्यकर्ताओं संग पेरिस में पोस्टर लगवा रही थीं, तभी एक समूह ने हमला कर दिया। इस मामले में तीन किशोरों समेत चार लोगों को हिरासत में लिया गया है।

मीडिया संस्थाओं की ओर से कहा गया है कि हमले में थेवेनोट घायल नहीं हुई हैं और अपना कैंपेन जारी रखेंगी। पार्टी के कार्यकार्ता घायल हुए हैं। अभियोजक कार्यालय की ओर से कहा गया है कि मामले में एक सरकारी अधिकारी पर हमले की जांच की जा रही है। अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमले के पीछे की मंशा क्या थी।

पुतिन मानते हैं बाइडन बनेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति

अस्ताना, रायटर : अमेरिका में हुई सार्वजनिक बहस में भले ही राष्ट्रपति जो बाइडन पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारी पड़े हों लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्राथमिकता बाइडन को लेकर बनी हुई है।

रूस के राष्ट्रपित पुतिन ने कहा, यदि ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो उनका मानना है कि यूक्रेन युद्ध खत्म कराने को लेकर वह गंभीर होंगे। लेकिन वह ऐसा कैसे करेंगे यह पता नहीं है।

एक पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर पुतिन ने कहा, एक बहस में पिछड़ जाने मात्र से बाइडन की उम्मीदवारी पर कुछ नहीं होने जा रहा है। कुछ भी नहीं बदला है। बाइडन को लेकर उनकी सोच नहीं बदली है। पुतिन ने कहा, वह जानते हैं कि अमेरिका में क्या होगा। एक सवाल के जवाब में पुतिन ने कहा, अमेरिका से किसी तरह की वार्ता अब वहां होने वाले चुनाव के बाद ही संभव है। कहा, वह नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद देखा जाएगा कि वहां बनने वाला राष्ट्रपति रूस के बारे में क्या राय रखता है।

आस्ट्रेलियाई संसद की छत पर चढ़े फलस्तीन समर्थक

सुरक्षा को धता बताते हुए गुरुवार को कैनबरा में आस्ट्रेलियाई संसद भवन की छत पर चढ़े फलस्तीन समर्थक। रायटर

कैनबरा, रायटर : आस्ट्रेलिया में गुरुवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया। फलस्तीनी समर्थक सुरक्षा को धता बताते हुए संसद भवन की छत पर चढ़ गए। इस मामले में चार फलस्तीनी समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले सत्तारूढ़ पार्टी के एक सीनेटर ने फलस्तीन को लेकर सरकार के रुख पर इस्तीफा दे दिया था।

प्रदर्शनकारी लगभग एक घंटे तक संसद की छत पर खड़े रहे और उन्होंने काले बैनर लहराए। इसमें फलस्तीन के समर्थन में नारे लिख हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम भूलेंगे नहीं, हम माफ नहीं करेंगे और विरोध करना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने विरोध प्रदर्शन की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों को कानून की ताकत का एहसास होना चाहिए। शांतिपूर्ण विरोध का हमारे समाज में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं था। स्पीकर मिल्टन ने कहा कि सुरक्षा उल्लंघन कैसे हुआ, इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। आस्ट्रेलिया के पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि चारों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है।

मैं ही डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रत्याशी, दौड़ छोड़ने का कोई दबाव नहीं : बाइडन

- चुनाव जीतने पर उठ रहे सवाल के बीच आया बयान
- कहा, हम ट्रंप को 2024 में फिर से हराने जा रहे हैं

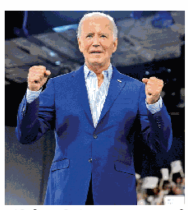

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन। एपी

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार को कहा कि वह पांच नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं और उन पर दौड़ छोड़ने का कोई दबाव नहीं है। बाइडन ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार हूं। कोई मुझे बाहर नहीं कर रहा। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अंत तक दौड़ में शामिल हूं। हम यह चुनाव जीतने जा रहे हैं। पिछले गुरुवार को अटलांटा डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मीडिया और उनकी पार्टी में ही उनके चुनाव जीतने पर सवाल उठने लगे हैं।

बाइडन ने कहा है कि यह अभियान मुझसे या आपसे बड़ा है। जिस चीज पर हम विश्वास करते हैं, जिस चीज के लिए हम खड़े हैं और जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वह सब इस चुनाव में खतरे में है। उन्होंने अपने समर्थकों को भेजे सामूहिक ईमेल में कहा, ''मैं इसे यथासंभव स्पष्ट और सरलता से कह सकता हूं। मैं चुनाव लड़ रहा हूं।'' कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं हार गया हूं। लेकिन मेरे पिता कहा करते थे यह मायने नहीं रखता कि आप कितनी बार हारते हैं।

बाइडन ने अपने ईमेल में आगे लिखा है कि मायने यह रखता है कि आप कितनी जल्दी उठते हैं। एक देश के रूप में जब हम हार जाते हैं, तो फिर से खड़े हो जाते हैं और अधिक मेहनत करते हैं। मैं बिल्कुल यही करने जा रहा हूं और मुझे आपसे भी यही करने की आशा है। ठीक उसी तरह जैसा हमने 2020 में डोनाल्ड ट्रंप को हराया, 2024 में फिर से हराने जा रहे हैं। लेकिन यह आसान नहीं होगा और इसे पूरा करने के लिए मुझे आप सभी की जरूरत है। अगर मुझे पूरे दिल और आत्मा से विश्वास नहीं होता कि मैं यह काम कर सकता हूं, तो मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ता।

जमैका में तबाही मचा मेक्सिको की ओर बढ़ रहा तूफान बेरिल

- मेक्सिको में तूफान से बचाव की हो रही तैयारी
- यह 32 किमी प्रति घंटे की गति से बढ़ रहा

प्लाया डेल कारमेन, एपी : जमैका और पूर्वी कैरेबियन में तबाही मचाने के बाद तूफान बेरिल अब मेक्सिको की ओर बढ़ रहा है। तूफान की भयावहता इसी से समझी जा सकती है कि इसके सामने जमैका में छतें तक नहीं टिकीं।

केमैन द्वीप की ओर बढ़ने से पहले सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में कुछ द्वीपों पर बड़ी संख्या में घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। तूफान को देखते हुए मेक्सिको के कैरेबियाई तट पर अस्थायी आश्रय स्थल तैयार किए गए हैं। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन प्लाया डेल कारमेन और टुलम जैसे नाइटलाइफ हाटस्पाट में पर्यटक अब भी मौजूद हैं। मेक्सिको की नौसेना ने टुलम में गश्त की और पर्यटकों को तूफान को लेकर आगाह किया। तूफान का केंद्र गुरुवार सुबह मेक्सिको के टुलम से लगभग 800 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। 205 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति से निरंतर हवाएं चल रही थीं और यह 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ रहा था।

अनुमान लगाया गया है कि बेरिल शुक्रवार के शुरुआती घंटों में टुलम के दक्षिण में लैगून और मैंग्रोव के एक कम आबादी वाले क्षेत्र में टकराएगा। फिर इसके युकाटन प्रायद्वीप को पार करने और मेक्सिको की खाड़ी पर मजबूत होकर टेक्सास सीमा के पास मेक्सिको के उत्तरपूर्वी तट पर टकराने की ओर जाने की आशंका है। उल्लेखनीय है कि हाल के महीनों में विश्व में कई तूफान आए जिसकी चपेट में आकर कई लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हो गए।

एक कलाकार का सपना

पश्चिमी फ्रांस के डाउनटाउन नैन्टेस में प्रसिद्ध ओपेरा नैन्टेस के सामने प्रदर्शित ब्राजीलियाई आर्टिस्ट हेनरिक ओलिवेरा की कलाकृति 'रे लेवे डे फित्जकाराल्डो'(फिटजकारोल्डो का सपना)। इसमें आर्टिस्ट ने सूखे पेड़ को दिखाया है, जो जमीन से निकलकर बिल्डिंग के सामने लेट गया है। यह कलाकृति वायज ए नैटटेस का हिस्सा है। एएफपी

नेपाल में स्वतंत्र पार्टी प्रधानमंत्री प्रचंड के साथ

- इस्तीफा देने गए चार मंत्रियों का मन बदला, रहेंगे पीएम के साथ

काठमांडू, एएनआइ : नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेताओं ने पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड से भेंट के बाद सरकार के साथ बने रहने का निर्णय लिया है। सरकार में पार्टी के मंत्री गुरुवार को इस्तीफा देने के लिए पहुंचे थे लेकिन पीएम से वार्ता के बाद उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया और अब वे संसद में विश्वास मत के दौरान सरकार का समर्थन करेंगे।

बुधवार को नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) के समर्थन वापसी से प्रचंड सरकार अल्पमत में आ गई है पर पीएम ने इस्तीफा देने से इन्कार करते हुए कहा है कि वह संसद में बहुमत साबित करेंगे। सीपीएन (यूएमएल) का नेपाली कांग्रेस के साथ समझौता हो गया है और सीपीएन नेता केपी शर्मा ओली अब अगले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सीपीएन (यूएमएल) ने प्रचंड से कहा है कि वह कोई ऐसा निर्णय नहीं लें जिसका परिणाम देश पर लंबे समय तक पड़े। उनकी सरकार अल्पमत में आ गई है इसलिए अब वह केवल कामचलाऊ सरकार के मुखिया के तौर पर ही कार्य करें।

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के मुख्य सचेतक संतोष पेरियार ने कहा, हम इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हम पीएम के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास से सहमत हैं, हम संसद में उनका साथ देंगे। पेरियार पार्टी के चार मंत्रियों को इस्तीफा दिलाने के लिए पीएम आवास गए थे। संसद के सदन प्रतिनिधि सभा में स्वतंत्र पार्टी के 20 सदस्य हैं जबकि प्रचंड की पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) के 32 सदस्य हैं। 275 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा में 89 सदस्य नेपाली कांग्रेस के हैं। प्रचंड सरकार के समर्थन वापस लेने वाली सीपीएन (यूएमएल) के 78 सदस्य हैं।

****

T20 आइसीसी विश्व कप अमेरिका व वेस्टइंडीज 2024

विश्व विजेता

एक नजर में

गुकेश ने कारुआना को बराबरी पर रोका

बुखारेस्ट: विश्व चैंपियनशिप के चैलेंजर ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने यहां सुपरबेट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट के सातवें दौर में शीर्ष पर चल रहे अमेरिका के फाबियानो कारुआना को बराबरी पर रोका। एक बार फिर दिन की सभी बाजियां ड्रा रहीं। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रगनानंद ने रूस के इयान नेपोम्नियाची के साथ अंक बांटे। अंतिम स्थान पर चल रहे रोमानिया के डिएक बोगडेन-डेनियल ने फिरोजा के साथ ड्रा खेला जबकि गिरी ने वाचियेर-लाग्रेव के साथ बाजी ड्रा की। शीर्ष वरीय कारुआना दो जीत और पांच ड्रा से 4.5 अंक के साथ शीर्ष पर बरकरार हैं। उनके बाद गुकेश, प्रगनानंद और अलीरेजा हैं जो अमेरिकी से आधा अंक पीछे हैं। (प्रेट्र)

नाडा ने 400 मीटर धाविका दीपांशी को किया निलंबित

नई दिल्ली: नाडा ने हाल में राष्ट्रीय अंतर राज्यीय चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की शीर्ष महिला 400 मीटर धाविका दीपांशी को डोप जांच में विफल होने के कारण निलंबित किया। दीपांशी (21 वर्ष) ने शुक्रवार को पंचकूला में महिलाओं के 400 मीटर फाइनल में किरण पहल (50.92 सेकेंड) के बाद 52.01 सेकेंड के समय से दूसरा स्थान प्राप्त किया था। टूर्नामेंट के दौरान लिए गए डोप नमूने में 'एनाबोलिक स्टेरायड' मिला है। ये नमूने 27 जून को लिए गए। राष्ट्रीय अंतरराज्यीय चैंपियनशिप (27 से 30 जून) में यह पहला डोप पाजिटिव मामला सामने आया है, जो ओलिंपिक के लिए अंतिम क्वालीफाइंग टूर्नामेंट भी था। (प्रेट्र)

पंकज आडवाणी ने सिद्धार्थ पारिख को दी शिकस्त

रियाद: भारत के शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए सिद्धार्थ पारिख को 4-2 से हराकर एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में खिताब की हैट्रिक की ओर कदम बढ़ाए। मैच में पारिख ने शानदार शुरुआत करते हुए पहला फ्रेम 101-38 से जीता। दूसरे फ्रेम में कड़ा मुकाबला देखने को मिला लेकिन पारिख ने 100-99 से आडवाणी को हराकर 2-0 की बढ़त बनाई। आडवाणी ने दो फ्रेम से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए तीसरा फ्रेम 101-0 से जीता। (प्रेट्र)

राजावत ने गेम्के को हराया

कैलगेरी: उभरते हुए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत ने यहां कनाडा ओपन के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में अपने से बेहतर रैंकिंग वाले डेनमार्क के रासमुस गेम्के को हराया। विश्व के 39वें नंबर के खिलाड़ी राजावत ने बुधवार रात आठवें वरीय गेम्के को तीन गेम तक चले कड़े मुकाबले में एक घंटे और 10 मिनट में 17-21, 21-16, 21-14 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। राजावत अब पुरुष सिंगल्स में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बचे हैं। जगह बनाने में सफल रहीं। (प्रेट्र)

बाबर ने यंग से मदद मांगी

लाहौर: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने हाल ही में समाप्त हुए विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अपने टी-20 कौशल को फिर से तराशने के लिए प्रसिद्ध आस्ट्रेलियाई पावर हिटिंग कोच शेनन यंग की सहायता मांगी है। बाबर ने टी-20 विश्व कप के चार मैचों में 120 रन बनाए। पाकिस्तान सुपर आठ में प्रवेश नहीं कर पाया और पहले दौर से बाहर हो गया (प्रेट्र)

प्रधानमंत्री से लेकर आमजन तक ने विश्व चैंपियनों पर लुटाया बेशुमार प्यार

प्रधानमंत्री आवास में विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ● प्रेट्र

वानखेड़े स्टेडियम के बाहर विजय जुलूस के दौरान चैंपियंस को लेकर जा रही बस को घेरे प्रशंसक ● एएफपी

14000 किलोमीटर का विजयी सफर

विश्व कप जीतने के बाद बारबाडोस से विशेष विमान से स्वदेश पहुंची भारतीय टीम

अभिषेक त्रिपाठी ● जागरण
टीम के विशेष विमान से

मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी 15 घंटे 30 मिनट में 14000 किलोमीटर का सफर बिना सोए करूंगा। मैं ही नहीं विश्व विजयी कप्तान रोहित शर्मा सहित पूरी भारतीय टीम, मुख्य कोच राहुल द्रविड़ सहित उनका सहयोगी स्टाफ, बीसीसीआइ सचिव जय शाह, अध्यक्ष रोजर बिन्नी, स्टार स्पोर्ट्स के कुछ क्रू मेंबर और बाकी खेल पत्रकारों ने भी इस लंबे सफर में कुछ ही देर अपनी पलकें झपकाई होंगी क्योंकि उस फ्लाइट में जो हो रहा था उसका एक भी पल कोई छोड़ना नहीं चाहता था। सब चाहते थे कि 13 साल बाद विश्व कप ट्राफी जीतने वाली भारतीय टीम के साथ बिताए हर पल को आंखों में कैद कर लिया जाए। शायद वहां हुई हर बात को मैं यहां लिख भी न पाऊं क्योंकि वहां जो हो रहा था उसे शब्दों में पिरोना शायद आज मेरे बस की भी बात नहीं है। पहली बार भारतीय टीम ने सीधे किसी कैरेबियाई देश से भारत का सफर किया। इससे पहले टीम लंदन या न्यूयार्क से फ्लाइट बदलकर जाती थी।

जय शाह का बड़ा कदम : भारतीय टीम 29 जून को विश्व कप ट्राफी जीतकर हिल्टन होटल पहुंच गई। वह भारत निकलने के लिए तैयार थी लेकिन बारबाडोस सरकार ने बेरिल तूफान के कारण अगले ही दिन रविवार शाम से ग्रांटली एडम्स हवाई अड्डे को बंद करने का निर्णय लिया। कुछ देर पहले बीसीसीआइ सचिव जय शाह ने टीम की जीत को लेकर बातचीत करने के लिए भारतीय पत्रकारों को टीम होटल बुलाया था। ये जय ही थे जिन्होंने रोहित, विराट और हार्दिक पांड्या जैसे सीनियर खिलाड़ियों को टीम में रखने के निर्णय पर मुहर लगाई, जिसका फल भारत को ट्राफी के तौर पर मिला। कई पत्रकारों की भी फ्लाइट रद हो चुकी थीं। इसके बाद की फ्लाइट सात जुलाई की मिल रही थीं। जब जय को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि हम देखते है। आप सबको यहां से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। जय खुद अपनी फ्लाइट छोड़कर टीम भारत के लिए रुके थे क्योंकि वह भारतीय टीम को तूफान में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से भी इस बारे में पूछा और उन्होंने भी इस निर्णय का समर्थन किया।

मुश्किलें कम नहीं हो रही थीं : बीसीसीआइ किसी भी तरह भारतीय टीम को बारबाडोस से निकालने के लिए प्रयासरत था। उसने एयर इंडिया के एक चार्टर को बुक किया, लेकिन वह तकनीकी कारण से सैन फ्रांसिस्को से उड़ान नहीं भर सका। फिर दूसरा चार्टर न्यूयार्क से बुलाया गया। यह तय हुआ कि टीम बारबाडोस से दो जुलाई को छह बजे (स्थानीय समयानुसार) निकलेगी और तीन तारीख को शाम 7.45 पर दिल्ली पहुंच जाएगी लेकिन दो बार समय आगे बढ़ा और टीम तीन जुलाई को सुबह 4.30 (स्थानीय समयानुसार) पर बारबाडोस से दिल्ली के लिए रवाना हुई।

शुरू हुआ अनोखा सफर : करीब 22 खेल पत्रकार, भारतीय टीम और अन्य लोग तीन जुलाई की सुबह बारबाडोस एयरपोर्ट पहुंचे। मैंने सूर्य कुमार से उनकी कैच को लेकर पूछा, उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान इस बात पर था कि किसी तरह सिर्फ दो रन जाने दूं लेकिन कैच का प्रयास सफल हो गया। विराट कोहली पीछे इकोनामी में पूछने आए जगह खाली हैं क्या। राहुल द्रविड़ इकोनामी में आकर सो गए। इस पूरे यादगार सफर के बाद गुरुवार सुबह छह भारतीय टीम का विशेष विमान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरा। यहां जय शाह ने केक काटकर भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाया।

होटल में प्रवेश करने के बाद ढोल की थाप पर थिरकते रोहित ● सौ.आइटीसी

चैंपियंस को लेकर आ रही विशेष विमान हुआ सर्वाधिक ट्रैक

नई दिल्ली, जेएनएन : टी-20 विश्व कप 2024 की विजेता भारतीय टीम को बारबाडोस से दिल्ली लेकर पहुंची एअर इंडिया की विशेष चार्टर प्लेन ने रिकार्ड बना दिया। एअर इंडिया चैंपियन 24 वर्ल्ड कप को ट्रैक करने वाली एक कंपनी फ्लाइट रेडार 24 ने एक्स के माध्यम से बताया कि बारबाडोस से दिल्ली पहुंची इस फ्लाइट को सबसे अधिक लोगों ने ट्रैक किया। फ्लाइट रेडार 24 कंपनी ने एक्स पर बताया 'उस प्लेन को सबसे अधिक ट्रैक किया गया, जिसमें टी-20 विश्व कप 2024 की चैंपियन भारतीय टीम सवार थी।'

दिल्ली से मुंबई तक 'अविश्वसनीय' स्वागत

मुंबई, प्रेट्र : चैंपियन का ऐसा अद्भुत, अतुलनीय और अविश्वसनीय स्वागत न तो कभी देखा गया था और ना ही हमारे देश के अलावा कहीं और देखा जा सकता है, क्योंकि यहां क्रिकेट महज एक खेल नहीं बल्कि 'जुनून' है। चाहे दिल्ली हो या मुंबई, बारिश के बावजूद प्रशंसकों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई।

सुबह छह बजे भारतीय टीम दिल्ली पहुंची, जहां गातार बूंदाबादी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रशंसकों ने खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे सैकड़ों प्रशंसक मौसम की परवाह किए बिना विभिन्न नारे लिखे बैनर और राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे थे। शाम को टीम नई दिल्ली से टीम इंडिया मुंबई पहुंची, जहां सड़कों पर लाखों फैंस जुटे थे। स्वागत के लिए विजय परेड में गुरुवार को मरीन ड्राइव जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिससे दक्षिण मुंबई का यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से अनुसार विजय परेड नरीमन प्वाइंट से शाम पांच बजे शुरू होकर वानखेड़े स्टेडियम में शाम सात बजे समाप्त होना था, लेकिन रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम नई दिल्ली से देर से यहां पहुंची, जिससे परेड सात बजकर 30 मिनट के बाद ही शुरू हो पाई। इस विजय परेड का साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी मरीन ड्राइव पर पहुंच गए। मुंबई यातायात पुलिस को लोगों को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़े। मुंबई पुलिस ने मरीन ड्राइव पर जाने से रोकने को लेकर कई अलर्ट जारी किए, लेकिन इसके बावजूद लोग वहां पहुंचे और वर्षा के बावजूद डटे रहे। मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम का करीब एक किलोमीटर है, लेकिन यहां इतने लोग इकट्ठा थे कि खुली बस में सवार टीम को स्टेडियम पहुंचने के लिए डेढ़ घंटे से भी ज्यादा का समय लगा। वानखेड़े स्टेडियम को प्रशंसकों के लिए शाम चार बजे ही खोल दिया गया था। खचाखच भरे स्टेडियम में भारतीय टीम को सम्मानित किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाव से जीता दिल

नई दिल्ली, जेएनएन : टी-20 विश्व कप 2024 की विजेता भारतीय क्रिकेट टीम ने गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ियों के अलावा बीसीसीआइ अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सचिव जय शाह और टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ भी थे। प्रधानमंत्री के साथ खिलाड़ियों की मुलाकात अद्भुत रही और इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने भाव से लोगों का दिल भी जीत लिया।

जब पीएम और खिलाड़ियों की विश्व कप ट्राफी के साथ फोटो ली गई तो प्रधानमंत्री ने ट्राफी को हाथ में नहीं लिया। प्रधानमंत्री ने बराबर में खड़े कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ के हाथों में थमा दी। ट्राफी को राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने पकड़ा हुआ था जबकि प्रधानमंत्री इन दोनों दिग्गजों के हाथ पकड़े हुए थे। इस तरह नरेन्द्र मोदी फोटो के केंद्र में होने के बावजूद ट्राफी स्वयं नहीं पकड़े थे। पीएम का संदेश स्पष्ट है कि जिस ट्राफी को देश लाने के लिए जिन खिलाड़ियों और कोच ने असल मेहनत की है, उसका श्रेय भी उन्हीं को दिया जाना चाहिए।

चैंपियंस के साथ बेहतरीन मुलाकातः नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली, जेएनएन : टी-20 विश्व कप ट्राफी जीतकर घर लौटी टीम भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गुरुवार को उनके आवास पर पहुंची। प्रधानमंत्री ने करीब दो घंटे तक कोच द्रविड़ समेत पूरी टीम के खिलाड़ियों से बात की। भेंट के बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर तस्वीरें साझा कीं। पीएम मोदी ने तस्वीर साझा कर लिखा, चैंपियंस के साथ एक बेहतरीन मुलाकात हुई।'

हमारे स्वागत के लिए उमड़े प्रशंसकों के जनसमुद्र ने यह दर्शा दिया कि हमारी तरह टी-20 विश्व कप ट्राफी जीतने के लिए वह भी उतने ही बेताब थे।
- **रोहित शर्मा**, भारतीय टीम कप्तान

मैं उस रात जब 2011 विश्व कप जीतने के बाद वरिष्ठ खिलाड़ी रो रहे थे, उनकी भावनाओं को नहीं समझ सका था, लेकिन अब मैं उसे समझ सकता हूं। 15 वर्षों में पहली बार मैंने रोहित को इतना भावुक होते देखा है।
- **विराट कोहली**, भारतीय बल्लेबाज

मुझे मिला यह प्यार बहुत याद आएगा। आज जो मैंने सड़कों पर देखा, मैं कभी इसे भूल नहीं पाऊंगा।
- **राहुल द्रविड़**, भारतीय क्रिकेट कोच

मैंने आज जो देखा, आज तक इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था।
- **जसप्रीत बुमराह**, तेज गेंदबाज

दिल्ली पहुंचने पर हवाई अड्डे पर रोहित को केक खिलाते जय शाह ● आइएएनएस

मुंबई एयरपोर्ट पर टीम के विमान को वाटर सैल्यूट दिया गया ● एक्स

मुंबई में टीम के स्वागत में खड़े प्रशंसक ● एएनआइ

बोपन्ना-एब्डेन की जोड़ी दूसरे दौर में

पुरुष डबल्स के पहले दौर में भारत के बोपन्ना व आस्ट्रेलियाई जोड़ीदार एब्डेन की रोबिन हास और सैंडर एरेंड्स की जोड़ी पर आसान जीत

लंदन, प्रेट्र: भारत के रोहन बोपन्ना और उनके आस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एब्डेन ने यहां रोबिन हास और सैंडर एरेंड्स की जोड़ी पर आसान जीत के साथ विंबलडन के पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में प्रवेश किया।

बोपन्ना और एब्डेन ने बुधवार को वर्षा से बाधित पहले दौर के मुकाबले में एक घंटे 11 मिनट में नीदरलैंड्स के अपने प्रतिद्वंद्वियों को 7-5, 6-4 से हराया। आस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियन दूसरी वरीयता प्राप्त बोपन्ना और एब्डेन की जोड़ी दूसरे दौर में हेंड्रिक जेबेंस और कांसटेंटिन फ्रेंटजन की जर्मनी की जोड़ी से भिड़ेगी। बोपन्ना और एब्डेन पिछले वर्ष सत्र के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचे थे। इससे पहले बुधवार को भारत के सुमित नागल और उनके सर्बियाई जोड़ीदार दुसान लाजोविक को पहले दौर में स्पेन के पेड्रो मार्टिनेज और जामे मुनार के विरुद्ध हार का सामना करना पड़ा। मार्टिनेज और मुनार ने एक घंटे सात मिनट में 6-2, 6-2 से जीत दर्ज की। पुरुष डबल्स के पहले दौर में एन श्रीराम बालाजी और युकी भांबरी भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बालाजी ने ब्रिटेन के ल्यूक जानसन के साथ जोड़ी बनाई है। ये दोनों गुरुवार को सर्बिया के मेट पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की चौथी वरीय जोड़ी से भिड़ेंगे। महिला सिंगल्स में चार बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका को दूसरे दौर में 19वें नंबर की ऐमा नवारो ने 6-4, 6-1 से हराकर बाहर कर दिया।

रोहन बोपन्ना ● फाइल फोटो

भांबरी-ओलिवेटी की जोड़ी जीती

भारत के युकी भांबरी और फ्रांस के उनके जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी ने यहां पुरुष डबल्स स्पर्धा के दूसरे दौर में प्रवेश किया जबकि ओलिंपिक दल के सदस्य एन श्रीराम बालाजी और ल्यूक जानसन की जोड़ी विंबलडन चैंपियनशिप से बाहर हो गई। भांबरी और ओलिवेटी की जोड़ी ने कजाखस्तान के एलेक्जेंडर बुबलिक और एलेक्जेंडर श्वेचेंको की जोड़ी को 58 मिनट में 6-4, 6-4 से पराजित किया। अब भांबरी और ओलिवेटी का सामना जर्मनी के केविन क्राविट्ज और टिम पुएट्ज की जोड़ी से होगा।

फ्रांस और पुर्तगाल के मैच में टकराएंगे दिग्गज

स्टुटगार्ट, एपी : यूरो चैंपियनशिप में शुक्रवार को पुर्तगाल और फ्रांस के बीच होने वाले मैच में दिग्गज खिलाड़ी टकराएंगे। इस दौरान सभी की नजरें पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और फ्रांस के स्टार खिलाड़ी कायलियन एमबापे पर होंगी। यह मैच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही टीम प्रबल दावेदार होने के बावजूद अब तक एक भी प्रभावशाली जीत प्राप्त नहीं कर सकी है।वहीं, एक अन्य क्वार्टर फाइनल में स्पेन की युवा टीम और मेजबान जर्मनी की टीम आमने-सामने होगी। सर्वाधिक तीन-तीन बार चैंपियन बनने वाली दोनों टीमें अपने चौथी ट्राफी की तलाश में हैं। इस दौरान दोनों टीमों के सबसे युवा खिलाड़ी जर्मनी के जमाल मुसियाला और स्पेन के लमीन यमाल पर सभी की नजरें होंगी, जिन्होंने अपने कौशल से सभी को प्रभावित कर दिया है।

आज के मैच

स्पेन vs जर्मनी	
रात 9.30 बजे	स्थानः स्टुटगार्ट
पुर्तगाल vs फ्रांस	
रात 12.30 बजे	स्थानः हैम्बर्ग
सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर	

अर्जेंटीना के सामने इक्वाडोर

ह्यूस्टन, एपी : स्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी के पैर में लगी चोट के कारण क्वार्टर फाइनल में आज इक्वाडोर के विरुद्ध उनका खेलना संदिग्ध है। पेरू के विरुद्ध मैच के दौरान उन्हें पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें बाहर जाना पड़ा था। वह तब से नहीं खेल सके हैं, हालांकि कोच स्कालोनी ने बताया कि वह इक्वाडोर के विरुद्ध उतर सकते हैं, हम अंतिम निर्णय मैच से पहले लेंगे। 15 बार की चैंपियन अर्जेंटीना ने टूर्नामेंट में ग्रुप चरण के अपने सभी मैच जीते हैं।

एथलेटिक्स टीम की अगुआई करेंगे नीरज

21 दिन शेष पेरिस ओलिंपिक

नई दिल्ली, प्रेट्र : वर्तमान ओलिंपिक चैंपियन भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलिंपिक में भारत की 28 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की अगुआई करेंगे। टोक्यो ओलिंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले और वर्तमान विश्व चैंपियन चोपड़ा ने पेरिस ओलिंपिक की तैयारी के सिलसिले में डायमंड लीग के अंतिम चरण में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है।

एएफआइ के अनुसार, ओलिंपिक के लिए एथलेटिक्स टीम में 17 पुरुष और 11 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। टोक्यो में स्वर्ण जीतने वाले नीरज चोपड़ा के अलावा इनमें एशियाई खेलों के चैंपियन अविनाश साबले, तेजिंदरपाल सिंह तूर और बाधा दौड़ के धावक ज्योति याराजी जैसे अन्य प्रमुख खिलाड़ी भी शामिल हैं। वहीं, पुरुषों की चार गुणा 400 मीटर रिले टीम में मोहम्मद अनस, मोहम्मद अजमल, अमोज जैकब और राजेश रमेश शामिल हैं। इस टीम ने हाल में विश्व चैंपियनशिप में अमेरिका की टीम को कड़ी टक्कर देकर सनसनी मचा दी थी। पेरिस ओलिंपिक में ट्रैक एवं फील्ड की स्पर्धाएं एक अगस्त से 11 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी।

नीरज चोपड़ा ● फाइल फोटो, एएफपी

पेरिस ओलिंपिक के लिए एथलेटिक्स टीम

पुरुष: अविनाश साबले (3,000 मीटर बाधा दौड़), नीरज चोपड़ा, किशोर जेना (भाला फेंक), तजिंदरपाल सिंह तूर (गोला फेंक), प्रवीण चित्रवेल, अबुल्ला अबूबकर (ट्रिपल जंप), अक्षदीप, विकास, परमजीत बिष्ट (20 किमी पैदल चाल), अनस, अजमल, अमोज जैकब, संतोष तमिलारासन, राजेश रमेश, मिजो चाको कुरियन (4×400 मीटर रिले), सूरज पंवार (पैदल चाल), सर्वेश कुशारे (ऊंची कूद)। **महिला:** किरण पहल (400 मीटर), पारुल चौधरी (3,000 मी. स्टीपलचेज) और 5,000 मी. स्टीपलचेज ज्योति याराजी (100 मीटर बाधा दौड़), अन्नू रानी (भाला फेंक), आभा खटुआ (गोला फेंक), ज्योतिका, सुभा, विथ्या रामराज, पूवम्मा एमआर (4×400 मीटर रिले), प्राची (4×400 मीटर), प्रियंका गोस्वामी (20 किमी पैदल चाल)।

नीरज ने सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए किया प्रेरितः धिनिधि

बेंगलुरु, प्रेट्र: हांगझू एशियाई खेल 2022 के दौरान एक कैफे में नीरज चोपड़ा से हुई छोटी सी मुलाकात ने तैराक धिनिधि देसिंघु को अपने खेल में अव्वल रहने के लिए प्रेरित किया और अब वह इस ओलिंपिक और विश्व चैंपियन भालाफेंक स्टार के साथ पेरिस ओलिंपिक जा रहे भारतीय दल में सबसे युवा खिलाड़ी हैं।

****

दैनिक जागरण
सप्तरंग
मनोरंजन की दुनिया का
शुक्रवार, 5 जुलाई, 2024

मुलाकात

अमेजान प्राइम वीडियो पर आज से उपलब्ध होगा वेब शो मिर्जापुर का तीसरा सीजन। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कालीन के व्यवसाय की आड़ में मादक पदार्थों व हथियारों का गैरकानूनी धंधा चलाने वाले अरवंडानंद त्रिपाठी को शहर कालीन भैया के नाम से जानता है। पिछले सीजन में उन्हीं की तरह गैरकानूनी हिंसा से उनके साम्राज्य का अंत करते दिखे गुड्डू पंडित। नए सीजन में पता चलेगा कि क्या कालीन भैया अपनी सत्ता वापस पा सकेंगे या गुड्डू पंडित को मिलेगी उनकी गद्दी। शो में हिंसा दिखाने व अपशब्दों के प्रयोग को लेकर सवाल तो खड़े हुए, पर लोकप्रियता भी खूब मिली। कालीन भैया का पात्र निभाने वाले पंकज त्रिपाठी व गुड्डू पंडित बने अली फजल से शो को लेकर प्रियंका सिंह की बातचीत के अंश...

पूर्वांचल की बोली में है मिठास

क्या मिर्जापुर शो को लेकर कहा जा सकता है कि कंटेंट और पात्र कलाकारों से बड़े हो गए हैं?

अली: हां, यह बात सही है। शो का जो कंटेंट है, उसके कारण कलाकारों का कद बढ़ा है। एक आत्मविश्वास आ जाता है कि यह तो हमने किया है, अब इसके साथ दूसरे कंटेंट में भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं इस शो को अपने जीवन में स्तंभ की तरह देखता हूं। जो मुझे कुछ न कुछ (प्रसिद्धि, पैसा) देता रहता है। हालांकि इसके बाद दूसरा शो कर नहीं पाया हूं क्योंकि यह बहुत वक्त और ऊर्जा ले लेता है।

पंकज: निःसंदेह कंटेंट बड़ा हो गया है। लोग पूछते रहते थे कि नया सीजन कब आ रहा, पर मेरे पास उत्तर नहीं होता था। हमें भी प्रदर्शन से एक हफ्ता पहले ही पता चलता है। फिर रणनीति बनानी पड़ती है। तारीख पता होने के बाद भी दर्शकों की जिज्ञासा बनाए रखना आवश्यक होता है। बीवी और बच्चों को भी बताने में झिझकते हैं कि कहीं कहानी लीक न हो जाए।

कालीन भैया की गद्दी के लिए दावेदारी है, लेकिन क्या कभी पात्रों के लिए दावेदारी करनी पड़ी है?

पंकज : (हंसते हुए) जब घूम-घूमकर आडिशन देते थे तो वह दावेदारी ही तो थी। मैं अपनी तरफ से यही कहता था कि पात्र के लिए उपयुक्त हूं, लेकिन काम नहीं मिलता था। उस समय हमारी दावेदारी चलती नहीं थी।

अली: अब सब कुछ गठबंधन वाला काम हो गया है। निर्देशक कलाकारों से इनपुट लेते हैं।

हमारे सुझाव को ऊपर रखते हैं, उन पर अमल करते हैं, इन कारणों से दावेदारी अब नहीं करनी पड़ती है। शो में कई ऐसे दृश्य रखे गए हैं, जो पटकथा लेखन के समय नहीं सोचे गए थे।

गुड्डू पंडित का पात्र कहता है कि वायलेंस हमारी यूएसपी (हिंसा हमारी पहचान) है। शो में वे सब चीजें हैं, जो सिनेमा में सेंसरशिप के दायरे में आती हैं। क्या आप स्वयं सोचते हैं कि इस सीमा से आगे नहीं जाऊंगा?

अली: हां, मेरी सीमा है। मैं चाहे जितना भी पात्र में रम जाऊं, मेरे जो मूल्य हैं, वो नहीं बदलेंगे। मुझे फिर पात्र और अपने मूल्यों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। फिर उसका तर्क मैं स्वयं उस पात्र की दुनिया में निकालता हूं। हिंसा और अपशब्दों को लेकर दूसरे सीजन के दौरान भी निर्देशक के साथ काफी विचार-विमर्श हुआ था, जहां मैंने एक भी गाली नहीं दी थी। तीसरे सीजन में पात्र में कुछ बदलाव आया है। जहां आवश्यकता थी, वहां थोड़ा प्रयोग किया गया है।

लेकिन कई बार कहा जाता है कि ओटीटी ही एक प्लेटफार्म है, जहां पर थोड़ी स्वतंत्रता है....

पंकज: मैं मानता हूं कि कंटेंट को बांधना नहीं चाहिए, लेकिन दृश्यों का औचित्य साबित करना जरूरी है। पहले सीजन में कालीन भैया का पत्नी बीना संग बेडरूम दृश्य रखा गया था। दर्शकों को बताना था कि बाहर भले ही कालीन भैया का भौकाल है, लेकिन उसके नितांत पारिवारिक जीवन में समस्या है। वह दृश्य कहानी को दिशा देने के लिए जरूरी था। कई लोगों को लगता है कि ओटीटी पर सेंसरशिप नहीं है तो दृश्यों को सनसनीखेज बनाओ। मैं इसके खिलाफ हूं। अगर उस दृश्य या गाली के बिना कहानी पूरी नहीं हो सकती है तो फिर करिए। दृश्य से सनसनी फैलाना इरादा नहीं होना चाहिए।

अली: मिर्जापुर को सफलता मिली तो लोगों को लगा कि इस फार्मूले का प्रयोग करो, पर कोई नियम नहीं है। पूरा खेल पसंद से जुड़ा है। विविधतापूर्ण कंटेंट एक क्लिक पर उपलब्ध है। अपनी पहचान बनाए रखनी है तो दर्शकों को कुछ अलग परोसना ही होगा।

अली फजल कहते हैं कि मिर्जापुर और गुड्डू पंडित के पात्र ने उन्हें बतौर कलाकार मजबूती देने के साथ ही जोखिम लेने और प्रयोग करने का आत्मविश्वास दिया।

कालीन भैया की नैतिकता

पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि कालीन भैया के पात्र की भी सीमाएं हैं। अपने मूल्य और नीतियां हैं। पहला और दूसरा सीजन देखें तो मैंने ज्यादा हिंसा और अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया है। कुछ संवादों में अपशब्द हैं, क्योंकि वहां भाव का अभाव था। भाव के अभाव में ही गालियों का आविष्कार हुआ है, उसके लिए दूसरे शब्द नहीं बने हैं। बाकी पूर्वांचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश) की गालियों में बहुत रस भी है। वे आम जीवन और बोलचाल का ही हिस्सा हैं। आप बनारस के आसपास जाएंगे तो एक मिठास और अपनत्व की भावना मिलती है।

● सभी फोटो: टीम अमेजान प्राइम

मेरी बात

बतौर खलनायक शुरू होगा सफर

बतौर डांसर पहचान बनाने के बाद अब अभिनय में सक्रिय राघव जुआल आज प्रदर्शित हो रही फिल्म किल में खलचरित्र में दिखेंगे...

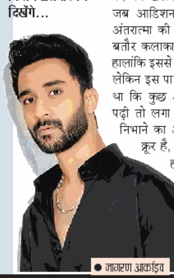

● जागरण आर्काइव

फिल्म किल को राघव जुआल बेहद खास मानते हैं। इसमें पहली बार उन्हें खलनायक बनने का अवसर मिला है। फिल्म से जुड़ाव को लेकर राघव कहते हैं कि हमेशा से मन था कि पर्दे पर खलनायक की भूमिका निभाऊं। जब आडिशन का पहला सीन पढ़ा तो अंतरात्मा की आवाज आई कि यह पात्र बतौर कलाकार नई यात्रा आरंभ करेगा। हालांकि इससे पहले भी मैंने फिल्में की हैं, लेकिन इस पात्र को लेकर समझ आ गया था कि कुछ अलग होगा। जब पटकथा पढ़ी तो लगा कि उसमें बहुत सारे शेड निभाने का अवसर मिलेगा। पात्र बहुत क्रूर है, लेकिन उसे जीवंत बनाना हमारा काम है। मुझे एक्शन करने में काफी मजा आया। शाह रुख सर ने भी टीवी पर एंकरिंग की थी। फिर फिल्म में खलनायक के तौर पर उनकी यात्रा का आरंभ हुआ। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। एंकरिंग के बाद अब फिल्म में खलनायक बनने का अवसर मिला है। यह साम्य अच्छा लगता है। (मुस्कुराते हुए) सपने वही शाह रुख वाले ही हैं।

फिल्म में हिंसा दिखाए जाने की चर्चा है। राघव कहते हैं कि यह सिनेमा है, कहानी है। हम किसी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहे हैं। एक नैतिक आधार पर एक फौजी मेरे पात्र के साथ लड़ रहा है। उसकी अपनी वजहें हैं। फिल्म इंडस्ट्री की कौन ऐसी चीजें हैं जिन्हें किल (समाप्त) कर देना चाहिए? राघव कहते हैं पहला फिल्म शूट कर लो उसके बाद सीधे थिएटर में दिखा दो। (हंसते हुए) प्रमोशन किल करना चाहिए। दरअसल, उसके लिए खास तैयार होना पड़ता है। एक चीज और किल होनी चाहिए कि सबको हिंदी आती है तो फालतू में अंग्रेजी न बोलें।

स्मिता श्रीवास्तव

दिल से

पोस्टर पर दिखना है

एनिमल जैसी सुपरहिट फिल्म में नायक की बहन रीत की छोटी लेकिन प्रभावशाली भूमिका निभाने के बाद अभिनेत्री **सलोनी बत्रा** की अपेक्षाएं भी काफी बढ़ गई है। अब वह ऐसे प्रोजेक्ट करना चाहती हैं, जहां उन्हें केंद्रीय भूमिकाएं निभाने और पोस्टर पर आने के मौके मिलें। इस क्रम में वह जियो सिनेमा पर हालिया प्रदर्शित वेब सीरीज गांठ में केंद्रीय भूमिका में नजर आईं। सलोनी कहती हैं, 'एनिमल के बाद मुझे काफी प्यार और पहचान मिली है। निर्माता-निर्देशक गंभीरता से लेने लगे हैं। बतौर कलाकार कई दरवाजे खुले हैं। गांठ में केंद्रीय भूमिका मिलने के साथ ही अपने सपनों की ओर बढ़ने लगी हूं।'

जीवन की किस गांठ को सुलझाने में सबसे ज्यादा समय लगा? सलोनी बताती हैं, 'जीवन के हर पड़ाव पर आपको एक नई गांठ सुलझाने के लिए मिलती है। यही तो जीवन है। ऐसा कभी नहीं होता कि जीवन में कोई समस्या न हो। हम किसी न किसी गांठ को सुलझाते हुए आगे बढ़ते हैं। हां, एक सवाल मैं हमेशा स्वयं से पूछती रहती हूं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? शायद मैं यह गांठ भी कभी सुलझा पाऊं।' आगे की योजनाओं पर सलोनी कहती हैं, 'अब मैं ऐसी कहानियों का हिस्सा बनना चाहती हूं, जिनमें मेरी भूमिका महत्वपूर्ण हो। (हंसते हुए) सीधे-सीधे बात कहूं तो अब मुझे चाहिए मुख्य भूमिकाएं। मुझे पोस्टर पर आने वाले काम चाहिए।'

दीपेश पांडेय

वर्ग पहेली-2681

बाएं से दाएं
4. पक्षी, पंछी, खग (3)। 5. वृक्ष, पेड़ (3)। 7. दल परिवर्तन (2,3)। 8. विश्वासघाती, धोखेबाज (4)। 10. मिथ्या बात, धारा रूप में चलाना (3)। 11. मक्खन (3)। 14. तट, तीर (3)। 15. निर्वाचन संबंधी अधिकार प्राप्त व्यक्ति, सयाना (3)। 16. अनेक लोग (4)। 17. भाड़े पर लेनेवाला (5)। 20. करुणा, दया (3)। 21. प्रविष्ट, शामिल (3)।

ऊपर से नीचे
1. डुगडुग ध्वनि उत्पन्न करना (5)। 2. संख्या, अंक (3)। 3. मधु (3)। 6. सैनिक दल, सैनिकों का समूह (4)। 8. जोर की चिल्लाहट, गर्जन (3)। 9. तरल पदार्थ को ठोस बनाना, युग (3)। 12. बिगड़ा हुआ, हीन (3)। 13. सोना, निद्रा (3)। 14. भूमिका (4)। 15. भारी, महत्व का (5)। 18. राजा होने का भाव (3)। 19. छिपी हुई बात, गुप्त बात (3)।

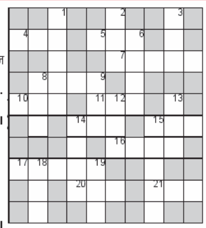

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

आ	प	रा	जि	त	■	मु	ह	जो	र
न	■	य	■	र	■	■	ड	■	ख
श	रा	ब	■	मी	ल	का	प	त्थ	र
न	■	हा	कि	म	■	र	■	■	खा
■	■	दु	■	■	■	क	ल	र	व
म	धु	र	ता	■	■	■	घु	■	■
नो	■	■	री	■	वि	धा	ता	■	ह
र	ग	नि	ख	र	ना	■	बा	च	क
ज	■	क	■	■	श	■	च	■	ला
क	चो	ट	ना	■	क	ड़	क	ड़ा	ना

जागरण सुडोकू-2681

8		1		5			3	
9		2		3			8	
	7		8		1	2		6
		4	6		2	8		5
	9				4		6	
5	8			1				2
1	3		7				4	
		9		6			2	8
6			9		8	7		

कल का हल

5	7	3	2	9	6	1	4	8
6	4	8	1	7	5	3	9	2
1	9	2	4	3	8	5	7	6
9	1	4	3	8	2	7	6	5
3	8	7	5	6	1	4	2	9
2	6	5	9	4	7	8	1	3
7	3	6	8	2	4	9	5	1
8	2	1	7	5	9	6	3	4
4	5	9	6	1	3	2	8	7

आज का भविष्यफल - 05 जुलाई, 2024 शुक्रवार

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या। आज का राहुकाल : प्रातः 10 बजकर 30 मिनट से 12 बजे तक। आज का दिशाशूल : पश्चिम।
आज का पर्व एवं त्योहार : स्नानदान की अमावस्या। विशेष : चतुर्दशी तिथि क्षय

कल 06 जुलाई, 2024 का पंचाग
कल का दिशाशूल : पूर्व
कल का पर्व एवं त्योहार : गुप्त नवरात्रि
विशेष : शुक्र कर्क राशि में
विक्रम संवत 2081 शके 1946 उत्तरायण, उत्तरगोल, ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 28 घण्टे 27 मिनट तक, तत्पश्चात द्वितीया पुनर्वसु नक्षत्र तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र व्याघात योग तत्पश्चात हर्षण योग मिथुन में चंद्रमा तत्पश्चात कर्क में।

मेष : पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी।
वृष : जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी।
मिथुन : बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
कर्क : शासनसत्ता का सहयोग रहेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
सिंह : शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा।
कन्या : रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा।
तुला : कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा।
वृश्चिक : यात्रा या स्थानांतरण की दिशा में सफलता मिलेगी।
धनु : संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी।
मकर : पिता या धर्म गुरु से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।
कुंभ : संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
मीन : जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

राष्ट्रीय फलक

मौसम देखकर निकलें, कार्बेट में सफारी रद होने पर रिफंड नहीं

जागरण संवाददाता, नैनीताल

- कार्बेट की विभागीय बुकिंग वेबसाइट पर पर्यटकों को दी गई है जानकारी
- अत्यधिक वर्षा की स्थिति में बंद कर दी जाती है ढेला, झिरना व गिरिजा जोन में सफारी

कार्बेट नेशनल पार्क में सफारी के लिए आ रहे हैं तो मौसम को देखकर ही प्लान बनाएं। अत्यधिक वर्षा होने पर पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए कार्बेट प्रशासन अचानक सफारी बंद कर देता है। ऐसे में एडवांस बुकिंग की धनराशि भी वापस नहीं मिलेगी।

मानसून को देखते हुए कार्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला, दुर्गादेवी पर्यटन जोन 15 जून और बिजरानी पर्यटन जोन 30 जून से पर्यटकों के लिए बंद हो चुका है। केवल ढेला, झिरना व गिरिजा पर्यटन जोन पर्यटकों की डे सफारी के लिए खुला हुआ है, लेकिन मानसून सीजन में पार्क आने वाले पर्यटकों के लिए विभागीय वेबसाइट में सफारी निरस्त होने पर बुकिंग का पैसा वापस नहीं होने की सूचना भी स्पष्ट रूप से दी गई है। वर्षा में कार्बेट में नदी-नाले उफान पर होते हैं। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए पार्क प्रशासन बिना पूर्व सूचना के सफारी निरस्त कर देता है। कार्बेट के ढेला जोन में सुबह और दोपहर की पाली में 15-15, बिजरानी व गिरिजा देवी पर्यटन जोन में सुबह व दोपहर की पाली में 30-30 जिप्सी सफारी पर निकलती हैं। एक जिप्सी में छह पर्यटक बैठ सकते हैं।

बुकिंग का देना होता है 3400 रुपये

सफारी बुकिंग के लिए जिप्सी परमिट का अधिकतम छह लोगों के लिए 3400 रुपये किराया तय है। इसके अतिरिक्त 900 रुपये गाइड शुल्क व जिप्सी का किराया 2500 से 2800 रुपये तक देना होता है। जिप्सी व गाइड का शुल्क सफारी होने पर ही दिया जाता है। जबकि परमिट की राशि एडवांस आनलाइन ही विभाग में जमा की जाती है। ऐसे में सफारी निरस्त होने पर छह पर्यटक के ग्रुप को 3400 रुपये का नुकसान होता है।

आगरा की शाही मस्जिद में श्रीकृष्ण के विग्रह के दावे पर एएसआइ से कोर्ट ने मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

- हाई कोर्ट में अगली सुनवाई पांच अगस्त को, एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की भी है मांग

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा स्थित शाही मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्रीकृष्ण के विग्रह दबे होने के दावे के मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने ठाकुर केशवदेव जी महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशव देव और अन्य के सिविल वाद की सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह आदेश दिया। एसआइटी गठित कर एएसआइ से सर्वे कराने और एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति करने की मांग सिविल वाद संख्या तीन में की गई है। कोर्ट ने अर्जी की प्रति एएसआइ के अधिवक्ता मनोज सिंह को सौंपने तथा उनको जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। शाही ईदगाह मस्जिद की प्रबंध समिति की तरफ से पक्षकार बनाने की विचाराधीन अर्जी की प्रति वादी अधिवक्ता को देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया।

एक अन्य सिविल वाद (संख्या 10) भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशवदेव खेवट 255 व छह अन्य में

इलाहाबाद हाई कोर्ट। फाइल

कोर्ट ने वादी अधिवक्ता शशांक सिंह को सात दिन में वाद की प्रति विपक्षी संख्या एक व दो को दिए जाने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने विपक्षी शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता नसीरुज्जमा से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। सिविल वाद की पोषणीयता पर विपक्षी की एक अन्य आपत्ति अर्जी की प्रति वादी अधिवक्ता को दी गई और उन्हें आपत्ति दाखिल करने का समय दिया गया। दोनों ही मामलों को सुनवाई के लिए पांच अगस्त को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

बता दें, हाई कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर कुल 18 केस हैं। इनकी पोषणीयता पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश सात नियम 11के तहत शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से आपत्ति की गई है। दो वादों (संख्या तीन और 10) को छोड़ कर शेष 16 में लंबी बहस के बाद कोर्ट ने जून में आदेश सुरक्षित कर लिया है।

वादी तथा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने विभिन्न इतिहासकारों की पुस्तकें भी कोर्ट को दिखाईं। उन्होंने जो पुस्तकें दिखाईं, उनमें साखी मुस्तैक खान की मासरे आलमगिरी, एफएस ग्राउज की मथुरा मेमोआयर, मथुरा गजेटियर और औरंगजेबनामा के अलावा फ्रैंकौस गुटियर की किताब औरंगजेब आईकोलिज्म शामिल है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि औरंगजेब द्वारा 1670 में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से स्वर्ण जड़ित छोटे-बड़े विग्रह ले जाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफन कर दिए गए और मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया था।

भोजशाला सर्वे की रिपोर्ट पेश करने को एएसआइ को मिले और दस दिन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर

- हाई कोर्ट में दो जुलाई को पेश करनी थी रिपोर्ट, अगली सुनवाई 22 को
- वैज्ञानिक सर्वे में 650 से अधिक आर्टिकल सामने आए

धार की ऐतिहासिक भोजशाला के सर्वेक्षण के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को रिपोर्ट पेश करने के लिए 10 दिन का समय और दिया है। गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि एएसआइ 15 जुलाई या उससे पहले सर्वे रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करे। मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

बता दें कि हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 11 मार्च, 2024 को एक आदेश जारी कर एएसआइ से कहा था कि वह ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला का भी पुरातात्विक सर्वेक्षण करे।

एएसआइ को छह सप्ताह में सर्वे पूरा कर 29 अप्रैल, 2024 को कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन उसने यह कहते हुए समय बढ़ाने की मांग की थी कि सर्वे में जिन अत्याधुनिक उपकरणों की आवश्यकता है, वह अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। इस पर कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के लिए एएसआइ को दो जुलाई तक का समय दिया था। दो जुलाई को फिर एएसआइ ने सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने तीन सप्ताह का समय मांगा। इसी आवेदन पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से एडवोकेट हिमांशु जोशी ने कहा कि वैज्ञानिक सर्वे में 650 से अधिक आर्टिकल सामने आए हैं। इनका विश्लेषण किया जाना है, इसलिए तीन सप्ताह का समय और दिया जाए। न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी ने कहा कि हम आपको 10 दिन का समय दे रहे हैं। साथ ही, इसकी प्रति सभी पक्षकारों को उपलब्ध करा दें, इससे कोर्ट का समय बचेगा। एडवोकेट जोशी ने कहा कि हम बंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे और जब आप कहेंगे हम इसकी प्रति पक्षकारों को उपलब्ध करवा देंगे। कोर्ट ने इस अनुरोध को नहीं माना। उसे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।

अनंत अंबानी की शादी में भागलपुर की माधवी मधुकर के गूंजेंगे संस्कृत स्त्रोत

ललन तिवारी ● जागरण

- नीता अंबानी को भा गई माधवी मधुकर की मधुर आवाज
- सबौर में घर व गोड्डा है ससुराल, अभी रह रहीं नोएडा में

भागलपुर : बिहार के भागलपुर की माधवी मधुकर की आवाज मुकेश और नीता अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी की शादी में सुनाई देगी। शादी 12 जुलाई को मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होगी। नीता अंबानी को माधवी मधुकर का संस्कृत भाषा में पिरोया भक्ति संगीत भा गया। उन्होंने बेटे की शादी के कार्ड में डिजिटल आवाज में माधवी मधुकर के विष्णु सहस्त्रनाम को शामिल किया। अनंत की शादी के समय भी यही स्त्रोत गूंजेगा। अनंत व राधिका मर्चेंट की शादी के लिए तैयार आमंत्रण पत्र को खोलते ही 'ॐ श्री विष्णवे नमः' गूंजने लगता है। माधवी ने बताया कि विवाह पत्र में अपनी आवाज के उपयोग के लिए अंबानी दंपती से उन्होंने कोई शुल्क नहीं लिया है।

माधवी मधुकर झा का मायका भागलपुर के सबौर में है। झारखंड के गोड्डा जिले में उनकी ससुराल है। विवाह के बाद से माधवी नोएडा में रह रही हैं। माधवी ने भागलपुर के माउंट असीसी स्कूल में पढ़ाई की। भागलपुर विश्वविद्यालय से ही उन्होंने उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। बचपन से ही कला में रुचि रखने वाली माधवी ने संगीत की कभी कोई शिक्षा नहीं ली। गोड्डा जिले के सुभाष चंद्र झा एवं निरंजना झा की पुत्रवधू माधवी के पति नोएडा में उद्यमी हैं। वह भी संगीत के लिए माधवी को प्रोत्साहित करते रहते हैं। संस्कृत भाषा में भजन गा रहीं माधवी ने मैथिली, हिन्दी व अवधी में भी भजन गाए हैं। आज भारत समेत अमेरिका और जर्मनी आदि देशों में उनके सात लाख फालोवर्स हैं। माधवी मधुकर झा के गुरु पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं। माधवी भोपाल के शंकर न्यास व संस्कृति विभाग से भी जुड़ी हुई हैं। वहां के शंकर दूतों को शंकर गान सिखाने में माधवी निश्शुल्क योगदान देती हैं। माधवी ने अपनी म्यूजिक टीम का नाम भी मधुरम वृंद रखा है।

भजन गातीं बिहार के भागलपुर की माधवी मधुकर। सौजन्य : स्वयं

महाकुंभ में पीने लायक होना चाहिए गंगा-यमुना का जल : एनजीटी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रयागराज प्रशासन को कुंभ मेला के शुरू होने से पहले गंगा और यमुना में सीवेज के बहाव को न्यूनतम स्तर पर रोकने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना के तहत सभी संभव प्रभावी और त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि महाकुंभ में पीने लायक होना चाहिए गंगा-यमुना का जल। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली प्रधान पीठ, जिसमें अरुण कुमार त्यागी (न्यायिक मजिस्ट्रेट) और डा. ए.सेंथिल वेल (विशेषज्ञ सदस्य) भी शामिल थे, ने अपने कहा कि कुंभ मेला के तीर्थयात्री गंगा व यमुना नदियों में स्नान करेंगे। पीने के लिए उनके पानी का उपयोग करेंगे। ऐसे में सभी संभव प्रभावी और त्वरित कदम उठाए जाने चाहिए। पीठ ने राज्य को आठ सप्ताह का और समय दिया है। कहा है कि संबंधित प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि नदियों के पानी की गुणवत्ता पीने के लिए उपयुक्त स्तर पर बनी रहे और यह उपयुक्तता श्रद्धालुओं को विभिन्न स्नान घाटों पर दिखाई जाए।

****

पुरी में 53 वर्षों बाद महाप्रभु का नेत्र उत्सव और रथयात्रा एक ही दिन

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

- स्वस्थ हुए महाप्रभु जगन्नाथ, 7 को रथयात्रा, शरीर में लगाया गया दिव्य लेप
- महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ को 22 जून को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया था

53 वर्षों बाद महाप्रभु का नेत्र उत्सव और रथयात्रा एक ही दिन यानि 7 जुलाई को होगा। महाप्रभु के स्वस्थ होते ही विश्व प्रसिद्ध महाप्रभु जगन्नाथ की रथयात्रा की पुरी मंदिर में तैयारी चरम पर है।

मालूम हो कि 22 जून को देव स्नान पूर्णिमा के दिन भक्तों ने पुरी में महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया था। इस परंपरा के बाद महाप्रभु को बुखार आ गया था। बीमार होने के बाद वह अणसर (बुखार घर) में चले गए। वहां पर उनका इलाज चल रहा था।

महाप्रभु के बीमार होने के बाद घर में चले जाने के बाद पुरी मंदिर का पट नहीं खुल रहा था। भगवान को महाप्रसाद का भोग नहीं लग रहा था। सेवक भगवान का जड़ी-बूटियों से इलाज कर रहे थे। इलाज और सेवा के बाद त्रयोदशी तिथि (गुरुवार) को महाप्रभु स्वस्थ हो गए।

इस मौके पर श्रीजिउ की घना एवं खली प्रसाद लागी नीति (महाप्रभु के शरीर में दिव्य लेप लगाना) संपन्न की गई। शुद्ध सुआर (सेवक) के घर से घंट, छाता, काहाली के साथ खली प्रसाद मंदिर में लाया गया। शुद्ध सुआर द्वारा बनाए गए इस दिव्य लेप को चांदी के बर्तन में रखा गया और दइतापति सेवक ने इसे भगवान के शरीर में लगाया। खली लागी नीति से पहले प्रभु की घणा लागी गुप्त नीति संपन्न की गई। इससे पहले नए विग्रह की गुप्त सेवा में दइता और पतिमहापात्र सेवक एक विशेष नीति के तहत लाल रंग का वस्त्र प्रभु के ऊपर चढ़ाया गया। नवयौवन दर्शन से पहले देर रात को श्रीविग्रहों के श्रीअंग में आखिरी बार खली लागी की गई। बताते चलें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भी इस वर्ष रथयात्रा में शामिल होंगी। वह चार दिवसीय दौरे पर छह जुलाई को भुवनेश्वर पहुंचेंगी।

रामपथ से जुड़ा भ्रामक वीडियो प्रसारित करने पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, अयोध्या : रामनगरी अयोध्या में रामपथ को दुर्दशाग्रस्त बताते हुए भ्रामक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया है। यह वीडियो समाजवादी छात्र सभा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह कुशवाहा के नाम से बने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया गया। इस वीडियो पर आपत्ति दर्ज कराते हुए स्थानीय निवासी आयुष शुक्ल ने कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने इसे रामनगरी एवं राज्य सरकार की छवि धूमिल करने का कुत्सित प्रयास बताया है।

बुधवार को प्रसारित वीडियो में एक महिला को रामपथ धंसने पर गड्ढे में गिरता दिखाया गया है। इस वीडियो को साकेत महाविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व महामंत्री अवधेश यादव ने भी साझा किया है। फेसबुक अकाउंट पर मुलायम सिंह कुशवाहा के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ कई फोटो भी हैं। समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवांशु तिवारी ने बताया कि छात्रसभा के प्रदेश अध्यक्ष का नाम विनीत कुशवाहा है, मुलायम सिंह कुशवाहा नहीं।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 5 जुलाई, 2024
आजकल

www.jagran.com

क्लोन से तैयार पहले स्तनपायी जानवर डाली का जन्म हुआ

1996 में आज ही क्लोन से तैयार पहले स्तनपायी जानवर डाली भेड़ का जन्म हुआ था। स्काटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट के विज्ञानियों ने एक वयस्क भेड़ की कोशिकाओं से इस क्लोन को तैयार किया था। सातवीं जन्मतिथि से कुछ महीने पहले ही डाली की मृत्यु हो गई थी।

सोवियत संघ से भारत को मिली पनडुब्बी आइएनएस कलवरी

1968 में आज ही भारत की पहली पनडुब्बी आइएनएस कलवरी सोवियत संघ के रीगा बंदरगाह से विशाखापत्तनम पहुंची थी। सोवियत संघ से करार के तहत यह पनडुब्बी भारत को मिली। 1971 में भारत-पाक युद्ध में कराची बंदरगाह तबाह करने में इसने भूमिका निभाई थी।

डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक माने जाते हैं लालजी सिंह

जीव विज्ञानी लालजी सिंह का जन्म 1947 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। 1987 में वरिष्ठ विज्ञानी के रूप में सेंटर फार सेल्युलर एंड मालिक्यूलर बायोलाजी (सीसीएमबी) से जुड़ गए। यहीं उन्होंने फोरेंसिक जांच के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक विकसित की। राजीव गांधी हत्याकांड, नैना साहनी व मधुमिता मर्डर जैसे कई चर्चित मामलों को इसी तकनीक के जरिये सुलझाया गया था। 1995 में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर शुरू किया। 2009 में बीएचयू के कुलपति बने।

महामारी के दौरान तीन फीसदी अधिक कमजोर बच्चे जन्मे

दो लाख से अधिक शिशुओं का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 12,000 महामारी में पैदा हुए, बाकी उससे पहले पैदा हुए

अमेरिका के नोट्रे डेम विश्वविद्यालय में नवजात पर किया गया अध्ययन

- दुनिया में लगभग हर चार में से एक बच्चा कम वजन के साथ पैदा होता है
- शिशुओं में कम वजन की व्यापकता महामारी के समय 20 प्रतिशत रही

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना महामारी के दौरान भारत में तीन फीसदी ज्यादा कमजोर शिशुओं का जन्म हुआ। साथ ही जन्म के समय इनका वजन भी औसतन 11 ग्राम कम पाया गया। एक नए अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है। महामारी के दौरान पैदा हुए नवजात में जन्म के समय कम वजन होने का जोखिम भी दोगुना पाया गया।

अमेरिका के नोट्रे डेम विश्वविद्यालय में विकास और वैश्विक स्वास्थ्य अर्थशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर और लेखक संतोष कुमार ने कहा कि कम वजन वाले बच्चों के जन्म की संख्या में वृद्धि से दीर्घ अवधि में ''मानव पूंजी'' के विकास पर असर पड़ सकता है क्योंकि इन शिशुओं को अक्सर स्कूल जाने में कठिनाई होती है। संतोष कुमार ने कहा कि शिशु के रूप में कम वजन वाले बच्चे अक्सर स्कूल जाने में कठिनाई का सामना करते हैं। इससे उनकी वह क्षमता सीमित हो जाती है, जिसे अर्थशास्त्री अक्सर 'मानव पूंजी' कहते हैं। वह ज्ञान और कौशल के क्षेत्र में कमी के कारण उनकी अच्छी आजीविका कमाने और खुद को और परिवार का भरण-पोषण करने की क्षमता को प्रभावित करेगा।

लगभग 95 प्रतिशत बच्चे निम्न और मध्यम आय वाले देशों में पैदा हुए : दुनिया भर में लगभग हर चार में से एक बच्चा (तीन करोड़) कम वजन के साथ पैदा होता है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) 2.5 किग्रा से कम वजन के रूप में परिभाषित किया। कम्युनिकेशन मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, कम वजन वाले बच्चे से लगभग 95 प्रतिशत बच्चे निम्न व मध्यम आय वाले देशों में पैदा हुए हैं, जिनमें से लगभग आधे दक्षिण एशिया में पैदा हुए हैं। अप्रैल 2020 और अप्रैल 2021 के बीच पैदा हुए बच्चों का वजन महामारी से पहले पैदा हुए बच्चों की तुलना में डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित सीमा से कम था। दो लाख से अधिक शिशुओं का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 12,000 महामारी में पैदा हुए और लगभग 1,92,000 महामारी से पहले पैदा हुए। 2019-21 के बीच भारतीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के पांचवें दौर का डाटा लिया गया।

नवजात शिशु। फाइल

नवजात के औसतन जन्म के वजन में 11 ग्राम की कमी पाई गई

लेखकों ने अध्ययन में लिखा है कि शिशुओं में कम वजन की व्यापकता की दर महामारी के समय 20 प्रतिशत और महामारी से पहले के समय 17 प्रतिशत है। उन्होंने दावा किया कि यह पहला अध्ययन है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि नमूने का उपयोग कर यह देखा गया है कि महामारी ने भारत में जन्म के परिणामों को कैसे प्रभावित किया। महामारी के दौरान औसतन जन्म के वजन में 11 ग्राम की कमी पाई गई। लेखकों ने यह भी पाया कि महामारी के दौरान पैदा हुए शिशुओं में महामारी से पहले पैदा हुए शिशुओं की तुलना में कम वजन वाले जन्म का जोखिम दोगुना था। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों में महामारी से प्रभावित बच्चों की एक बड़ी संख्या देखी गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि सबसे अमीर घरों के बड़ी संख्या में बच्चे भी प्रभावित हुए। संतोष कुमार ने कहा कि महामारी से संबंधित कई कारकों में कोविड के कारक एसएआरएस-सीओवी-2 वायरस, सामाजिक दूरी से संबंधित तनाव, आर्थिक उथल-पुथल और मातृ एवं नवजात शिशु देखभाल में व्यवधान शामिल हैं।

देवताओं को धन्यवाद देने के लिए उड़ाई जाती हैं पतंगे

रंग-बिरंगी और तरह-तरह के डिजाइनों की पतंगें जब आसमान में लहराती हैं तो यह दृश्य देखने लायक होता है। दुनियाभर में पतंगबाजी का क्रेज काफी तेजी से बढ़ रहा है। यह तस्वीर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पतंग प्रतियोगिता की है, जहां विविध डिजाइनों की पतंगें हवा से बातें कर रही हैं। देश में यह उत्सव लगभग तीन माह तक चलता है। यहां पतंगें सिर्फ शौक ही नहीं है, बल्कि बाली द्वीप पर नजर रखने वाले देवताओं को धन्यवाद देने और भरपूर फसल के मौसम के लिए प्रार्थना करने के उद्देश्य से उड़ाई जाती हैं। एएफपी

इधर-उधर की

दक्षिण अफ्रीका में मिले सबसे पुराने दीमक के टीले

केपटाउन, एपी : दीमक कीटों की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वास्तुकार माने जाते हैं। इनकी कारीगरी देखकर विज्ञानी भी हैरान हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्टेलनबोश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बफेल्स नदी के पास हजारों वर्ष पुराने दीमक के सक्रिय टीलों की खोज की है। रेडियोकार्बन डेटिंग के जरिये अनुमान लगाया गया है कि ये 34 हजार वर्ष पुराने हैं। शोधकर्ता इसे अब तक ज्ञात दीमक के सबसे पुराने टीले बता रहे हैं। शोधकर्ता मिशेल फ्रांसिस ने कहा कि टीले तब मौजूद थे जब धरती पर ऊनी मैमथ घूमते थे और यूरोप और एशिया का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था।

टीलों के 34 हजार साल पुराने होने का अनुमान लगाया गया है। एपी

बीपी रोगी 70 मिग्रा/डीएल से कम रखें बैड कोलेस्ट्राल का स्तर

- डिस्लिपिडेमिया प्रबंधन के लिए पहली बार भारतीय दिशानिर्देश जारी किए
- नियमित योग करें, 18 वर्ष की आयु में कराएं पहली लिपिड प्रोफाइल जांच

नई दिल्ली, प्रेट्र : मधुमेह या उच्च रक्तचाप वाले लोगों को बैड कोलेस्ट्राल का स्तर 70 मिलीग्राम डेसीलिटर से नीचे रखना चाहिए। कम जोखिम वाले लोगों को बैड कोलेस्ट्राल के स्तर को 100 प्रति डेसीलिटर से नीचे बनाए रखना चाहिए। कार्डियोलाजिकल सोसाइटी आफ इंडिया (सीएसआइ) ने पहली बार जारी दिशानिर्देशों में यह सलाह दी है।

डिस्लिपिडेमिया प्रबंधन के लिए जारी दिशानिर्देशों में चीनी और कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करने की सिफारिश की गई है। नियमित व्यायाम और योग करने की भी सलाह दी गई है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि 18 वर्ष की आयु में पहली लिपिड प्रोफाइल जांच करानी चाहिए। यदि परिवार में दिल के रोग का इतिहास रहा हो तो उससे भी पहले जांच कराएं।

कम जोखिम वाले व्यक्तियों को नान-एचडीएल-सी का स्तर 130 मिलीग्राम/डीएल से कम रखना चाहिए। नान-एचडीएल कोलेस्ट्राल, जिसे नान-एचडीएल-सी के नाम से भी जाना जाता है, यह मापने का तरीका है कि रक्त में कितने प्रकार के बैड कोलेस्ट्राल हैं। मधुमेह या हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को नान-एचडीएल का स्तर 100 मिलीग्राम/डीएल से कम रखना चाहिए।

देश में दिल की बीमारियों के मरीजों की संख्या में वृद्धि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच कार्डियोलाजिकल सोसाइटी आफ इंडिया (सीएसआइ) ने भारतीय डाटा का उपयोग कर डिस्लिपिडेमिया प्रबंधन के लिए भारतीय दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह पहल देशभर में डिस्लिपिडेमिया की चुनौतियों में निपटने में मील का पत्थर है।

खून में लिपिड के असामान्य स्तर को डिस्लिपिडेमिया कहते हैं। डिस्लिपिडेमिया में एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स बहुत अधिक होते हैं जबकि एचडीएल (गुड कोलेस्ट्राल) कम हो जाते हैं। नुकसानदायक बैड कोलेस्ट्राल को एलडीएल कोलेस्ट्राल कहा जाता है। बैड कोलेस्ट्राल धमनी की दीवारों में प्लाक या गुच्छे बना सकता है। चूंकि एचडीएल खून से एलडीएल को हटाने में सहायता करता है, इसलिए इसे ''गुड'' कोलेस्ट्राल माना जाता है। सीएसआइ के अध्यक्ष डा. प्रताप चंद्र रथ ने कहा, डिस्लिपिडेमिया साइलेंट किलर की तरह होता है। डिसलिपिडेमिया के लक्षण नहीं दिखते, लेकिन डिस्लिपिडेमिया से दिल के रोगों का जोखिम बढ़ जाता है।

सर गंगाराम अस्पताल के कार्डियोलाजी विभाग के अध्यक्ष और लिपिड गाइडलाइन्स के अध्यक्ष डा. जेपीएस. साहनी ने बताया कि, बहुत अधिक जोखिम वाले मरीजों को एलडीएल-सी का स्तर 55 मिलीग्राम/डीएल से कम या नान-एचडीएल का स्तर 85 मिलीग्राम/डीएल से कम रखना चाहिए। डा. साहनी ने कहा कि डिस्लिपिडेमिया प्रबंधन के लिए जीवनशैली में बदलाव पर जोर दिया जाता है। बहुत अधिक जोखिम वाले मरीजों में दिल के दौरे, एनजाइना, स्ट्रोक या किडनी की बीमारियों के मरीज शामिल हैं। एम्स, दिल्ली में कार्डियोलाजी के प्रोफेसर और लिपिड गाइडलाइंस के सह-लेखक डा. एस रामकृष्णन ने कहा, अधिक एलडीएल-सी और नान-एचडीएल-सी को स्टैटिन और गैर-स्टैटिन दवाओं के संयोजन से नियंत्रित किया जा सकता है। यदि यह कारगर ने हो तो पीसीएसके9 अवरोधक या इंक्लिसिरान जैसी इंजेक्शन वाली लिपिड-कम करने वाली दवाओं का उपयोग करें। उन्होंने कहा, जीवनशैली में बदलाव, जैसे कि नियमित व्यायाम, शराब और तंबाकू छोड़ना, और चीनी और कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करना, बहुत जरूरी है।

नियमित बलड प्रेशर चेक करें। फाइल

फ्लू संक्रमण से गर्भावस्था में होने वाली परेशानियों से बचा सकता है एस्पिरिन

अनुसंधान

एक शोध में सामने आया है कि कम मात्रा में एस्पिरिन फ्लू की वजह से रक्त वाहिका सूजन को ठीक करने में सहायक हो सकता है। इससे प्रेग्नेंसी के दौरान प्लेसेंटा में बेहतर ब्लड फ्लो बना रहता है। चूहों पर किए गए इस प्रकार के पहले शोध में यह बात सामने आई है। यह अध्ययन आस्ट्रेलिया की आरएमआइटी यूनिवर्सिटी की टीम और आयरलैंड के ट्रीनिटी कालेज डबलिन की टीम ने किया है।

इसमें कहा गया है कि प्रेग्नेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर (प्रीक्लेम्पसिया) से निपटने के लिए कम डोज में एस्पिरिन का उपयोग किया जाता रहा है। यह शरीर को उन केमिकल के निर्माण से रोकता है, जिनके कारण सूजन की समस्या सामने आती है। टीम ने इस दौरान अध्ययन किया कि क्या प्रीक्लेम्पसिया को फ्लू संक्रमण पर लागू किया जा सकता है। उन्हें चूहों पर किए गए अध्ययन में आशाजनक परिणाम मिले। जिन चूहों को रोज कम मात्रा में एस्पिरिन दिया गया उनमें सूजन कम थी और भ्रूण के विकास और संतान के जीवित रहने में सुधार हुआ। इसके विपरीत, इन्फ्लूएंजा संक्रमण वाले चूहों के भ्रूण और प्लेसेंटा असंक्रमित चूहों की तुलना में छोटे थे। उन्होंने भ्रूण में कम मात्रा में आक्सीजन की मात्रा और खराब रक्त वाहिका विकास भी पाया। प्रमुख शोधकर्ता डा. स्टेला लिओंग ने कहा कि प्रेग्नेंसी के दौरान फ्लू संक्रमण प्रीक्लेम्पसिया जैसा हो सकता है, जो गर्भावस्था की जटिलता है जो महाधमनी व रक्त वाहिकाओं में सूजन का कारण बनती है। (आइएएनएस)

स्क्रीन शाट

जिंदगी में इसे सबसे बड़ा बदलाव मानते हैं प्रतीक

फिल्म फुले में ज्योतिबा फुले की भूमिका में नजर आएंगे प्रतीक गांधी। इस्टाग्राम (@pratikgandhiofficial)

आडिशन की कतार से निकलने के बाद किसी भी कलाकार के लिए वह बहुत बड़ा दौर होता है, जब निर्माता निर्देशक उन्हें सोचकर अपनी फिल्में या प्रोजेक्ट लिखते हैं। अभिनेता प्रतीक गांधी फिलहाल अपने पेशेवर जीवन के उसी दौर में हैं।

इस साल अब तक उनकी मडगांव एक्सप्रेस, डेढ़ बीघा जमीन तथा दो और दो प्यार तीन फिल्में प्रदर्शित हो चुकी हैं। इसके अलावा आगामी दिनों में उनकी अग्नि, फुले, धूमधाम और वो लड़की है कहां जैसी फिल्में कतार में हैं। दैनिक जागरण से बातचीत में प्रतीक अपने इस दौर को लेकर कहते हैं, 'किसी भी कलाकार के लिए यह बहुत अच्छी बात है कि जब लेखक और निर्देशक अपनी कहानियां लिख रहे होते हैं, तो उनके मन में आपका नाम आता है। मैं तो पिछले कई वर्षों से चाहता था कि ऐसी ही किसी स्थिति में पहुंचूं कि कोई किरदार लिखते समय लोग आपके बारे में कम से कम एक बार सोचें। मेरी जिंदगी में वो दौर स्कैम 1992 : द हर्षद मेहता स्टोरी के बाद आया है।

स्कैम 1992 के कारण ही मुझे मडगांव एक्सप्रेस फिल्म भी मिली थी। मेरी जिंदगी में यह बहुत बड़ा बदलाव है। इसके अलावा अब दर्शकों की सोच भी बदली है। अब दर्शक भी नए चेहरों को, कहानी के अनुसार नए कलाकारों को देखने के लिए तैयार हैं।'

फास्ट फूड की तरह रिश्ते सेहत व जीवन के लिए हानिकारक : विनीत

पेज 3 फिल्म का एक गाना था, जो फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बनाया गया था कि कितने अजीब रिश्ते हैं यहां के...। वाकई इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स के लिए यहां दोस्त बनाना आसान नहीं होता है। कुछ कलाकार हैं, जो इंडस्ट्री में जब दोस्त बनाते हैं, तो उसमें पूरी ईमानदारी रखते हैं। उनके साथ जब काम करने का मौका मिलता है, तो वह काम भी करते हैं। आगामी दिनों में अभिनेता विनीत कुमार सिंह सुपरमैन आफ मालेगांव फिल्म में दिखेंगे। दैनिक जागरण से बातचीत में विनीत कहते हैं कि मैं ऐसा आदमी रहा हूं, जो रिश्ते बहुत सोच-समझकर बनाता है। चाहे फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त हों या फिर मेरे कालेज के दिनों के, जिनसे रिश्ता बना, वह हमेशा के लिए बना। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि रिश्ते बनाइए, तो लंबा चलिए। मैं फास्ट फूड खाता भी कम हूं और फास्ट फूड वाले रिश्ते भी कम बनाता हूं। फास्ट फूड की तरह अगर रिश्ता होगा, तो वह सेहत और जीवन दोनों के लिए हानिकारक होगा। ऐसे रिश्तों से दूर रहने की सलाह देता हूं। सुपरमैन आफ मालेगांव के साथ विनीत अभिनीत वेब सीरीज रंगीन भी प्रदर्शन की कतार में है। वह कहते हैं कि लगातार काम में लगा हुआ हूं।

सुपरमैन आफ मालेगांव फिल्म में होंगे विनीत। (@vineet_ksofficial)

...इसलिए वड़ा पाव खाने के लिए दिल्ली जाएंगी पौलमी दास

बिग बास का घर बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, वहां जाकर खेलना उतनी ही कठिन है। एक गलतफहमी दूर हुई है बिग बास ओटीटी 3 के घर से बाहर होने वाली अभिनेत्री पौलमी दास की भी। उन्हें इस घर में मिली हैं दोस्त चंद्रिका गेरा, जिन्हें लोग वड़ा पाव गर्ल के नाम से जानते हैं। दैनिक जागरण से बातचीत में पौलमी कहती हैं कि बिग बास में जाने के बाद चंद्रिका को लेकर कई गलतफहमियां दूर हुईं। जैसे इंटरनेट मीडिया पर उन्हें दिखाया गया है, वह उससे बहुत अलग हैं। वह अच्छी महिला हैं। कठिन परिस्थितियों से बाहर आई हैं। मैं वड़ा पाव खाने के लिए दिल्ली जाऊंगी। मैंने उन्हें बोलकर रखा है कि देखो मैं मुंबई से हूं, अगर अच्छा वड़ा पाव नहीं बनाओगी, तो गाली भी खाओगी। आगे पौलमी कहती हैं कि यू ट्यूबर शिवानी कुमारी से वह कभी दोस्ती नहीं रखेंगी। शिवानी केवल दूसरों का ध्यान अपनी और खींचने के लिए बातें करती हैं। उल्लेखनीय है कि शिवानी ने पौलमी के कपड़े पहनने के तरीकों पर टिप्पणी की थी। क्या पौलमी को बिग बास से प्रसिद्धी मिली, जिसकी तलाश में वह यहां आई थी? इस पर वह कहती हैं कि मैं काफी वक्त से काम कर रही हूं। लेकिन पिछले दो हफ्तों में जो प्रतिक्रिया मुझे मिली है, वह बहुत बड़ी है।

बिग बास से बाहर हुई पौलमी। (@poulomipolodas_official)

मैंने असफलता से ज्यादा लोगों को सफलता से बर्बाद होते देखा है

कबीर ने डाक्यूमेंट्री फिल्मों से की थी अपने सिनेमाई सफर की शुरुआत ● मिडडे आर्काइव

सात सवाल

फिल्म 83 के बाद फिल्मकार कबीर खान द्वारा निर्देशित एक और स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म चंदू चैंपियन ने टिकट खिड़की पर 55.5 करोड़ रुपये की कमाई की। कार्तिक आर्यन अभिनीत यह फिल्म देश के पहले स्वर्ण पदक विजेता पैरालिंपियन मुरलीकांत पेटकर की बायोपिक है। वर्तमान समय में अखिल भारतीय फिल्मों के चलन को सिर्फ एक मार्केटिंग का जरिया मानने वाले कबीर से उनकी फिल्मों और सिनेमा जगत के विविध पहलुओं पर बातचीत :

● चैंपियन की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है?

- आप जिंदगी में जो करना चाहते हैं अगर उसे आप अपने तरीके से कर सके, तो आप चैंपियन हैं। कई बार होता है कि इंसान सफल होते हुए भी काम अपने हिसाब से नहीं कर पाता वो सच्ची सफलता नहीं है। आसान तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है, हर चीज के लिए थोड़ा संघर्ष करना ही पड़ता है। फिल्म इंडस्ट्री ऐसी जगह है जहां काम करने के लिए हजारों लोग आते हैं। सभी का सपना होता है कि एक्टर बने, निर्देशक बने। उस भीड़ में अपनी आवाज पहुंचाना आसान नहीं होता है, लेकिन मजा भी उसी में है।

● क्या कभी सफलता सिर पर चढ़ी है, अगर हां, तो फिर उससे कैसे आगे बढ़े?

- मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कभी अपनी सफलता को गंभीरता से नहीं लिया। सफलता सिर न चढ़ने का शायद एक बड़ा कारण यह भी है कि मेरी ट्रेनिंग यशराज फिल्म्स में हुई है। वहां एक स्कूल कैंपस जैसा माहौल बना हुआ है। वहां आप अपनी रेस में अव्वल आए या आखिरी, आपके साथ लोगों का व्यवहार नहीं बदलता। तब मैंने जाना कि अगर आप अपनी सफलता को गंभीरता से नहीं लेंगे तो असफलता भी आपको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी। इतने वर्षों में मैं इंडस्ट्री में अपने पसंदीदा लोगों के साथ काम कर चुका हूं, मैंने देखा है कि असफलता से ज्यादा लोगों को सफलता बर्बाद करती है।

● आज के दौर में पैन इंडिया (अखिल भारतीय) के नाम पर प्रदर्शित हो रही फिल्मों के चलन को आप कैसे देखते हैं?

- दरअसल, मुझे ये पैन इंडिया वाली संकल्पना समझ में ही नहीं आती है। पहले एक चलन आया था क्रासओवर का, लोग कहते थे कि हम क्रासओवर फिल्म बना रहे हैं। जो क्रासओवर या पैन इंडिया फिल्में होंगी, वो बनने और प्रदर्शित होने के बाद ही पता चलेंगी। अगर दर्शकों को वो फिल्में अच्छी लगेंगी, तो वह पैन इंडिया स्तर पर ही क्यों, पैन वर्ल्ड स्तर पर भी जा सकती हैं। लोग तो बस शब्द का इस्तेमाल प्रचार के लिए करते हैं। मुझे ये सिर्फ मार्केटिंग का शब्द लगता है, जिसे मैं गलत भी नहीं कहता हूं।

● सुनने में आया कि आप कोई वेब सीरीज बना रहे हैं?

वेब सीरीज मैं नहीं मेरी एक कंपनी बना रही है। पहाड़ों के बीच घिरे एक छोटे से शहर में बहुत सारे हादसे होते हैं, वह शो उसी पर आधारित है।

● मुरलीकांत पेटकर ने तो पैरालिंपिक में तीन खेलों में हिस्सा लिया था, लेकिन आपने तो सिर्फ एक स्वर्ण पदक विजेता वाली कहानी ही दिखाई...

- जब भी आप किसी सत्य घटना पर आधारित कहानी उठाते हैं तो आपको तय करना पड़ता है कि क्या आगे ले जाए और क्या छोड़ दें। एक बड़ी फिल्म का स्क्रीनप्ले अधिकतम 110-120 पृष्ठ का होता है। किसी व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ी हर चीज दिखाने लगेंगे तो फिल्म में एक संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मुरलीकांत पेटकर की जिंदगी में इतनी सारी चीजें हैं कि हमने तो बस थोड़ा सा ही हिस्सा दिखाया है। कहानी की मांग के हिसाब से हमने जितना दिखाने का तय किया था बस उतना ही दिखाया है। वैसे मुरलीकांत पेटकर पर तो अच्छी सीरीज बन सकती है।

● बायोपिक फिल्मों में सिनेमाई लिबर्टी बहुत ली जाती हैं, ऐसे में फिल्मों को प्रामाणिक दस्तावेजों की तरह कितना देखा जा सकता है...

- अगर मुरलीकांत पेटकर के जीवन पर कोई संकलित दस्तावेज है, वो है हमारी फिल्म चंदू चैंपियन। भविष्य में अगर कोई पैरालिंपियन पर रिसर्च करना चाहेगा तो पहला नाम हमारी फिल्म का आएगा, क्योंकि इसमें प्रामाणिकता की कोई कमी नहीं है। मैं जब भी किसी सत्य घटना पर आधारित फिल्म बनाता हूं, तो बहुत रिसर्च करता हूं। इसके अलावा अगर किसी को 1983 के क्रिकेट विश्वकप पर रिसर्च करनी है तो मेरी फिल्म 83 एक प्रामाणिक दस्तावेज है। मेरी वेब सीरीज द फारगाटेन आर्मी, आजाद हिंद फौज पर रिसर्च के लिए प्रामाणिक दस्तावेज है और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में भी इसे मान्यता दी गई है।

● 7.83 और चंदू चैंपियन के बाद क्या अगली फिल्म भी किसी स्पोर्ट्स ड्रामा पृष्ठभूमि पर होगी?

- मैं ऐसे नहीं तय करता कि इसी पृष्ठभूमि पर बनानी है या कुछ अलग करना है। अंतिम निर्णय कहानी पर निर्भर करता है। अगली जो कहानी मुझे उत्साहित करती है मैं उस पर काम करूंगा। दो-तीन कहानियां हैं, जिन पर हम पहले से ही काम कर रहे हैं। (**दीपेश पांडेय**)

जूही की सास ने कैंसल कर दिए थे शादी के निमंत्रण

यूं तो अक्सर सास-बहू के झगड़ों का ही नजारा देखने को मिलता है। टीवी धारावाहिकों में सास-बहू के झगड़े ही अक्सर में दिखाए जाते हैं। लेकिन एक रियल लाइफ की सास-बहू हैं, जिनके बीच बेहद प्यार रहा है। अभिनेत्री जूही चावला, जब जीवन के कठिन समय से गुजर रही थी, तब उनकी सास ने जो उनके लिए किया, वह जूही के जेहन में रह गया। शादी के दौरान का एक किस्सा बताते हुए जूही एक साक्षात्कार के दौरान बताती हैं कि मेरी शादी के दौरान मैं करियर की कुछ बड़ी फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। मेरी मां को गुजरे हुए साल भर पूरा हुआ था। जब शादी की तारीख पास आने लगी, तो अजीब से ख्याल आने लग थे। मैं सोचने लगी थी कि जिसे मुझे सबसे ज्यादा प्यार था मेरी मां, वो चली गई हैं। अब मेरा करियर भी खत्म हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी शादी को लेकर खुश रहूं। एक दिन भावनाओं का बांध टूट गया। मैंने अपनी होने वाली सास से यह बातें बताईं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। सब ठीक है। उन्होंने पूरे परिवार को मनाया कि हम भव्य शादी नहीं करेंगे। मेरी और जय की शादी घर में ही हुई। हमारी शादी में परिवार से करीबी सदस्य और कुछ खास दोस्त ही शामिल हुए थे। कुल मिलाकर 80-90 लोग ही थे।

डिजिटल प्लेटफार्म के शो हश हश में नजर आई थीं जूही। फाइल

ढाई सौ दिनों के शेड्यूल में पूरी होगी लव एंड वार की शूटिंग

वेब सीरीज हीरामंडी के बाद फिल्ममेकर संजय लीला अपनी अगली फिल्म लव एंड वार के प्री प्रोडक्शन में व्यस्त हैं। हालांकि यह फिल्म पीरियड ड्रामा नहीं होगी। रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट अभिनीत इस फिल्म के लिए संजय को जीयो स्टूडियोज का साथ मिल चुका है। फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार फिल्म में कई भव्य दृश्य होंगे। रोमांस के साथ ही म्यूजिक, ड्रामा, एक्शन और इमोशंस में कोई कमी नहीं की जाएगी। संजय ने पिछले कुछ महीनों में फिल्म के संगीत पर काम कर लिया है। इसके साथ ही विक्की, रणबीर और आलिया के साथ कुछ स्क्रिप्ट रीडिंग सत्र भी खत्म कर लिए हैं। संजय इस फिल्म के जरिये पीरियड ड्रामा से ब्रेक ले रहे हैं। पहले उनकी योजना रणबीर के साथ एक छोटा सा शेड्यूल शूट करने की थी। फिर तय किया गया कि तीनों कलाकारों के साथ फिल्म की शूटिंग इस साल नवंबर से आरंभ की जाएगी। लगभग ढाई सौ दिनों के शेड्यूल के लिए तीनों ही कलाकारों ने अपनी डेट्स संजय को दी हैं। अगले साल अगस्त तक फिल्म की शूटिंग पूरी करने की योजना है और फिल्म को क्रिसमस के मौके पर रिलीज किया जाएगा। आलिया फिलहाल यशराज स्टूडियोज के जासूसी यूनिवर्स की फिल्म में व्यस्त हैं। वहीं रणबीर रामायण : पार्ट 1 की शूटिंग और विक्की छावा फिल्म का पैचवर्क खत्म करने में लगे हैं।

फिर रणबीर संग फिल्म में दिखेंगी आलिया ● मिडडे आर्काइव

****